हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

11 मार्च, 2008

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

मंगलवार, 11 मार्च, 2008

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
सदस्य का नाम लेना	(3)15
वाक-आऊट	(3)15
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(3)16
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)25
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)32
सदन की मर्यादा तथा गरिमा को बनाए रखने संबंधी अध्यक्ष महोदय का अवलोकन	(3)33
अनुपस्थिति की अनुमति	(3)34
अनुपस्थिति की सूचना	(3)34
सदस्य का नाम लेना	(3)35
वाक-आऊट	(3)36
इंडियन नेशनल लोक दल के सदस्यों के दुराचरण तथा अनुत्तरदायी व्यवहार की निन्दा करना	(3)36
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(3)43
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)44

मूल्य : 68

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 11 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 09.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 848

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राम कुमार गौतम सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Construction of Roads by HSAMB

***889. Dr. Sushil Indora :** Will the Agriculture Minister be pleased to state the number of roads constructed in the state by the Haryana State Agricultural Marketing Board during the last three financial years ; togetherwith the total amount incurred on the construction of such roads during the said period ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir, the Haryana State Agricultural Marketing Board has constructed 461 roads during the last three financial years and Rs. 7860.76 lacs have been incurred on the construction of these roads during the said period.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष जी, जब भी कोई सरकार बनती है और जब उसके मुख्यमंत्री बनते हैं तो समान विकास की बात प्रदेश में करते हैं। सड़कों का निर्माण भी विकास की उसी धुरी में आता है जिससे पता चलता है कि विकास के काम हो रहे हैं।

सरदार एच० एस० चट्ठा : स्पीकर सर, मेरा इनसे निवेदन है कि ये स्टेटवे क्वैश्चन करें तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। इनको कथा नहीं कहनी चाहिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष जी, चूंकि सिरसा मेरी पार्लियामैंट्री कांस्टीच्यूएंसी रही है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। रोहतक पार्लियामैंट्री कांस्टीच्यूएंसी से मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में सिरसा पार्लियामैंट्री

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
कांस्टीच्यूएंसी में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ है और रोहतक पार्लियामैंट्री कांस्टीच्यूएंसी में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ है।

Mr. Speaker : It is very difficult to give answer, therefore, you may divide your supplementary in two-three parts. आप इसे ए०बी०सी० पार्ट में तबदील करके पूछ सकते हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस इस बात को सामने लाना चाहता हूं और यह देखना चाहता हूं कि प्रदेश में समान विकास के कार्य हो रहे हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो तभी आएगा जब आप प्रश्न का ए०बी०सी० पार्ट करके कुछ पूछोगे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी तैयारी करके आए हैं या नहीं आए हैं that is not the question, जवाब देते हैं या नहीं that is not the question. मैंने उनसे यह जानना चाहा है कि पिछले तीन वर्षों में सिरसा पार्लियामैंट्री कांस्टीच्यूएंसी में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ है और रोहतक पार्लियामैंट्री कांस्टीच्यूएंसी में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ है।

Mr. Speaker : Indora ji, please put your specific supplementary.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष जी, मैं यह देखना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में समान विकास कार्य हुए हैं या नहीं। कहीं पर कोई डिसपैरिटी की गयी हैं या नहीं।

सरदार एच० एस० चट्ठा : स्पीकर सर, इन्होंने अपने मेन सवाल में यह नहीं पूछा है कि पार्लियामैंट्रीवाइज सड़कें कितनी बनी हैं और कितनी नहीं बनी हैं इसलिए मेरे लिए इस समय यह बताना मुश्किल होगा कि किस पार्लियामैंट्री हल्के के किस-किस गांव में किस समय में कितनी सड़कें बनी हैं। लेकिन मैं इनकी और हाऊस की जानकारी के लिए सी०एम० साहब की निष्पक्षता के बारे में बताना चाहता हूं। मैं इनकी ऐलनाबाद कांस्टीचयूएंसी के बारे में बता देता हूं। इनकी कांस्टीच्यूएंसी में 20 रोडज कम्पलीट हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, क्या आपको पार्लियामैंट का इलैक्शन लड़ना है?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष जी, मैं उस सिरसा कांस्टीच्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं इसलिए मैं इस बारे में पूछ रहा हूं।

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर साहब, मैं हल्केवाइज जितनी सड़कें बनी हैं उसको कम्परेटिव रूप से बता देता हूं। सारे जिलों में से सबसे ज्यादा इनके यहां सड़कें बनी हैं। सी०एम० साहब और मैंने इनके हल्के का ज्यादा ख्याल रखा है क्योंकि ये डॉक्टर हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम उसके लिए इनका धन्यवाद करेंगे।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, असली बात यह है कि जैसा

मंत्री जी ने कहा कि चूंकि डॉक्टर साहब मंत्री जी के चहेते हैं इसलिए वे इनका ज्यादा ख्याल रखते हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जबाव दे दिया और मैं उनके जबाव से संतुष्ट हो गया हूं फिर सुरजेवाला साहब क्यों बीच में उठकर ऐसी बात कर रहे हैं।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या रादौर हल्के में मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से कोई नयी सड़क बनाने का प्रस्ताव है? स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के में पलाका से मंसूरपुर तक सड़क बनाने के लिए पिछले तीन साल से प्रयासरत हूं लेकिन आज तक भी वह सड़क नहीं बनी है।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी सरकार के समय यह क्यों नहीं बनवायी?

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर साहब, हमारी सरकार के समय वह सड़क मंजूर हो गयी थी।

श्री अध्यक्ष : पलाका जी, आपकी बात आ गई है। अब मंत्री महोदय को जबाव देने दें।

सरदार एच० एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, पलाका साहब, हल्के के हिसाब से भी मेरे ग्वांडी हैं और इनका घर भी मेरे घर के साथ है लेकिन इन्होंने मेरे यहां आने की कभी तकलीफ नहीं की है। ये मेरे यहां आएं, चाय भी पीयें और सड़कों के बारे में भी बताएं, इनका कोई काम रुकेगा नहीं।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के मंडी डबवाली के अंदर पिछले तीन साल में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा कितना पैसा खर्च किया गया है, क्या कोई नयी सड़क भी मंजूर की गई है?

Sardar H.S. Chatha : Mr. Speaker Sir, at this time it is not possible to give reply of this query. Hon'ble Member can ask separate question in this regard.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी पूछा था लेकिन आज तक नैगेटिव में ही जवाब आया है।

श्री अध्यक्ष : आपने एक सवाल पूछा और Hon'ble Minister has said that you can ask separate question in this regard. It is not possible for the Hon'ble Minister to give reply of every question.

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे तावडू हल्के में एक भी सड़क की मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से रिपेयर नहीं की गई है। मेरा खुद का गांव भी उसमें शामिल है वहां सड़क की रिपेयर ही नहीं हुई है, नयी सड़क की तो बात ही बहुत बड़ी है। सिकरावे से अलावलपुर तक की सड़क ऐसी हालत में है कि लोग खेत में से होकर चलना पसंद करते हैं लेकिन सड़क पर चलना पसंद नहीं करते हैं। शिकारपुर से तावडू सड़क की हालत भी खराब है और बणैणी रोड से पालावास तक भी सड़क की हालत खराब है। इसी तरह से 20 सड़कें ऐसी हैं जिन पर अब तक एक पैच भी नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में मंत्री जी के पास लिखकर भिजवा देना।

श्री साहिदा खान : मैं लिखकर दे चुका हूं।

सरदार एच० एस० चट्ठा : सर, मेरे पास अभी तक लिखकर नहीं आया है। डिपार्टमैंट की तरफ से यह पूरी कोशिश रहती है कि जो सड़कें 5 साल से पुरानी बनी हुई हैं उनकी पहले रिपेयर की जाए। आप आज ही लिखकर भिजवा दें तो आज से ही प्रौसेस शुरू हो जाएगा।

श्री साहिदा खान : मैं हाउस में इस बारे में तीन बार कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : बात हो गई है, आप लिखकर भिजवा दें।

Prime Minister Scholarship Scheme

*805. **Dr. Sita Ram :** Will the Education Minister be pleased to state the details of the Prime Minister Scholarship Scheme togetherwith the criteria for Scholarship and the benefits thereof for the students ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : स्पीकर सर, "प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति स्कीम" के नाम से शिक्षा विभाग में कोई भी स्कीम नहीं चलाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं सदस्य की और माननीय सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक "स्कॉलरशिप फार ऐक्सीलैंसी इन ऐजुकेशन" नामक स्कीम मिडिल, उच्च और वरिष्ठ विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है। उक्त स्कीम 2005-06 के दौरान प्रारंभ की गई थी इस स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले एवं परीक्षा में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के तौर पर नकद राशि दी जाती है। इस हेतु कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक विद्यालय के एक छात्र को और एक छात्रा को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को और छात्राओं को यह राशि 750 रुपये प्रति मास के हिसाब से व मिडिल कक्षा से ऊपर के छात्रों को 1 हजार रुपये पर मंथ के हिसाब से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जवाब दिया गया है कि इस तरह की कोई छात्रवृत्ति स्कीम ऐजुकेशन डिपार्टमैंट की तरफ से लागू नहीं है। अब इन्होंने इस बारे में यहां पर यह जवाब दिया है। मैं चाहूंगा कि मेरे पास यह जवाब लिखित में भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष : यह प्रोसीडिंग में आ जाएगा और आपके पास लिखित में करैक्शन के लिए आएगा। जो कहा है उस हिसाब से आपके पास आ जाएगा।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी दे दी है। अगर फिर भी ये लिखित रूप में जानकारी लेना चाहते हैं तो इनको लिखित रूप में जानकारी भिजवा देंगे।

Construction of By-Pass of Narnaul City

***814. Sh. Radhey Shyam Sharma :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any porposal under consideration of the Government to construct a by-pass for Narnaul City ; if so, the time by which the work is likely to be started thereon ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Yes, Sir. A Consultant has been appointed to examine feasibility of the by-pass. Decision regarding construction of by-pass will be taken after examining the feasibility report.

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, जो यह कन्सलटैण्ट एप्वांट किया गया है इसके लिए तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। लेकिन मंत्री जी यह बतायें कि अगर कन्सलटैण्ट अपनी समय पर रिपोर्ट दे देता है तो इस बाई-पास का काम कब तक शुरू करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल आ गया है अब आप बैठ जाइये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो नारनौल का बाई-पास है इसको बनाने की बड़ी भारी जरूरत है। यह बात मैं भी मानता हूं। इस को बनाने में लगभग 20 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत आयेगी। इस बाई-पास को बनाने के लिए सरकार ने मैसर्ज स्कॉटविलसन इण्डिया लिमिटेड नामक कम्पनी को प्रोजैक्ट रिपोर्ट दी है और हमें उम्मीद है कि उसकी रिपोर्ट हमें 3-4 महीने में मिल जायेगी। यह प्रोपोज्ड बाई-पास नारनौल-निजामपुर चौक से लेकर नारनौल-महेन्द्रगढ़-दादरी रोड तक 11.20 किलामीटर है तथा नारनौल, वाया नांगल चौधरी, बुडवाल, कोटपुतली रोड 3.80 किलोमीटर है। उसके बाद नारनौल, वाया रामबास रोड, नारनौल-कुलतारपुर रोड, नारनौल सिंघाना रोड से होते हुए महेन्द्रगढ़-नारनौल रोड पर नांगल तिहाड़ी पर जाकर मिलेगा जिसकी लैंथ कुल 8 किलोमीटर होगी। इसकी लैंड एक्विजीशन को लगाकर तकरीबन 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दूसरी जो हमारी यह रिपोर्ट आ जायेगी तो उसके बाद हम बाकी की कार्यवाही शुरू करेंगे।

श्री अरजन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के गांव में बुढ़िया खदरी देवघर रोड है जिसे बी०के०डी० रोड कहते हैं जो 24 किलोमीटर का टुकड़ा है उसको मंत्री जी कब तक पूरा करवा देंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस टुकड़े को हम जरूर रिपेयर करवायेंगे।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, नारनौल को बाई-पास बनाने के बारे में मंत्री जी ने यह कहा कि कन्सलैटैंट की रिपोर्ट 3-4 महीने में आ जायेगी। क्या मंत्री जी बाई-पास को जोड़ने वाली बाकी की सड़कों को जैसे सेका मंडाना रोड, नौनी हबल वाली रोड, चाहे नांगल चौधरी रोड चारों तरफ की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, को भी तभी ठीक करवाने का काम शुरू करेंगे।

Mr. Speaker : It is not possible.

कैप्टन अजय सिंह यादव : जहां तक बजट का सवाल है 4 करोड़ 53 लाख रूपये नारनौल कान्सटीच्यूंसी को अलॉट हुए हैं। इसके अन्दर माननीय सदस्य के गांव भी बीच में ही आते हैं। मैं समझता हूं कि यह जो कुछ सड़कों पर काम चल रहा है एक तो जो राधेश्याम जी के हल्के निजामपुर से नारनौल की सड़क पर एक करोड़ दो लाख रुपये एप्रूव हुए हैं। इसलिए राजस्थान बोर्डर पर लगने वाली सड़क को जल्दी ही रिपेयर किया जायेगा। दूसरा नयागांव बायल वाली रोड़ पर वर्क-इन-प्रोग्रैस है और इस पर तकरीबन दो करोड़ 59 लाख रुपये नाबार्ड की स्कीम के तहत खर्च किये जायेंगे। एक हमने एस०पी० के तहत काम लिया हुआ है। इनकी कान्सटीच्यूंसी के लिए दो करोड़ 50 लाख रुपये का कार्य अब तक हो चुका है। बाकी और भी जो सड़कें होंगी उनकी हम रिपेयर करवाएंगे। पिछले दिनों मैं नरेश जी के हल्के में गया था, इनके हल्के में मैं समझता हूं कि पिछले 5 सालों के आंकड़े देखें और अब के आंकड़े देखें तो इनके यहां की सड़कों पर काफी काम हुआ है। नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नरेश जी के हल्के में कई सड़कों के काम की शुरूआत की गई है। बाकी जो बची हुई सड़कें हैं उनको भी ठीक करवाएंगें।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हमारे यहां के ग्रिवैंसिज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और वे हमारे यहां बाई रोड गए हैं, मेवात का एक रोड भी ऐसा नहीं है जिस पर आदमी आसानी से चल सकता हो। हमारे रास्ते में एक कुलवाडी गांव पड़ता है, मंत्री जी इस गांव में एक प्रोग्राम के लिए गए थे तो लोगों ने पर्सनली डिमांड रखी थी कि जहां से गुड़गांव खत्म होता है और मेवात जहां से शुरू होता है वहां आदमी सड़कों पर चलने में बहुत परेशानी उठाता है। बिलासपुर से होडल जाना होता है तो कम से कम 4-5 घण्टे लग जाते हैं, 50 किलोमीटर जाने के लिए 5 घण्टे लग जाते हैं। सड़कों की इतनी बुरी हालत है। आपकी सरकार का एक आदमी ऐसा है जिसने डम्परों से 32-32 टन वजन लोड करके सारी सड़कें तोड़ दी हैं। जब भी मुख्यमंत्री महोदय वहां जाते हैं तो वे हैलीकोप्टर से जाते हैं लेकिन कैप्टन साहब हमेशा बाई-रोड गए हैं तो उनको तो मेवात के बारे में पूरी जानकारी है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि मेवात में काम नहीं होते।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों एन०सी०आर० के तहत 588 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। (विघ्न) गुड़गांव, नूंह अलवर रोड, राजस्थान बार्डर तक करीबन 348 करोड़ रुपए सड़कों के लिए मंजूर हुए हैं और इसके लिए जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। होडल, नूंह, पटौदी-पटौदा रोड के लिए करीबन 240 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं। इसके अलावा 25.75 करोड़ रुपए से ओल्ड गुड़गांव-अलवर रोड-नूंह टाउन तक पिनुवा, शिकरवा रोड, सोनपुर, कौल गांव, धोवा और कुछ महत्वपूर्ण सड़कों पर काम कर रहे हैं और लिंक रोड पर भी इम्प्रूवमैंट कर रहे हैं जिसके लिए 6 करोड़ रुपए खर्च करेंगे जिसके लिए टैण्डर्ज रिसीव हो गए हैं और इस पर जल्दी ही काम शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें मेवात की सड़कों की हालत के बारे में पता नहीं है। इसके अलावा नूंह पलवल रोड पर साढ़े 7 करोड़ रुपए के काम के लिए टैण्डर्ज रिसीव हो गए हैं और जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 53.86 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं और यह जरूरी भी है क्योंकि मेवात की सड़कों की हालत बहुत खराब थी। लेकिन हमारा फिलहाल

जो फाइनैंशियल इयर है उसमें हम काफी एरियाज में काम करेंगे (विघ्न)।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ से हिसार, रोहतक और जींद जाने के लिए अम्बाला शहर से होकर जाना पड़ता है और उस सड़क पर काफी जाम लगा रहता है और उस सड़क पर रोज हादसे भी होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अम्बाला शहर में बाई-पास बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है और अगर विचाराधीन है तो यह बाई-पास कब तक बनाया जाएगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि अम्बाला में 4 लेनिंग का काम चल रहा है और अम्बाला में पुल का काम भी चल रहा है। फिर भी हम माननीय साथी की बात को एग्जामिन करके कंसल्टैंट अप्वायंट कर देंगे।

Financial aid given by the NABARD to reclaim Water Logged Land of the State

***826. Sh. Ranbir Singh Mahendra :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether any financial aid is being given by the NABARD to reclaim the water logged land of the State ;

(b) if so, the amount of the financial aid being given togetherwith the names of the places where the said amount is being spent ; and

(c) whether any project has been prepared by the Drainage Department in this regard ; if so, the details thereof ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, a statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. Financial aid is being given to NABARD in the shape of refundable loans and not as grant for execution of new drainage schemes to prevent water logging in the area.

(b) Sir, few schemes namely Sullar Drain, Hissar Ghaggar Multipurpose Channel, Bass and Hansi Multipurpose Channel, Rangoi Khariff, Channel, Bhiwani Ghaggar Drain, Mithathal Ghuskani Link Drain are being executed with NABARD Financing. Total approved cost of these schemes is Rs. 203.20 Crores against which NABARD share is Rs. 158.31 Crores. These schemes are being executed in Ambala, Hisar, Fatehabad, Sirsa, Kaithal and Bhiwani districts. An expenditure

[Capt. Ajay Singh Yadav]

of Rs. 170.20 Crores has been incurred against these schemes so far. A list showing details of schemes is also enclosed.

(c) Sir, few schemes amounting to Rs. 18.93 Crores have been executed as ditch/seepage drains by Irrigation Department, Haryana during the year 2004-2007. CADA has prepared a Pilot Project (under WJC - VI) for bio-drainage under which 1000 hectares of water logged area will be reclaimed in Rohtak District for which Government of India has agreed to give 50% funds at the rate of Rs. 15000/- per hectare (Total Rs. 1.5 cr). In this project, cloned variety of Eucalyptus will be used to facilitate bio-drainage. It is further proposed to take up 1000 hectare per year till 2019-2020 under bio-drainage scheme by CADA, Haryana in water logged areas of Rohtak, Jhajjar, Sonepat, Jind, Panipat & Bhiwani districts of Haryana State.

List of Schemes for prevention of water logging.

(Rs. in lacs)

S. No.	Name of Scheme	Total Sanctioned Cost	NABARD Share	Expenditure	District	Upto date Progress
1	2	3	4	5	6	7
1.	Excavation on Sullar Drain from RD 0-20100 off taking from village Sullar and outfalling in SYL Parallel drain at RD 28431.	118.98	84.48	106.63	Ambala	Completed
2.	Constructing Hisar Ghaggar Multipurpose Channel from RD 0-398600	8813.59	6696.87	6809.88	Hisar Fatehabad, Sirsa	98%
3.	Constructing Bass Multipurpose Channel from RD 0-155580 and Hansi Multipurpose Channel from RD 0-38320	4229.11	3008.61	4179.7	Hisar, Kaithal	96%
4.	Excavation of Rangoi Kharif Channel from RD 0-278000 outfalling at RD 24500, Darba Ghaggar Drain and linking with river Ghaggar.	3548.37	2611.05	3680.98	Sirsa, Faridabad	Completed

1	2	3	4	5	6	7
5.	Constg. Bhiwani Ghaggar Drain from RD 0-166200 outfalling at RD 384000/L Hisar Multipurpose Channel.	2760.96	2622.92	1751.66 (on land Acquisition)	Bhiwani	5%
6.	Constg. Mithathal Ghuskani Link Drain from RD 0-53350 outfalling at RD 28345/R Bhiwani Ghaggar Drain	849.09	806.63	491.36 (On Land Acquisition)	Bhiwani	Work likely to be started shortly
	Total	20320.10	15830.56	14777.19		

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मिथाथल घुसकनी सम्पर्क ड्रेन में कौन-कौन से गांव शामिल हैं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि मिताथल घुसकानी लिंक ड्रेन में ज्यादातर गांव भिवानी जिले के आयेंगे। इस लिंक ड्रेन पर 203 करोड़ रुपए की लागत आयेगी जिसमें से 158 करोड़ रुपए नाबार्ड का हिस्सा है। जहां तक माननीय साथी ने गांवों के बारे में पूछा है कि इसमें कौन-कौन से गांव आयेंगे इस बारे में मैं मेरे माननीय साथी को अभी नहीं बता सकता। केवल यही बता सकता हूं कि इस ड्रेन में ज्यादातर गांव मुंढाल और भिवानी हल्के के ही आयेंगे। इसके अतिरिक्त भिवानी जिले में भिवानी घग्गर ड्रेन भी सेम की समस्या दूर करने के लिए बनाई जा रही है। इसकी टोटल सैंग्शंड कोस्ट 2760 लाख रुपए है जिसमें 2662 लाख रुपए नाबार्ड का हिस्सा है। इसकी लैंड एक्वीजेशन पर 1751 लाख रुपए लगेंगे। इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी 100 क्यूसिक होगी और इसकी लैंथ 50.5 कि०मी० होगी तथा यह ड्रेन 30.6.2009 तक बनकर तैयार हो जायेगी।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने गांवों की जानकारी तो नहीं दी कि मिताथल घुसकानी ड्रेन में कौन-कौन से गांव शामिल होंगे लेकिन हल्कों के नाम बतायें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इस ड्रेन में घुसकानी, मिताथल, तिगड़ाना, मण्डाणा तक के गांव आएंगे। मण्डाणा, लुहारी जाटू और उसके बाद के जो गांव हैं मुंढाल खुर्द, मुंढाल कलां, बडेसरा, जटाई, सुखपुरा, धनाना आदि गांव इस ड्रेन में नहीं आयेंगे। इसके अतिरिक्त चांग से बवानीखेड़ा, बामला आदि गांव भी इस ड्रेन की रेंज में नहीं आयेंगे। इन गांवों को भी मंत्री जी स्टडी करवा लें। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मिरान, सागबन आदि गांवों में सेम की सबसे ज्यादा समस्या है इन गांवों के लिए भी मंत्री जी कोई न कोई योजना अवश्य बनायें और जल्दी से जल्दी उस पर काम शुरू करवायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जिन गांवों का जिक्र माननीय साथी ने किया है उनको हम एग्जामिन

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
करवा लेंगे। मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि मिताथल घुसकानी लिंक ड्रेन से सबसे ज्यादा लाभ मुंढाल हल्के के गांवों को मिलेगा। यह ड्रेन घुसकानी, तिगड़ाना, राजपुरा और खापोड़ा गांवों में होती हुई भिवानी-घग्गर ड्रेन में जाकर मिल जायेगी और यह ड्रेन मुंढाल हल्के के गांवों की सेम की समस्या दूर करेगी। मैं माननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम इस ड्रेन की 2008-09 में एक्सटैंशन करवा रहे हैं from RD 50100 to 60630 including construction of Prem Nagar Drain, extension Gujrali Drain and extension of Dhanana drain outflow falling in Ghuskanin linked drain. हो सकता है उसमें वे गांव कवर हो जायें जिनका जिक्र अभी माननीय साथी ने किया है। अगर ये गांव इसमें कवर नहीं होंगे तो उनको एग्जामिन करवाकर हम जरूर करेंगे और उनकी सेम की समस्या दूर करेंगे।

डॉ० शिवशंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि भिवानी घग्गर ड्रेन भी मिताथल-घुसकानी लिंक ड्रेन के साथ लिंक होने वाली है और मेरे नोटिस में यह आया है कि इसके लिए 30 करोड़ रुपए भी सैंक्शन हो चुके हैं लेकिन इस पर अभी तक भी काम शुरू नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि एक और ड्रेन भी प्रस्तावित थी जो हुड्डा ने बनानी है क्योंकि हुड्डा के भिवानी शहर में 13, 21, 23 और 26 सैक्टर हैं लेकिन डिस्पोज़ल कोई नहीं है। यह भी मेरे नोटिस में आया था कि इस तरह का एक डिस्पोजल बनाकर उसको भी ड्रेन से जोड़ा जायेगा लेकिन उस पर भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कब तक यह काम पूरा हो जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो भिवानी-घग्गर ड्रेन है इसका तकरीबन 5 प्रतिशत काम शुरू हुआ है और मैं समझता हूं कि इसका लैंड एक्वीजिशन का काम अभी पैंडिंग है। लैंड एक्वीजीशन के लिए इरीगेशन डिपार्टमैंट ने पैसा दे दिया है लेकिन उसका अवार्ड नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि वहां पर डी०आर०ओ० नहीं है और उसकी वजह से ही हमने डी०आर०ओ०, रेवाड़ी को यह ड्यूटी दी है। इसमें 175 करोड़ रुपए तो हमें लैंड एक्वीजिशन के पे करने हैं और जो मिताथल-घुसकानी लिंक ड्रेन है इसके ऊपर भी अभी लैंड एक्वीजीशन का कार्य हो रहा है। इसमें 49 करोड़ रुपए हमें देने हैं और इस पर तभी काम शुरू होगा जब इसका लैंड एक्वीजीशन का काम पूरा हो जायेगा। लेकिन वह अवार्ड होना बाकी है। हमने पैसा जमा करवा दिया है जैसे ही यह लैंड एक्वीजीशन का काम पूरा हो जायेगा उस पर काम शुरू हो जायेगा। मैं सम्बन्धित मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे डी०आर०ओ० की पोस्टिंग जल्दी कर दें ताकि इसका अवार्ड जल्दी हो जाये।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह और करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी भिवानी ड्रेन का जिक्र किया यह हालुवास, दिनौंद, खापौड़ा होते हुए हिसार की तरफ निकलेगी और जो मिताथल-घुसकानी लिंक ड्रेन है इसमें रेवाड़ीखेड़ा और सय और मिला दिये जायें। इसको अगर ये एग्जामिन करवायें तो बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक मुंढाल कलां, मण्ढ़ाल खुर्द, बडेसरा और जतई का सम्बन्ध है इनको आगे जाकर

भिवानी-घग्गर ड्रेन से मिलाने के लिए दूसरी ड्रेन आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि मिताथल-धुसकानी लिंक ड्रेन से यह पानी नहीं जा पायेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इन्होंने जो प्वायंट्स रेज किए हैं इनको हम एग्जामिन करवा लेंगे और एग्जामिन करवाकर जो भी फिजीबिलटी होगी उसके मुताबिक हम अपने अधिकारियों को आदेश दे देंगे।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के डबवाली के अन्दर दो गांव हैं एक लोहगढ़ और दूसरा जोतावाली इनके अन्दर सेम की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ओ०एस०डी० डॉ० के०वी० सिंह ने भी वहां पर दौरा किया था उन्होंने वहां आश्वासन दिया था कि इस सेम की समस्या से जल्दी ही निजात मिल जायेगी तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस सेम की समस्या को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास हुए हैं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा वे इस बारे में मुझे अलग से लिखकर दें तभी मैं इनको प्रॉपर जवाब दे सकूंगा।

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल वहां से निकलती हैं उसकी सीपेज की वजह से वहां पर सेम की समस्या पैदा हो गई है।

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हांसी-बुटाना सम्पर्क नहर का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा क्योंकि माननीय साथी के हल्के में सेम की समस्या है और हमारे यहां वाटर लैवल नीचे जा रहा है जिसकी वजह से हमारे यहां सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। स्पीकर सर, हांसी-बुटाना नहर के चालू हो जाने से दोनों समस्यायें अपने आप हल हो जायेंगी।

10.00 बजे

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, इनको शायद ज्ञान नहीं है। मैंने जो प्रश्न पूछा है वह राजस्थान कैनाल की वजह से है। कुछ गांव वहां पर नीचे हैं इसलिए यह सेम की समस्या है। इनको पता नहीं आपने क्या इंजैक्शन लगा दिया कि इन्होंने दक्षिण हरियाणा का जिक्र करना ही बंद कर दिया।

श्री अध्यक्ष : क्या इस प्रकार का कोई इंजैक्शन लगता है और क्या आपको भी इस प्रकार का इंजैक्शन लगा हुआ है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो बात श्री नरेश यादव जी ने उठाई है यह वास्तव में वाजिब है। सिरसा के इलाके में सेम की बड़ी भारी समस्या है और जैसा मैंने बताया कि उस पानी को ड्रेन किया जाये। करोड़ों, अरबों रुपए इस समस्या से निदान पाने के लिए हमारी सरकार खर्च कर रही है। अपने शेयर से ज्यादा पानी लेने की इनकी आदत बनी हुई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि जब हाँसी-बुटाना लिंक नहर बनकर तैयार हो जायेगी और पानी का समान बंटवारा हो जायेगा तो इनकी समस्या अपने आप दूर हो जायेगी। इस पर 350 करोड़ रुपए का खर्च आयेगा और 98 परसैंट उसका काम पूरा हो चुका है लेकिन कुछ लोग खुराफाती करते रहते हैं। हमारे कुछ साथी इनकी शह पर हाईकोर्ट में चले गये, वहां से उस पर स्टे ले आये और जब वह स्टे टूट गया तो अब

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
सुप्रीम कोर्ट में चले गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ये गलत कह रहे हैं। यह अनपार्लियामैंटरी लैंग्वेज है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या ये आपको कह रहे है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सर, जब प्रश्न हमने पूछा है तो हमें ही कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप खुराफाती शब्द को डिफाईन कीजिए, आप एक्सप्लेन कीजिए।

डॉ० सीता राम : सर, आप ही बताइये क्या यह पार्लियामैंटरी वर्ड है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कल आपने बी०एस०पी० के विधायक के साथ जो किया क्या वह खुराफाती नहीं था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : सर, यह सब आप जानबूझ कर करवा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठिए। Take your seat. I say sit down. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अरजन सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये मेरे साथ हाथापाई कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : आपका 9 आदमियों का ग्रुप है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी अकेले आदमी के साथ ऐसा करेंगे। यहाँ पर 67 आदमियों का ग्रुप भी है। My duty is to protect the each and every member. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सर, यह सब जानबूझ कर करवाया जा रहा है। आप अपना कर्त्तव्य ठीक से नहीं निभा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जानबूझ कर कुछ नहीं हो रहा है। आप अपनी सीट पर बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) I am performing my duty.

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल चल रहा है। इनको न तो संसदीय प्रणाली की जानकारी है, न ही समझ है। इनके नेता ने पहले से ही इनको तैयार करके भेजा है। बिजली और पानी के इतने अहम् प्रश्न पूछे जा रहे हैं लेकिन ये जानबूझ कर इनको सुनना नहीं चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे हाउस नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. प्रश्नकाल चल रहा है (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, **********।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री साहिदा खान : ********** ।

Mr. Speaker : Please sit down. Please sit down. Mr. Sahida, I am on my legs.

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, ********** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब तक पूछे गये 20 सप्लीमैंटरी में से 16 आपने पूछे हैं। जनता ने तो आपको ओपीजीशन का स्टेटस भी नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नेशनल लोक दल के कई माननीय सदस्यगण अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलते रहे)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इन लोगों का काम हर रोज व्यवस्था भंग करने का रहता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीटों पर बैठें। क्वैश्चन आवर चल रहा है (शोर एवं व्यवधान) डॉ० साहब आप जानते हैं कि क्वैश्चन आवर कितना इम्पोर्टैंट है (शोर एवं व्यवधान)। I will give my ruling after the Questions Hour. Please don't interrupt the Questions Hour. (Interruptions) I will give my ruling during the Zero Hour. (शोर एवं व्यवधान) अभी इतना इम्पोर्टैंट सवाल चल रहा है इसके आगे आपके मैम्बर साहिदा खान जी का सवाल भी लगा हुआ है। आप हाउस में व्यवस्था बनाएं रखें और अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) साहिदा जी का सवाल आ रहा है और इतनी इम्पोर्टैंट सप्लीमैंट्रीज़ चल रही हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी सवाल का रिप्लाई देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द : अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। जो भी ये लोग बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये लोग मन बना कर आये हैं कि इस हाउस की कार्यवाही को नहीं चलने देना है। इन लोगों को चाहिए कि ये लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें और हाउस की कार्यवाही को चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, **********

Mr. Speaker : Don't cry like jackals. (Interruptions)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *********

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. (Interruptions)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब ने जो कहा है वह श्री नरेश जी को कहा है न कि इन लोगों को कहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि इनको यह कहा गया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, **********

Mr. Speaker : You are crying like jackals. Please take your seat.

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, ये लोग बार-बार हाउस की कार्यवाही डिस्टर्ब कर रहे हैं। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *********

Mr. Speaker : Dr. Indora I warn you. (Interruptions)

Dr. Sita Ram : Mr. Speaker Sir, **********

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, I warn you. Please sit down. आपकी जो भी सप्लीमैंट्री बनती है या जब भी कोई सप्लीमैंट्री पूछने के लिए आप लोगों ने हाथ खड़े किये हैं मैंने आपको बोलने का पूरा समय दिया है। अगर आप कोई सप्लीमैंट्री पूछना चाहते हैं तो पूछें। हाउस की एक व्यवस्था होती है आप लोग उस व्यवस्था को बनाए रखें। जितना टाईम आप लोग बोलने के लिए लेना चाहते हैं आपको टाईम दिया जाएगा। (विघ्न)

Mr. Phool Chand Mulana : All the Hon'ble Members are elected. The Hon'ble Minister while replying only said that we are trying to construct the canal but there are certain Khuraphatis. जो कोर्ट में चले जाते हैं। ये आप लोग अपने ऊपर न लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या आपने यह केस कोर्ट में करवा रखा है? यह जो खुरापाती कहा गया है यह आपको नहीं कहा गया है। (शोर एवं व्यवधान) इन्दौरा जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : **********। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : **********। (शोर एवं व्यवधान)

श्री फूल चन्द मुलाना : यह मैंने आपको नहीं कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री नरेश यादव : बादल कोर्ट में गया है। ये बादल को यहां क्यों ला रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह डांगी : कोर्ट में जाने वाले खुरापाती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : जो कोर्ट में गया है वह खुरापाती है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Interruptions) I warn you, Indoraji, third time. It is question hour and it is very important but you are wasting the time of the House unnecessarily without assigning any reasons thereof.

सदस्य का नाम लेना

डॉ० सुशील इन्दौरा : अगर आप मुझे सदन से निकालना चाहते हैं तो मैं लोकतंत्र की हत्या होने के बारे में सदन से वाक-आऊट करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : हम सभी भी लोकतन्त्र की हत्या होने के विरोध में वाक-आऊट कर जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, आपका रवैया हमारे प्रति ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) ********* ।

श्री अध्यक्ष : इनका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। आप किस तरह से बोल रहे हैं। मैं आपको वार्न करता हूं। (शोर एवं व्यवधान) आपकी पार्टी के साथी वाक-आऊट करने की बात कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ जाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको वार्न करता हूं आप इस तरह से विहेव न करें। (शोर एवं व्यवधान) पलाका जी, मैं आपको वार्न करता हूं। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको नेम करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : ********** । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पलाका जी, आपको नेम कर दिया गया है, आप सदन से बाहर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मार्शल इनको सदन से बाहर ले जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward Staff took Sh. Ishwar Singh Plaka out of the House.)

वाक-आऊट

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे एक साथी को नेम किया है, इसके विरोध में हम सदन से वाक आऊट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ॥

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी, आप बाहर जाएं। आपने वाक-आऊट किया है। (शोर एवं व्यवधान) अब आप किस तरह से बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित सभी इण्डियन नेशनल लोकदल के सदस्य बोलते हुए सदन से वाक-आऊट कर गए।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Development of Bidh Kaiyar in Kaithal

***831 Sh. Shamsher Singh Surjewala :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Haryana Government/Kurukshetra Development Board has decided to develop/renovate the Bidh Kaiyar area in Kaithal town ;

(b) if so, the total cost of the project together with details of the works which will be executed on this site ; and

(c) the time by which this project is likely to be completed ?

Urban Development Minister (Sh. A.C. Chaudhry) :

(a) Yes, Sir.

(b) The total estimated cost of the project is Rs. 705.08 lacs. The works envisaged to be executed on the site are as under :—

(i) Making arrangement for stoppage of entry of dirty water and storm water of the town in the lake at a cost of Rs. 273.00 Lacs.

(ii) Laying of underground pipe line for supply of fresh canal water in the lake from Keorak Minor at a cost of Rs. 53.77 Lacs.

(iii) Development of lake which includes its excavation, earth filling, construction of steps and ghats and path, stone pitching, providing of fountain & illumination at a cost of Rs. 378.31 Lacs.

(c) Works mentioned at (i) & (ii) are likely to be completed by 31.10.2008 and work mentioned at (iii) is likely to be completed by 31.3.2009 subject to the availability of funds.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कैथल टाऊन में विद्ध क्यार लेक है और कुरुक्षेत्र का एरिया बहुत ही ऐतिहासिक है जहां पर बहुत ही ऐतिहासिक मन्दिर हैं और ये

मन्दिर महाभारत के समय के हैं। वहां पर बहुत से पूर्वतत्व चिह्न भी हैं जिनकी प्रोटैक्शन बहुत ही जरूरी है। इस बारे में कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड ने और हरियाणा सरकार ने एक ज्वायंट प्रोजैक्ट बनाया हुआ है। इस बोर्ड का शिलान्यास आज से साल-डेढ़ साल पहले महामहिम गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने ज्वायंटली किया था। इसलिए इस बात का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री जी और हैड आफ दि स्टेट गवर्नर साहब की प्रैस्टीज जुड़ी हुई है। चौधरी साहब का यह कहना कि अगर फंड अवेलेबल होंगे तो इस बारे में कुछ किया जाएगा। मैं तो यह कहूंगा कि यह तो will to do की बात है। मेरा इस बारे में यह कहना है कि सरकार इस बारे में कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड से भी कहे कि वे अपने फंडस से यह काम करे। मुख्यमंत्री जी ने और गवर्नर साहब ने जब ज्वाइंटली वहां पर एक पत्थर रखा है तो उसको पूरा करने के लिए फंडज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसी उम्मीद है। दूसरी बात, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पहले फेज में और दूसरे फेज में जो काम शुरू हुए हैं उनके अभी तक कितने कितने परसैंट काम पूरे हुए हैं?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, सरकार इस बात से भलीभांति परिचित है कि कुरुक्षेत्र एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसको भारत देश में प्रायः सभी जातियों के लोग सम्मान की निगाह से देखते हैं। माननीय सदस्य ने जिस स्थान पर एक लेक का जिक्र किया है सौभाग्य से वहां पर मन्दिर और मस्जिद भी है। हमने इस प्रोजैक्ट को माननीय सदस्य के आग्रह पर शुरू करके 705 लाख रुपये इसके ऊपर खर्च करने का फैसला किया है। प्रायः इसके जो दो भाग हैं वह पब्लिक हैल्थ विभाग द्वारा पूरे होने वाले हैं। 31 अक्तूबर तक हम इसको पूरा कर रहे हैं। जहां तक तीसरे भाग का प्रश्न है यह तो हर कोई जानता है कि कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड की आय का अपना कोई साधन नहीं है। पिछली बार भी महामहिम राज्यपाल महोदय ने जब इस बोर्ड की अध्यक्षता की थी तो इसका जिक्र आया था और इसके लिए फंड्ज दिए गए थे। पिछले साल भी हमने इस पर एक करोड़ रुपया लगाया है और दो करोड़ रुपये अभी और इस पर लगने का अंदाजा है। चूंकि कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड के अपने कोई आय के साधन नहीं हैं इसलिए हम इस बारे में सरकार पर आश्रित हैं। मैं आज ही अपने अधिकारियों से कहकर एक और नोट पुट कर दूंगा ताकि और फंड्ज मांगकर इसको पूरा कर दिया जाए। यह तो हमारा धार्मिक कर्तव्य है इसलिए सरकारी जिम्मेवारियों के साथ-साथ दोनों कामों को हम पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि थर्ड फाईनैंस कमीशन में शायद पैसा आ गया है इसलिए इस साल में और अगले साल में पैसा भी उपलब्ध हो जाएगा। चूंकि इसके साथ पूरे कुरुक्षेत्र के इलाके के लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं इसलिए इसमें पैसे की दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। थर्ड फाइनैंस कमीशन से जो पैसा आया है उसमें से पैसा महकमे को एलोकेट करवाना पड़ेगा क्योंकि के०डी०बी०.के पास पैसा नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री बिरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, मैं इसको क्लैरीफाई कर देता हूं। जो डिपार्टमैंटल काम हैं उनके लिए कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड तो एक नोडल एजेंसी है। उसको फंडज एलोकेट कर दिए जाते हैं और फंडज की हमारे पास कोई कमी नहीं है। बात खत्म।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, पिछले सत्र के दौरान भी कलायत कपिल मुनि सरोवर पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, के बारे में एक प्रश्न किया गया था। चूंकि इसका भी निर्माण कार्य कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड के तहत ही चल रहा है और यह 48 कोस की भूमि के अंदर ही आता है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि इसके लिए पहली किश्त तो मिल गयी है इसलिए अब इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है लेकिन जब रि-ऐस्टीमेट्स करके दोबारा से केस भेजा गया तो उसके बाद से अभी तक और पैसा इसका नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछें।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, सरस्वती नदी के बारे में बताया जाता है कि यह पहले लुप्त हो गयी थी लेकिन आजकल वहां पर पानी बहुत तेज प्रवाह से चल रहा है इसलिए काफी लोगों ने वहां पर रिसर्च का काम भी शुरू किया है। चमन ऋषि का जो हमारा मंदिर था उसकी दीवारें भी टूट गयी हैं इसलिए मेरा मंत्री जी से कहना है कि पहली किश्त का तो पैसा वहां पर लग गया है लेकिन पैसे की कमी की वजह से अभी भी काम अधूरा पड़ा है इसलिए इसकी दूसरी किश्त कब तक भेज दी जाएगी ताकि उसका कोई नुकसान न हो?

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर सर, वैसे तो इस प्रश्न का ताल्लुक विद्ध कयार लेक से था लेकिन मेरी बहन ने एक चिंता व्यक्त की है कि कोई काम शुरू होने के साथ रुक गया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल ही मैं कोई न कोई अधिकारी वहां भेजकर पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद जो भी काम हो सकने वाले होंगे और जितने समय के अंदर होने वाले होंगे उसको हम पूरी वचनबद्धता के साथ लिखकर इनको भेज देंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्थानीय निकाय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि करनाल में कर्णताल के नाम से एक ऐतिहासिक पार्क है जहां पर राजा कर्ण बैठकर सोने का दान किया करते थे। अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस पार्क को डिवैल्प कराया था। आज के दिन उस पार्क की बहुत ही दयनीय स्थिति है जो असामाजिक तत्व हैं वे दिन में उस पार्क में ताश खेलते हैं रात में वहां बैठकर दारू पीते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि उस पार्क का सुधार करने की सरकार की कोई योजना है? यदि योजना है तो उसे टाइमबाउंड किया जाए। जब मंत्री महोदय पिछले दिनों करनाल गए थे तो वहां के लोगों ने इनको इस बारे में बताया भी था।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो विद्ध क्यार लेक का और 48 कोसी क्षेत्र का है लेकिन मेरी बहन इस बारे में 148 कोस पर पहुंच गई हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके सवाल का आदर करते हुए यह कहना चाहूंगा कि यह पार्क म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया में आता है और सौभाग्य से यह विभाग भी मेरे ही पास है। मैं उस नाते से इतना ही कह सकता हूं और इस बात से सारा सदन भी सहमत होगा कि गर्मियां आने वाली हैं और इस वक्त पानी की एक एक बूंद का हमें सदुपयोग करना है। उस लिहाज से पार्क को सिंचित करना तो लोगों को प्यासा मारने वाली बात होगी। लेकिन यह मैं अवश्य सुनिश्चित

करूंगा कि सारे हरियाणा के अंदर जो बड़े पार्क हैं उनके सौन्दर्यीकरण का सरकार पक्का इरादा रखती है। करनाल के इस पार्क को मैं स्वयं जाकर प्राथमिकता के आधार पर देखूंगा।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल भी सुरजेवाला जी के सवाल से संबंधित है। मेरे हल्के में मूंदड़ी गांव में लवकुश का मंदिर है और उस मंदिर की बहुत मान्यता है। माननीय फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड में पास किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी स्वयं मेरे हल्के में गए थे और उनकी जो वहां घोषणाएं थी उनमें भी यह शामिल है। क्या मंत्री जी या फाइनैंस मिनिस्टर साहब इस साल में उसके विकास के लिए फंड देंगे। यह टूरिज्म का भी एक स्पॉट बन सकता है।

श्री ए०सी० चौधरी : मैं भी आदरणीय सदस्य की बात से सहमति प्रकट करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड में काफी लिबरल फंड्स की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम कुछ भी कर सकने में सक्षम नहीं हो पाऐंगे। अगर फाइनैंस मिनिस्टर साहब फंड्स देंगे तो मैं काम करवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक बात कही है। महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में लवकुश मंदिर तीर्थ के बारे में मीटिंग हुई थी और लौहदर तीर्थ जो कि भुक्कल मैडम के हल्के में आता है और एक मेरी कांस्टीच्यूएंसी में कसूर गांव में काया शोधन तीर्थ के नाम से महाभारत काल से यह जुड़ा हुआ है। इन सभी के बारे में ऐस्टीमेट्स बनाए गए थे और उनको रिवाइज भी किया गया है। अब जो ऐस्टीमेट्स हैं उनके तहत इनमें अच्छा पैसा लगाया जाएगा ताकि जो काम हो तो वह लोगों को नजर आए। मैंने पहले भी कहा है कि जिन डिपार्टमैंट्स ने इनको इंप्लीमैंट करना है वे इस बारे में प्रोविजन बना करके हमें भेजें।

Number of Boosting Stations in Barwala Constituency

***851. Sh. Randhir Singh :** Will the Water Supply & Sanitation Minister be pleased to state the total number of boosting stations for the supply of water in Barwala Constituency togetherwith the number of those boosting stations which are working properly ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, A statement is placed on the table of the House.

Statement

17 Boosting Stations were sanctioned for supply of drinking water in Barwala Constituency, the category-wise details of which are as follows :

Boosting Stations Completed = 7

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Name of scheme	Estt. Cost	Expenditure incurred
1.	Boosting station Daulatpur	11.80	5.54
2.	Boosting station Litani	12.30	7.83
3.	Boosting station Prabhuwala	12.50	11.50

[Sh. Randeep Singh Surjewala]

Sr. No.	Name of scheme	Estt. Cost	Expenditure incurred
4.	Boosting station Kapro	8.00	7.80
5.	Boosting station Kheri Jalab	12.00	10.80
6.	Boosting station Koth Kalan	12.75	11.80
7.	Boosting station Budha Khera	8.80	6.42
	Total	78.15	61.69

Boosting Stations where work is in progress = 7

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Name of scheme	Estt. Cost	Upto date funds	%age achi-evement	Likely date of completion
1.	Boosting station and renovation W/S Kharak Punia	60.00	33.00	80%	2008-09
2.	Boosting station Banbhori	10.40	7.00	80%	2008-09
3.	Boosting station Mirchpur	13.70	13.70	70%	2008-09
4.	Boosting station Bhada	12.00	6.00	70%	2008-09
5.	Boosting station Gianpura	13.00	5.00	70%	2008-09
6.	Boosting station Kinnar	9.50	3.00	80%	2008-09
7.	Aug. and Boosting station Barwala town	56.95	20.00	90%	2008-09
	Total	175.55	87.70		

Boosting Stations where work is being taken in hand = 1

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Name of scheme	Estt. Cost	Upto date funds	Likely date of completion
1.	Boosting station Milkpur	13.65	2.00	2008-09

Boosting Stations where work not started due to non-availability of land = 2

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Name of scheme	Estt. Cost	Upto date funds	Remarks
1.	Boosting station at Dhani Khan Bahadur	10.20	3.00	Land not available

Sr. No.	Name of scheme		Estt. Cost	Expenditure incurred
2.	Boosting station at Dhani Garan	8.20	8.20	Land not available

Other Works (Urban)

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Name of scheme	Estt. Cost	Upto date funds	Remarks
1.	Sewerage scheme for Barwala Town	720.00	175.00	Work in progress

श्री रणधीर सिंह : स्पीकर सर, स्टेटमैंट जो दी हुई है उसके हिसाब से सात बूस्टिंग स्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं और कार्य कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में इनकी संख्या 17 है और 17 में से 10 बूस्टिंग स्टेशन बचे हैं। माननीय मंत्री जी ने इसके लिए समय दिया है लेकिन समय के हिसाब से 2008-09 बहुत ही लंबा समय दिया गया है। गर्मियों का सीजन आने वाला है। बरवाला कस्बे में बरवाला शहर का जो बूस्टिंग स्टेशन है उसका जो कार्य है वह 90 परसैंट पूरा हो चुका है और एक दूसरा बूस्टिंग स्टेशन बरवाला शहर के लिए.....

श्री अध्यक्ष : आप स्पैसिफिक क्वैश्चन ही पूछें।

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने समय में इन बुस्टिंग स्टेशनों को बनाने का काम पूरा हो जायेगा और दूसरा बुस्टिंग स्टेशन इसी प्लान में सरहेड़ा के नजदीक बरवाला में बनाना है उसको बनाने का काम क्या इस वर्ष में शुरू हो जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिन सात बुस्टिंग स्टेशनों पर काम चल रहा है, मैंने महकमे से इस बारे में बात की है उन्होंने यह बताया है कि इनका 70-80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और मेरा प्रयास यह होगा कि जून से पहले इनका काम पूरा हो जाये ताकि गर्मियों में पानी की दिक्कत न हो।

Illegal selection of Deputy Director, Agriculture

***879. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

(a) whether the State Government has received any representation against the illegal selection of Deputy Directors of Agriculture by the Haryana Public Service Commission headed by Dr. K.C. Bangar in pursuance to any order and direction of Hon'ble Punjab and Haryana High Court dated 20.9.2005 ; and

[Sh. Karan Singh Dalal]

(b) if so, the contents of the representation and the findings of the enquiry, if any and details of action taken together with the time frame granted by the Hon'ble High Court alongwith the cogent reasons for non-adherence to time frame granted by the Hon'ble Court for taking action ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) :

(a) Yes, Sir. The information is laid on the table of the House.

(b) The information is laid on the table of the House.

Information

(a) A representation was received by the Department of Agriculture, Govt. of Haryana on 25.10.2005 from Dr. Som Prakash and others regarding the alleged illegal selection of Deputy Directors of Agriculture by the Haryana Public Service Commission (HPSC).

A requisition of 13 posts of Deputy Director of Agriculture was sent by the Government on 31.07.2003 to the HPSC. Consequent to this, HPSC carried out the selection process and recommended 12 persons for appointment to the post of Deputy Director of Agriculture in the Department of Agriculture, Haryana, on 10.06.2004 and one more recommendation of Sh. Chand Ram was made on 23.07.2004. They were consequently given appointment vide appointment letters issued on 18.06.2004 and 8.11.2004 respectively.

The representation of Dr. Som Prakash and others was made pursuant to the decision of the Hon'ble High Court dated 20.09.2005 in CWP No. 9789 of 2004 in which Dr. Som Parkash and nine others challenged the appointment of the following as Deputy Directors in the Agriculture Department by the Haryana Public Service Commission :—

S/Shri —

(i) Suresh Kumar son of Shri Sahab Singh,

(ii) Ram Partap son of Shri Jagdish Chander,

(iii) Jagdeep Singh son of Shri Devi Dayal,

(iv) Atma Ram son of Shri Chet Ram,

(v) Rohtash Singh son of Shri Bhoop Singh,

(vi) Pardeep Kumar Meel son of Shri Balwant Singh Meel,

(vii) Manjeet Singh son of Shri Bhag Singh,

(viii) Anil Sehrawat son of Shri Raghbir Singh,

(ix) Surender Singh son of Shri Ram Kishan,

(x) Surender Singh son of Sh. Ram Kanwar,

(xi) Mahavir Singh son of Shri Jagdish Rai,

(xii) Partap Singh son of Shri Luxmi Chand.

This Writ petition was decided on 20.9.2005 with the directions to the

petitioners (Dr. Som Prakash and others) to make representations to the Respondents (Govt. of Haryana) within a period of three weeks from that day so that the Govt. may look into the matter and take action if warranted at its own level. It was also made clear that proper procedure be followed at the time of the enquiry and that either party, which may fail before the Government, would be entitled to approach the Court yet again. The Secretary of the Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary was requested to conduct the enquiry and complete the same within four months from the date the parties first appearing before him.

A C.M. application was filed by the Department stating that it had been decided to entrust the enquiry to the Vigilance Department as the same is already conducting similar enquiry vide order dated 21/4/2005 against Shri K.C. Bangar, Ex-Chairman, Haryana Public Service Commission and there is no need to conduct a parallel enquiry at the level of Joint Secretary in the same matter. The appliction was allowed on 24.03.2006 with the directions that the enquiry by the Vigilance Department be completed within six months.

(b) The Deputy Inspector General of Police, State Vigilance Bureau, Ambala Range was requested on 03.05.2006 to complete the enquiry within stipulated period. Since, the enquiry was not completed within the stipulated period, a COCP was filed by Shri Pardeep Kumar which was heard on 17.10.2006 and was adjourned to 8.12.2006 for filing the reply. The Director, State Vigilance Bureau, Haryana, Panchkula submitted his enquiry report on 28.11.2006. The Hon'ble Court was accordingly informed that the enquiry report of the Vigilance Department has been received and decision in relation thereto is under process and is likely to be taken within one month. The COCP was disposed of on 8.12.2006 with a direction to take final decision in the matter on or before 31st January, 2007. It was also desired that the final outcome of the Vigilance Inquiry be communicated to the petitioners.

In the representation submitted by Dr. Som Prakash and others they had alleged irregularities in the selection of DDAs by the HPSC on which a vigilance enquiry was carried out. The enquiry report of the Vigilance Bureau was submitted on 28.11.2006. As per the enquiry report of the Vigilance Bureau out of eight appointees under enquiry, the allegations were partially/fully proved against four namely ; Sh. Suresh Kumar, Sh. Manjeet Singh, Sh. Chand Ram and Sh. Rajesh Sihag. Consequently, as follow up action on the enquiry report of the Vigilance Department, an order dated 6.4.2007, giving details of the decision taken on the allegation leveled was issued by the Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. Haryana, Agriculture Department and all the petitioners in C.W.P. No. 9789 of 2004 were informed. The Govt. has decided to take action under section 420/467/468/471 of IPC against Sh. Suresh Kumar, and also under the Haryana Punishment and Appeal Rules, 1987, and to chargesheet Sh. Manjit Singh and Sh. Chand Ram for major penalty under the Haryana Punishment and Appeal Rules, 1987. The matter relating to Sh. Rajesh Sihag was closed by the competent authority since the allegation was not proved.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय जो घोटाले हुए जिनमें कहीं तो एच०पी०एस०सी० की सिलैक्शन में घोटाला, दूसरा जे०बी०टी० स्कैम और

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

तीसरा जो श्री ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार के समय डिप्टी डायरेक्टर, एग्रीकल्चर की भर्ती की गई वह जल्दबाजी में की गई और नाकाबिल और निकम्मे लोगों को भर्ती किया गया जब उनको यह दिखाई दे रहा था कि उनकी सरकार अब नहीं आयेगी तो उन्होंने अपने लोगों को जो नाकाबिल थे, जो भर्ती के लिए नियमों को पूरा नहीं करते थे जिनका तजुर्बा नहीं था जो बांगड़ के रिश्तेदार थे और जिनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं थी उनके लिए उन्होंने फ्राड किया और सरकार ने जानबूझकर ऐसे लोगों को भर्ती किया जो नाकाबिल थे, उनको कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग में बैठाया जिसके बारे में कल एक सवाल लगा था कि कृषि का उत्पादन घट रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन नाकाबिल लोगों को इतनी बड़ी तादाद में बैठा रखा है इसके बारे में हाई कोर्ट ने भी विभाग को बाकायदा डायरेक्शंज दी हैं और यह कहा है कि अगर इस रिप्रजैंटेशन में और इस रिट पेटीशन में कोई दम है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है और यह साबित हो चुका है कि उनमें कई नियमों को ताक पर रखा गया है और गैर कानूनी तरीके से रिश्वत देकर इस महकमे में आये हैं तो उनको महकमे से निकाल करके उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज करें। क्या विभाग उनके खिलाफ एक्शन लेगा और जिन अधिकारियों ने इन नाकाबिल लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं उनके खिलाफ भी विभाग क्यों नहीं कार्यवाही कर रहा ?

Sardar H.S. Chatha : This is very unfortunate question and I am dealing it. पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 13 व्यक्ति सिलैक्ट करने थे लेकिन 13 में से 12 व्यक्तियों की लिस्ट भेजी थी। 12 कण्डीडेट्स में से जो नम्बर 1 पर था उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी उस दिन वह व्यक्ति ओवरएज था। उसने यह लिख कर दे दिया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गुम हो गई हैं और मैं दोबारा से सबमिट कर दूंगा। उस व्यक्ति ने उस डेट ऑफ बर्थ को गुम की बजाये करैक्ट करने के लिए पहले भिवानी में अप्लाई किया जब वहां पर नहीं हुआ तो उसने सिविल कोर्ट में केस डाल दिया और 4 महीने की एडवांस में डेट ले ली गई। He was not fit. He could not appear in the test because he was over-age on that day. दूसरा, जो अनफोर्टूनेटली व्यक्ति भर्ती हुआ है उसका नाम मनजीत सिंह है। मनजीत सिंह के बारे में एक अजीब सी स्थिति है कि एक्सपीरियंश पूरा करने के लिए वह दो-दो जगह से स्कालरशिप लेता रहा और वह एक जगह तो मेरठ से स्कालरशिप लेता रहा और उन्हीं दिनों दूसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से स्कालरशिप लेता रहा। अब यह बात समझ से परे है कि वह रातों-रात कैसे मेरठ और लुधियाना पहुंचता था और हाजरी कैसे लगती थी। इसका एक्सपीरियंश पूरा समझा गया और उस हिसाब से उसको भर्ती कर लिया गया। तीसरा केस भी बड़ा अजीब है। पहले तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 12 कण्डीडेटस की लिस्ट पहले भेजी और 13वें व्यक्ति की लिस्ट नहीं दी क्योंकि 13वां आदमी सिलैक्शन में आता ही नहीं था। 13वें व्यक्ति का नाम चांद राम था। वह जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट अपीयर हुआ था लेकिन जब उसका जनरल कैटेगरी में सिलैक्शन नहीं हुआ तो उसने यह लिखकर दे दिया कि मुझे एक्स सर्विसमैन कोटे का बैनीफिट दे दिया जाए जबकि वह ए०डी०ओ० की पोस्ट पर यह बैनीफिट पहले ही ले चुका था इस प्रकार इन तीनों व्यक्तियों ने धोखा किया और धोखा करके ये सिलैक्ट हुए। यह केस हाईकोर्ट में

गया, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा और सरकार ने विजीलैंस की इन्क्वायरी करवाई।

श्री अध्यक्ष : धोखा किया गया या करवाया गया।

सरदार एच०एस० चट्ठा : धोखा तो उन्होंने किया, पब्लिक सर्विस कमीशन की मर्जी से हुआ वैसे तो हो नहीं सकता। मैंने अब इन तीनों को सस्पैंड कर दिया है और इनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिए हैं इनमें से एक के खिलाफ तो केस दर्ज हो गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाकी दोनों के खिलाफ भी जल्दी ही केस दर्ज हो जाएगा।

Mr. Speaker : Now, the questions hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of New Roads in Pataudi Constituency

***862. Sh. Bhupinder Chaudhary :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for construction of new roads in Pataudi constituency are under various schemes ; if so, the names of the roads and the time by which roads are likely to be constructed ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : हां श्रीमान् जी, पटौदी से रिवाड़ी तक वाया जाट जार्टी, 5.40 कि०मी० की लम्बाई की सड़क अनुमोदित की गई है। इस कार्य के लिए निविदाएं 17.3.08 को प्राप्त होने की सम्भावना है जिसके अनुसार कार्य 6 मास में पूर्ण होना है।

Completion of Link Roads connecting neighbouring States

***903. Sh. Sahida Khan :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state —

(a) whether there is any scheme of the Government to complete the link roads connecting neighbouring States ; and

(b) if so, the time by which the road connecting Nagig (Mewat) to Tizara (Rajasthan) will be completed ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) (क) को मध्यनजर रखते हुये, प्रश्न ही नहीं उठता।

Shortage of Doctors in Ch. Bansi Lal Govt. General Hospital, Bhiwani

***868. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Health Minister be pleased to state :—

(a) whether the Government is aware of the fact that there is shortage of Doctors in Ch. Bansi Lal Govt. General Hospital, Bhiwani ; if so the time by which the shortage of doctors is likely to be met out ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide and improve the facilities such as Cobalt-therapy, Cardiac care unit and Neo-natal unit in above said Hospital ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) :

(क) हां, श्रीमान जी। 232 चिकित्सा अधिकारियों (जिस में जिला भिवानी सम्मिलित है) के रिक्त पदों को भरने के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया है। जैसे ही चयन सूचि प्राप्त होगी डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(ख) हां, श्रीमान् जी, कोबाल्ट थैरेपी यूनिट सामान्य अस्पताल, भिवानी में स्थापित किया जा रहा है। जहां तक कार्डिऐक केयर यूनिट और नियो नेटल यूनिट का सम्बन्ध है, वर्तमान पिडियाट्रिक्स और चिकित्सा विभाग को अपग्रेड करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Upgradation of Sub-Stations

***913. Sh. Bhart Singh Chhoker :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the 32 KV Sub-Stations of HVPN at Dikadia and Behroli and also to upgrade the Sub-Station of Samalkha to 220 K.V. ; if so, the time by which these Sub-Stations are likely to be upgraded ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : बेहोली में 2×20/25 एम०वी०ए० 132/33 के०वी० क्षमता का एक नया 132 के०वी० उपकेन्द्र निर्माण करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। यह उपकेन्द्र मार्च, 2010 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

डिकाडला के पास गांव बेहोली में ही 132 के०वी० उपकेन्द्र के निर्माण को ध्यान में रखते हुए डिकाडला में 33 के०वी० उपकेन्द्र का दर्जा बढ़ा के 132 के०वी० उपकेन्द्र करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

132 के०वी० उपकेन्द्र समालखा का दर्जा बढ़ा कर 2×100 एम०वी०ए०, 220/132 के०वी० क्षमता के साथ 220 के०वी० स्तर का करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। इस उपकेन्द्र का कार्य मार्च, 2010 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

Separate Electricity Line of Pump Houses

*919. **Sh. Somvir Singh :** Will the Irrigation Minister be pleased to state :—

(a) whether the Irrigation Department has taken separate electricity line for the pump houses No. 6, 7 and 8 of the Loharu canal on its own expenditure ; and

(b) whether it is a fact that connections have been provided to the private tubewells from the said pump houses ; if so, the time by which the said private connections will be disconnected from the electricity line of the canal ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) जी हां, श्रीमान् जी । सिंचाई विभाग ने लोहारू नहर के पम्प हाउस सं० 6, 7 तथा 8 के लिए अपने खर्च पर एक पृथक बिजली लाईन ली हुई है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् जी । लोहारू नहर के पम्प हाउस सं० 6, 7 तथा 8 से कोई निजी नलकूपों को कनैक्शन नहीं दिए गए है । यद्यपि लोहारू नहर के पम्प हाउस सं० 6 के स्वतन्त्र फीडर से लोक निर्माण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग को 5 स्थानों पर तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेरला को एक स्थान पर जोड़ा हुआ है । दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने आश्वासन दिया है कि इन कनैक्शनों को शीघ्र ही हटा दिया जायेगा ।

Facilities in the Stadiums in Villages

*893. **Sh. Sher Singh :** Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state the type of facilities which will be provided in the stadiums being constructed in the villages by the Government ?

वन राज्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : ग्रामीण स्टेडियमों में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी :--

1. ब्लाक स्तरीय स्टेडियम में 400 मीटर का एथलैटिक ट्रैक, हाकी / फुटबाल/हैण्डबाल मैदान, बास्केटबाल कोर्ट, वालीबाल कोर्ट, कुश्ती, मुक्केबाजी एवं जूडो हेतु बहुउद्देशीय हाल, स्टेज, दर्शक दीर्घा, चेंजरूम, चारदीवारी व प्रसाधन सुविधाएं हैं । ब्लाक स्तरीय स्टेडियम के लिए प्रशिक्षक-कम-प्रबन्धक अनुबन्धित किया जा रहा है ।

2. ग्रामीण स्तरीय स्टेडियम में चारदीवारी, जोगिंग ट्रैक, स्टेज, दर्शक दीर्घा, चेंजरूम, 200 मीटर एथलैटिक ट्रैक / फुटबाल / हाकी / हैंडबाल मैदान, बास्केटबाल एवं वालीबाल कोर्ट की सुविधाएं हैं ।

Old Age Pension

*897. **Sh. Tejender Pal Singh Mann :** Will the Social Justice and Empowerment Minister be pleased to state the total amount paid as old age pension

[Sh. Tejender Pal Singh Mann]
during the year 2006-07 and during nine months from 1.4.2007 to 31.12.2007 togetherwith the amount contributed by the Government of India during the said periods separately?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : श्रीमान जी, वर्ष 2006-07 के दौरान तथा 1.04.2007 से 31.12.2007 तक नौ मास के दौरान वृद्धावस्था भत्ता के रूप में अदा की गई कुल राशि तथा भारत सरकार द्वारा दी गई अंशदान राशि का पृथक-पृथक विवरण निम्न प्रकार से है :–

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वृद्धावस्था भत्ता की कुल राशि	भारत सरकार द्वारा दी गई अंशदान राशि
2006-07	366.71	28.46
1.4.07 से 31.12.07	276.86	25.20

To Revive the Sub-Tehsil Station of Village Badli

***900. Sh. Naresh Sharma :** Will the Minister of State for Revenue and Disaster Management be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to revive the Sub-Tehsil status of Village Badli ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : जी, नहीं ।

Establishment of Medical College at Karnal

***908. Smt. Sumita Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to establish a Medical College at Karnal ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be established ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) :

(क) हां, श्रीमान् जी,

(ख) आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने के बाद करनाल में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित कर दिया जाएगा ।

Judicial Enquiry, Commission on Fire Tragedy of Dabwali Town

***847. Sh. Ram Kumar Gautam :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the terms and conditions of the Judicial Enquiry Commission appointed to enquire into the fire tragedy of Dabwali town ;

(b) whether there was anytime bound schedule to submit the report by the said Commission ; and

(c) If so, the reason of delay in submitting the report.

मुख्यमंत्री (भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

सूचना

डबवाली कस्बा अग्निकांड में पीड़ितों को मुआवजा निर्धारित करने हेतु माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका नं० 13214/96 में न्यायाधीश टी०पी० गर्ग (सेवानिवृत्त) एक व्यक्ति आयोग नियुक्त किया गया जिसकी शर्तें निम्न हैं :—

1. माननीय न्यायधीश आयोग, उसके वेतन व भत्ते के समान वेतन व भत्ते के (वेतन में से पैंशन काटकर) हकदार होंगे ।
2. उच्च न्यायालय के न्यायधीश जो चिकित्सा पर खर्च होने वाली राशि ले रहे हैं के समान ही चिकित्सा पर खर्च होने वाली राशि लेने के हकदार होंगे ।
3. प्रतिमाह 10000 रुपये बतौर मुफ्त मकान किराया भत्ता ।
4. प्रतिवर्ष 3600 मि०ली० तक मुफ्त पानी ।
5. प्रतिवर्ष 10000 यूनिट तक मुफ्त बिजली ।
6. प्रति माह घरेलू दूरभाष से 5000 तक मुफ्त काल व कार्यालय से असीमित दूरभाष काल का अधिकार होगा ।
7. एक कार (वातानूकूलित) व 200 लि० पैट्रोल प्रति माह या वास्तविक खपत (जो भी कम हो)
8. सहायता के लिए कर्मचारीगण व कार्यालय का फर्नीचर ।

जिला में कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्थापना के लिए जरूरी आवास व स्टाफ का प्रबन्ध आयुक्त हिसार मण्डल करेंगे ।

वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान मेजर हैड "2070-ओ०ए०एस० स्पैशल कमीशन ऑफ इन्कवारी" के अन्तर्गत खर्चा वहन किया जायेगा ।

आयोग अपनी रिपोर्ट छः महीने में प्रस्तुत करेगा ।

(ख) जी हां, प्रारम्भ में समय सीमा छह महीने थी, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर समय सीमा बढ़ा दी गई । आयोग की समय सीमा दिनांक 31.3.2008 को समाप्त हो रही है ।

(ग) पीड़ितों के कानूनी सलाहकारों की अनुपलब्धता एवं अन्य प्रशासनिक व कार्य सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाया ।

Waiving off Electricity Bills of Farmers

*820. **Sh. Sushil Indora :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) the details of amount of electricity bills of farmers waived off so far under the electricity bill waiving off scheme worth Rs. 1600 crores ; and

(b) the number of person to whom the no dues certificates have been issued under the said scheme to-date ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान् जी,

(ए) योजना के अन्तर्गत ग्रामीण घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं से संबंधित 998.78 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि दिनांक 31.1.2008 को माफ कर दी गई है।

(बी) योजना के प्रावधान के अनुसार 6,19,137 नम्बर उपभोक्ताओं की बकाया धनराशि माफ की गई है और इसके बाद चालू बिल जारी किए जा रहे हैं। इस योजना में बेबाकी (नो ड्यूज) प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

Selection of Model Village

*804. **Dr. Sita Ram**
Dr. Sushil Indora : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the criteria for the selection of a Model Village togetherwith the details of works on which funds are spent alongwith the total amount provided for the purpose and the department by whom such funds are released ; and

(b) the district-wise number of Model Villages selected during the period from April, 2006 to date togetherwith the total amount spent on the said Model Villages ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) आधारभूत संरचनाओं की कमी, जनसंख्या एवं गांव का कोई विशेष पहलू सामान्य तौर पर माडल गांवों के चयन के लिए मानदण्ड के रूप में अपनाए गए हैं जिनमें मुख्यतया गलियों का पक्का करना, नालियों का निर्माण तथा पेय जल आपूर्ति सुविधाओं का उपलब्ध करवाना शामिल हैं।

पंचायत विभाग द्वारा गलियों को पक्का करने व नालियों का निर्माण करने हेतु 175 करोड़ रुपये एवं पेय जल आपूर्ति सुविधाओं हेतु जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 41.68 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं।

(ख) 91 गांवों को माडल गांवों के रूप में चुना गया है जिनमें से 74 गांवों में विकास कार्यों को करवाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष 17 गांवों के प्रस्ताव कार्यवाही अधीन हैं। अप्रैल, 2006 से 29.2.2008 तक खर्च की गई राशि का जिला वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

जिला का नाम	माडल गांवों की संख्या	गलियों को पक्का करने एवं नालियों के निर्माण पर खर्च की गई राशि (रुपये करोड़ों में)
अम्बाला	5	2.49
भिवानी	16	14.46
फरीदाबाद	1	0.10
फतेहाबाद	1	1.05
गुड़गांव	1	0.05
हिसार	9	16.94
झज्जर	12	8.61
जीन्द	6	10.18
कैथल	6	5.58
करनाल	1	1.80
कुरुक्षेत्र	3	0.22
मेवात	2	1.71
पानीपत	1	1.80
रिवाड़ी	2	1.85
रोहतक	18	13.40
सोनीपत	6	2.94
यमुनानगर	1	0.42
कुल	91	83.60

इसके अतिरिक्त जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग द्वारा चयन किए गए 91 माडल गांवों में से 70 माडल गांवों में पेय जल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 29.2.2008 तक 33.15 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

———

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Bonus for Paddy Crops

109. Dr. Sita Ram : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether the bonus of Rs. 50/-, 50/- i.e. Rs. 100/- has been distributed to the farmers as declared by the Government on the paddy crop ?

उप मुख्यमंत्री (श्री चन्द्र मोहन) : हां श्रीमान् जी, राज्य स्तर की खरीद संस्थाओं द्वारा 161.16 करोड़ रुपये की राशि जो अदा किए जाने वाले बोनस की राशि का 91 प्रतिशत है, संस्थाओं द्वारा किसानों को भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार निजी चावल मिल मालिकों द्वारा खरीद किए गए लेवी धान के विरुद्ध 15.71 करोड़ रुपये जो अदा किए जाने वाले बोनस की कुल राशि का 19 प्रतिशत है, पूर्ण दस्तावेजों की प्रस्तुति के आधार पर प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। बोनस की राशि का भुगतान दिनांक 30.09.2008 तक किया जाना है।

Amount spent under the Employment Guarantee Scheme

107. Sh. Naresh Yadav : Will the Chief Minister be pleased to state the block-wise details of the amount spent under the Employment Guarantee Scheme in district Mahendergarh ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, रोजगार गारंटी योजना के अधीन जिला महेन्द्रगढ़ में प्रारम्भ से खर्च की गई राशि का ब्लॉकवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है –

क्र० सं०	ब्लॉक का नाम	खर्च की गई राशि (रु० लाखों में)
1.	कनीना	545.59
2.	नांगल चौधरी	392.61
3.	अटेली	516.95
4.	महेन्द्रगढ़	411.84
5.	नारनौल	345.89
	कुल	2212.88

Financial Help on the Marriages of Sons and Daughters of Freedom Fighters

108. Dr. Sita Ram : Will the Chief Minister be pleased to state whether

there is any scheme of the Government to provide financial aid on the marriages of sons and daughters of the freedom fighters ; if so, the amount spent so far on the marriages of the sons and daughters of such freedom fighters since the start of the said scheme ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : जी हां, श्रीमान् । स्वतंत्रता सेनानियों / आजाद हिन्द फौज के सदस्यों / विधवाओं को उनकी पुत्रियों / आश्रित बहनों की शादी के लिए वित्तीय सहायता देने बारे हरियाणा सरकार की योजना है । स्वतन्त्रता सेनानियों / आजाद हिन्द फौज के सदस्यों को उनके पुत्रों की शादी के लिए वित्तीय सहायता देने बारे ऐसी कोई योजना नहीं है । इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1984, जबसे इस योजना को लागू किया गया है, अब तक 24,66,000 रुपये की राशि खर्च हुई है ।

सदन की मर्यादा तथा गरिमा को बनाए रखने संबंधी अध्यक्ष महोदय का अवलोकन

Mr. Speaker : Hon'ble Members, in a democratic set-up the Members have the right to speak in a free and frank manner in the House but this right enjoins upon them the duty to restrain themselves and refrain from indulging into manhandling with other Members and creating unruly scenes in the House. The unprecedented scenes witnessed yesterday have pained me greatly and I am sure it has pained all others who have a staunch and unshakeable faith in democratic institutions.The members of the Indian National Lok Dal made every effort to interrupt the proceedings of the House and even they did not allow their own leader to speak. Their leader Shri Om Parkash Chautala also cast aspersions on the Chair unfortunately not only once but many a times. It is not only the duty of the Speaker to maintain decorum and dignity of the House but of the other Members of various parties. The Speaker cannot perform his duty well without the whole-hearted cooperation of the Members of both the sides. The Members of the Indian National Lok Dal manhandled/misbehaved with Shri Arjan Singh, a member of the BSP, keeping in view the fact that he is the lone member of his party. Had they manhandled/ misbehaved with the Members of the ruling party, whose strength is more than 65, either they would have dared to manhandle/misbehave with them, or they would have got a befitting reply from them. Therefore, I feel it my duty to make it quite clear that in case of any disturbances or attempts to interfere with the proceedings of the House, these will be taken care of in accordance with the prestige and dignity of the House and the Members will not be allowed to breach the privilege of the House as it is the duty of all of us to uphold and enhance the dignity of this House. It is the duty of the Speaker to protect the interest of all the Members of all parties being a custodian of the House. I hope that the Members of Indian National Lok Dal will improve their behaviour and all the Members will cooperate me in the smooth conduct of the proceedings of this House.

अनुपस्थिति की अनुमति

(i)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received leave of absence dated 11th March, 2008 from Shri Lachhman Dass Arora, Industries Minister, which reads as under :—

"Speaker Sir,

As I am not feeling well, I may please be allowed leave of absence from the House today on 11th March, 2008."

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the leave of absence be granted to Shri Lachhman Dass Arora, Industries Minister to remain absent from the sitting of the House today, i.e. the 11th March, 2008 ?

Voices : Yes.

(The leave was granted)

(ii)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received leave of absence dated 7th March, 2008 from Shri Nirmal Singh, M.L.A.which reads as under :—

"Sir,

I will not be able to attend the Session on 11th and 12th of March. Therefore, I leave of absence may kindly be granted to me."

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the leave of absence be granted to Shri Nirmal Singh, M.L.A. to remain absent from the sitting of the House on 11th to 12th March, 2008 ?

Voices : Yes,

(The leave was granted.)

अनुपस्थिति की सूचना

(i)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a letter from Senior Secretary to Smt. Kartar Devi, Health Minister dated 11th March, 2008, that she is not feeling well and unable to attend the sitting of the House today, i.e. the 11th March, 2008.

(ii)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a letter from Private Secretary to Sh. Anil Thakkar, Parliamentary Secretary, Revenue dated 11th March, 2008, that he is not feeling well and unable to attend the sitting of the House today, i.e. the 11th March, 2008.

सदस्य का नाम लेना

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी ज्यों ही मैं सदन में दाखिल हुआ आपकी तरफ से हमारे एक विधायक को नेम किया गया। कल भी हमारी पार्टी के एक सदस्य को सदन की शेष अवधि के लिए नेम कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, वाक-आउट करने के बाद सदन में नहीं ठहरना चाहिए। वाक-आउट करने के बाद वे सदन में क्या कर रहे थे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, नेम करने के बाद हमारे उस सदस्य को सदन से बाहर ले जाया जा रहा था लेकिन पीछे से उसे सदन की शेष अवधि के लिए निष्कासित कर दिया गया, जैसा कि हमने सुना है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती और कोई सदस्य यदि बोलने के लिए खड़ा होता है तो आप उन पर कामैंट्स कसते रहते हैं। आज भी पता नहीं आप किस किस्म के कामैंट्स कस रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कोई अधिकार नहीं है कि वे इस प्रकार के एस्पर्सन चेयर के प्रति कास्ट करें। ये जब भी सदन में आते हैं कोई न कोई एस्पर्सन चेयर के प्रति कास्ट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी सदस्य सम्मानित सदस्य है। आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी को बोलने का अवसर न दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, अभी मैंने जो पढ़ा है, क्या वह आपने सुना है। (शोर एवं व्यवधान) आप अंग्रेजी समझते हैं या नहीं समझते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या हम सम्मानित सदस्य नहीं हैं। कल इन्होंने मेरे साथ कौन सा सम्मान किया था। क्या आज ये वह बात भूल गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब हम बोल रहे होते हैं तो आप इशारा करके दूसरे मैंबर को खड़ा कर देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : It is wrong to suggest. (Noise and interruptions) चौटाला जी, यह आपके लैवल की बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, this is seriously condemnable and objectionable. (Noise and Interruptions).

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप बहुत बड़े बाप के बेटे हो। आप सदन में इस तरह का व्यवहार करके क्यों उनका नाम मिट्टी में मिला रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) आपको सदन की कार्यवाही में विघ्न डालने का क्या अधिकार है? Please sit down. (Noise and Interruptions). Chautala Ji, I warn you, I am on legs. Please sit down, If you don't know the decency and decorum of the House, then you please sit down. (Noise and Interruptions).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप किसी के प्रति भी कामैंट कसते रहते हो। (शोर एवं व्यवधान) आपकी अपनी गरिमा तो है नहीं लेकिन आप इस चेयर की गरिमा का तो ध्यान रखें। (शोर एवं व्यवधान) हम जीरो ऑवर में अपनी बात कह रहे हैं। क्या आपका यही तौर तरीका रहेगा। (शोर एवं व्यवधान) आपकी यही मंशा है कि हम सदन में न आयें। (शोर एवं व्यवधान) क्या आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Chautala, you please sit down, I warn you. (Noise and Interruptions). Mr. Chautala, I warn you. (Interruptions). Nothing to be recorded.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, *********

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, कल जो घटना हुई उसी को आज आप फिर क्यों दोहरा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) Nothing to be recorded.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, *********

Mr. Speaker : Chautala Ji, I name you. Please you may leave the House. (Noise and interruptions).

(At this stage Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. withdrew from the House).

वाक-आऊट

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी पार्टी के नेता को नेम किया है, इसलिए हम एज ए प्रौटैस्ट हम सदन से वाक-आऊट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह सढौरा : **** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. (Interruptions)

श्री ईश्वर सिंह पजाका : **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री साहिदा खान : **** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Whatever they had said nothing to be recorded. (Noise and Interruptions).

At this stage all the members of Indian National Lok Dal present in the House staged a walked out from the House).

इंडियन नेशनल लोक दल के सदस्यों के दुराचरण तथा अनुत्तरदायी व्यवहार की निन्दा करना

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की कुछ परिपाटियां हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ परम्पराएं हैं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी हाउस का

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

सम्मान उसके जो चुने हुए सदस्य आते हैं उनके व्यवहार और उनके self restraint तथा दूसरे सदस्यों के प्रति उनके सम्मान से बड़ा होता है। अध्यक्ष महोदय, चाहे किसी राजनैतिक पार्टी का एक सदस्य हो और चाहे किसी राजनैतिक दल का बहुमत हो, सभी सदस्य इस सदन में समान हैं। ये लोग एक समय यहां बैठा करते थे। उस समय इनमें बहुत ज्यादा अहंकार और घमण्ड होता था। इनके उसी अहंकार और घमण्ड की वजह से हरियाणा की 2.50 करोड़ जनता ने ओम प्रकाश चौटाला के घमण्ड को अपने एक वोट की पावर से एक झटके में चकना चूर कर दिया। इनकी संख्या इतनी कम रह गई कि आज इनका नेता रिकोगनाईज्ड विपक्ष का नेता भी नहीं बन सकता। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि एक कहावत है कि "रस्सी जल गई उसका बल नहीं टूटा"। आज यही हाल चौटाला जी का है। अध्यक्ष महोदय, इस बात की आपने भी चर्चा की है कि कल जिस प्रकार का व्यवहार लोकदल के सदस्यों ने किया कि 8-9 सदस्य इकट्ठे होकर बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य के विरुद्ध खड़े हो गये। बहुजन समाज पार्टी के अगर एक सदस्य हैं तो कांग्रेस पार्टी चाहे एक सदस्य हो और चाहे 10 हों और चाहे वे 80 हों सबके लिए बराबर सम्मान चाहते हैं। आप यहां के कस्टोडियन हैं। अध्यक्ष महोदय, आप एक सदस्य को भी उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से आप सत्ता पक्ष के सदस्यों को देखते हैं और आप हमेशा चाहे वह लोकदल के सदस्य हों, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हों, चाहे वे निर्दलीय सदस्य हों, चाहे वे बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हों और चाहे वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों आपने हमेशा सभी को एक नजर से देखा है और आप सभी को लगातार मौके देते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कई बार तो सत्ता पक्ष के लोगों को यह भी लगता है कि जैसे उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है जैसे आज आपने 16 सप्लीमैंट्री में से 10 केवल लोकदल के साथियों को पूछने की इजाजत दी। परन्तु अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने यह निर्णय कर रखा है कि वे इस सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे क्योंकि जब तक वे इस सदन में नहीं आते इस सदन की कार्यवाही बहुत सलीके से, पूरी तहजीब से, बहुत अदब से एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान की भावना रखते हुए चलती है। राजनीति में मतभेद होते हैं। हमारी और उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती यह सच है हमारे और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा भी मेल नहीं खाती परन्तु उसका यह मतलब नहीं है कि हम राजनीति के जो मान दण्ड हैं, जो इस सदन की मर्यादायें हैं उनका घोर उल्लंघन करें। किसी का सम्मान ही न करें और यहां तक स्थिति पहुंच जायें कि हम किसी माननीय सदस्य को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने तक उतारू हो जायें और अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करें। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जब भी इस सदन में आते हैं वे यह मन बनाकर आते हैं, वे आने से पहले ही स्पीकर के लिए एक्सपर्सन कास्ट करना शुरू कर देते हैं और जाते समय तक यही उनका व्यवहार और रवैया रहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस हाउस को अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोग जो इस मानसिकता से ग्रस्त हैं जो केवल यही मन बनाकर आते हैं कि वे इस सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देना चाहते, न प्रश्न काल को चलने देना चाहते, न शून्य काल को चलने देना चाहते, न किसी सम्मानित सदस्य को प्रश्न देना चाहते न किसी को सप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछने देना चाहते न सदन का आदर करना और न ही सदन के अध्यक्ष का आदर करना चाहते हैं। पूरा अनादर का माहौल जो उनकी मानसिकता का परिचायक है और जो उनके मन और दिमाग के अंदर घुसा है वे इस सदन

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

को भी उस रंग के अंदर रंगना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण में यह सम्भव नहीं है। इस सदन की मर्यादा, इस सदन की परिपाटी, इस सदन की परम्परा और उनका निर्वहन आपके संरक्षण के अन्दर सभी दलों के सदस्य करेंगे। मेरा आपकी अनुमति से इस सदन से अनुरोध है कि ऐसा व्यवहार जो आज भी श्री ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी का रहा है, आज भी चेयर के साथ जिस प्रकार वे अपमान की भाषा का लगातार इस्तेमाल करते रहे और कल भी जो उनका व्यवहार रहा उसको ध्यान में रखते हुए इस सदन को सर्वसम्मति से श्री ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी के इस व्यवहार को कंडैम करना चाहिए।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : स्पीकर सर, हरियाणा के लोग अपने इलाके की और प्रदेश की भलाई के लिए हमें अपने वोट के माध्यम से चुनकर भेजते हैं। इस हाउस में बैठने के बाद चेयर पर बैठे स्पीकर साहब सभी सदस्यों को सम्मान की दृष्टि से अपने हल्के और प्रदेश की समस्याओं पर बोलने का आदेश देते हैं। इसी प्रकार से हम सभी सदस्यों का भी यह कर्त्तव्य बनता है कि हम चेयर के आदेश की पालना करते हुए और स्पीकर साहब का सम्मान करते हुए उनके हर आदेश को मानें। हमें बोलने का आदेश मिले तो हम बोलें और बैठने का हुक्म हो तो बैठ जायें। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस हाउस में दोनों तरफ बैठने का मौका मिला है। 50 प्रतिशत टाइम मिला मुझे रूलिंग की तरफ बैठने का और 50 प्रतिशत के करीब टाईम मिला विपक्ष में बैठने का। श्री ओम प्रकाश चौटाला 5 साल इस सदन में लीडर ऑफ दी हाउस रहे उस समय मैं विपक्ष में बैठता था और उनके पिता चौधरी देवी लाल भी जब विधान सभा में लीडर थे उस वक्त भी मैं विपक्ष में बैठता था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में बैठते हुए हमने कभी भी चेयर की अवहेलना नहीं की बल्कि आदर और सम्मान किया। मैं यह कह सकता हूं कि पूरे पीरियड में कभी भी स्पीकर को यह मौका नहीं दिया कि हमें हाउस से निकाला जाये या नेम किया जाये। विपक्ष में बैठते हुए चेयर का सम्मान किया। अध्यक्ष महोदय, एक मौका तो ऐसा आया कि उस समय चौ० देवी लाल मुख्यमंत्री थे और मैं विपक्ष में होने के नाते सरकार के खिलाफ जनता की भलाई के लिए हाउस में आवाज उठाता था। मैंने पूरे तथ्यों के साथ जो सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा था उस पर बहुत हंगामा हुआ था। अध्यक्ष महोदय, यह बात रिकॉर्ड है कि हाउस एडजर्न हो गया था। जब दोबारा हाउस शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने उस सवाल का जवाब दिया और यह कहा कि श्री मांगे राम गुप्ता जी, जो कि विपक्ष के विधायक हैं और उन्होंने सरकार पर जो उंगली उठाई है, हमने पूरी तसल्ली की है, उसमें पूरी सच्चाई है। उन्होंने अधिकारियों को हुक्म दिया कि गुप्ता जी ने जो बात कही है उस पर पूरा अमल होना चाहिए और सरकार की तरफ से इस बारे में कोई मुखालफत नहीं होगी। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि विपक्ष के विधायक भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने हल्के के लिए, प्रदेश के लिए और जनता के लिए ठीक तरीके से अपनी बात इस हाउस में कहें तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्पीकर किसी भी सदस्य को बाहर निकालेगा या नेम करेगा। सभी सदस्यों का यह कर्त्तव्य बनता है कि वे सैंसिबल होकर बैठें, दिमाग में किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा लीडर बनकर हाउस में बैठने की बात कहे और यह कहे कि जैसे मैं कहूं वैसे यह हाउस चले। यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है। हम इस बात की तसलीम

करते हैं कि जब से आप इस चेयर पर बैठे हैं आपने सभी सदस्यों को बराबर का समय और सम्मान दिया है। आपसे मेरी विनती है कि इसी तरह की प्रथा को कायम रखते हुए हाउस के प्रत्येक सदस्य को अपने हल्के की समस्याओं को उठाने का पूरा मौका दें ताकि हम अपने फर्ज को पूरा करते हुए हल्के की जनता का पूरा विश्वास जीत सकें। यही मैं कहना चाहता था, धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रदेश में लम्बे अर्से तक जो मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद अपने पद की गरिमा को ही नहीं समझ पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन देख रहा है कि श्री ओमप्रकाश चौटाला जी जब आते हैं तो आपके प्रति और दूसरे सदस्यों के प्रति जानबूझ कर गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा लगता है कि जो उनकी गुस्ताखियां हैं जो उनकी काली करतूतें इस हरियाणा में रही हैं, जिस बेहूदा तरीके से प्रदेश को इन्होंने लाठी से हांका है और प्रदेश को बदनाम किया है उससे ऐसा लगता है कि आज की सरकार के सामने आने की इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। इस सरकार का मुकाबला करने की इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अगर ये इसी तरीके से भागते रहे तो यह तो इनकी अपनी चाल है। आप बड़े दिल के मालिक हैं, आपने इतना अच्छा सदन बना कर दिया है मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सदन की मर्यादा को देखते हुए अगर आप ठीक समझें तो सभी दलों के विधायकों की एक बैठक आप अपने चैम्बर में बुलाएं। उसमें आप ओम प्रकाश चौटाला जी को भी बुलाएं, बहुजन समाज पार्टी के सदस्य को भी बुलाएं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को भी बुलाएं और हमारे कांग्रेस के जो संसदीय कार्य मंत्री जी हैं या और दूसरे सदस्य हैं उनको भी अगर आप बुलाना चाहें तो बुलाएं और ये जो बेहूदगी कर रहे हैं यह नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के लोग उम्मीद करते हैं कि बजट सैशन में उनके दुःख तकलीफों की चर्चा होगी। सरकार की कारगुजारियों की जानकारी लोगों को मिलेगी। सरकार ने लोगों के लिए बजट में क्या-क्या सपने संजोये हुए हैं उसकी जानकारी लोगों को मिलेगी। स्पीकर सर, ये लोग जानबूझ कर क्वैश्चन आवर की कार्यवाही को डिस्टर्ब कर रहे हैं और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। यदि आप ठीक समझते हैं तो आप उन लोगों को एक और मौका दें कि वे आकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें। यह सारा हाउस आपकी फाखदिली को देख रहा है। आप सारी पार्टियों के प्रतिनिधियों को अपने चैम्बर में बुलाएं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बुलाएं, बी०एस०पी०, बी०जे०पी० और कांग्रेस के हमारे पार्लियामैंट्री अफेयरज मंत्री जी और निर्दलीय साथियों में से जिसे भी आप मुनासिब समझें बुलाएं और उनसे बात करें। यदि इन लोगों की तरफ से ठीक बिहेव करने का आश्वासन मिलता है तो आप इस बारे में कोई निर्णय लें।

श्री नरेश यादव (अटेली) : अध्यक्ष जी, आज और कल विधान सभा में जो कुछ हुआ वह अफसोसनाक है। हमारे माननीय सदस्य श्री अर्जन सिंह के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ अगर सारे सदस्य और निर्दलीय साथी नहीं पहुंचते तो कल एक बड़ा हादसा हो जाता और उस हादसे के कारण हमारा प्रदेश भी यू०पी० और बिहार की विधान सभाओं की तरह बदनाम हो जाता। कल यह हादसा होने से बच गया। आज इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात चल रही थी। एक तरफ हमारे भाई हिसार सिरसा में इस बात की परेशानी से

[श्री नरेश यादव]

परेशान थे कि वाटर लॉगिंग हो रही है और सेम की समस्या हो रही है। वे लोग पानी को निकालने के लिए परेशान हो रहे थे। इस बार भी वहां पर कृषि मेला लगा था और वहां पर कृषि मेले में कृषि मंत्री जी गए थे वहां पर 10 हजार किसान आए थे और उन्होंने मांग की थी कि हमारा वाटर लैवल बहुत ऊपर आ गया है दूसरी तरफ हमने सब्मीमैंट्री की थी कि दक्षिणी हरियाणा में जो पानी का लैवल नीचे जा रहा है इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। हांसी बुटाना नहर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें पानी मिल सकता है। मैंने इस बारे में मंत्री जी से इतना ही जानना चाहा था कि इस नहर के बनने में क्या परेशानी है, क्या रूकावट है। इस बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा था इसमें रूकावट कोर्ट कचहरी की है। अध्यक्ष जी, कोर्ट कचहरी की जो रूकावट है वह सभी लोग जानते हैं, सभी मैम्बर्ज जानते हैं कि उसके अन्दर रूकावट पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं या दूसरे हमारे माननीय सदस्य हैं। हमारे माननीय सदस्य सदन में आएं और इस बात को बताएं कि हांसी बुटाना लिंक नहर लोगों के हित में बन रही है। कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। पानी हमारी जीवन रेखा है। जो लोग इसके बनने में बाधा डाल रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हाउस में इस प्रकार की वारदात दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस बारे में माननीय कर्ण सिंह दलाल जी ने जो सुझाव दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affiars Minister will move a resolution.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That this House condemns the misbehaviour and irresponsible attitude of the members of the Indian National Lok Dal and the unruly scenes created by them yesterday the 10th March, 2008.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House to adopt the resolution moved by the Parliamentary Affairs Minister condemning the misbehaviour and irresponsible attitude of the Members of Indian National Lok Dal ?

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That this House condemns the misbehaviour and irresponsible attitude of the members of the Indian National Lok Dal and the unruly scenes created by them yesterday the 10th March, 2008.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I want to speak. स्पीकर सर, यहां पर एक बात बार-बार दोहराई जाती है और हाउस की परम्पराएं, हाउस की मर्यादा और ऑगस्ट हाउस की बात कही जाती है। पहले तो हमें यह देखना है कि ये मर्यादाएं ये परम्परायें, ये मूल्य क्या हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं 1977 से इस हाउस का मैम्बर हूं। हमने परम्पराएं तो डाली नहीं। जो भी यहां पर ट्रेजरी बैंचिज पर बैठते हैं वे विपक्ष को बुलडोजिंग करने की कोशिश करते हैं अगर विपक्ष कभी सशक्त और मजबूत हुआ तो जो कोई अभद्र

भाषा बोल सकता है उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। मैं खुद यह महसूस करता हूं। इस कान्फ्रैंस का जिक्र भाई कर्ण सिंह दलाल जी ने भी किया था, यह कान्फ्रैंस थी All India Conference of Presiding Officers, Chief Ministers, Ministers, Ministers for Parliamentary Affairs, Leaders and Whips of the parties on "Discipline and Decorum in the Parliament and Legislative Assemblies". This conference was held in the year 2001 at New Delhi and after that there were repeated meetings of the different whips from all over the country. सर, अल्टीमेटली इन कान्फ्रैंस का कन्क्लूजन यह निकला कि पार्लियामैंट की सीटिंग्ज 110 होनी चाहिए। बड़ी स्टेट्स की सीटिंग्ज 90 होनी चाहिए और जो छोटी स्टेट्स हैं उनकी सीटिंग्ज कम से कम 50 होनी चाहिए। सर, कल आपने भी पढ़कर सुनाया था कि हरियाणा में पिछले पांच साल में जब चौटाला साहब की सरकार थी, तो उस वक्त बजट सैशन की 16, 15, 14, 9 या 8 ही सीटिंग्ज हुई थी। यही नहीं कांग्रेस की गवर्नमैंट के वक्त में भी कोई ज्यादा सीटिंग्ज नहीं होती थी। सर, जो भी चीफ मिनिस्टर की सीट पर बैठता था उसकी कोशिश होती है कि सैशन जल्दी से रैप-अप हो, खत्म हो। सर, अगर आप हाउस की 50 सीटिंग्ज करना चाहते हैं तो हमें यहां पर नई परम्पराएं डालनी होंगी। अगर हम यह कहें कि यह हमारी हाउस की परम्परा है, 40 साल हरियाणा को बने हुए हो गए हैं और साल की हाउस की एवरेज सीटिंग्ज 16 हैं तो इससे शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यहां पर कहा था कि महाराष्ट्र विधान सभा का नागपुर और मुम्बई में दो जगह सैशन होता है और उनकी 108 एवरेज सीटिंग्ज होती हैं। सर, आपने हाउस की रैनोवेशन करवाई है, यहां पर नई सीट्स लगाई हैं, अपने कमरों की भी रैनोवेशन करवाई है और वहां पर भी नया फर्नीचर वगैरह लगवाया है यदि हम इन कुर्सियों का 50 दिन भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं और हम यह समझते हैं कि ये कुर्सियां सिर्फ 16 दिन या 10 दिन के प्रयोग के लिये ही बनी है तो मैं नहीं समझता हूं कि We are doing justice with our people. मैं आपसे यह भी गुजारिश करता हूं कि I totally agree with Mr. Karan Singh Dalal that you must call all the M.L.As. of all the leaders of the parties so that a decision can be taken. यह नहीं हो सकता है कि हमें कई आदमी अच्छे लगते हैं या कई बुरे लगते हैं। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं इन्होंने 3-4 इलैक्शन ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने लड़े हैं। इसी तरह से हमारी कोई भी पुरानी पार्टी हो सकती है, डांगी साहब, की पुरानी पार्टी थी औरों की भी दूसरी पार्टी हो सकती है। अगर हम इलैक्शनों को आधार मानकर यहां पर कोई बात करें और सोचें कि हाउस हमारी विल पर चले तो यह अन्फोरचुनेट होगा कि हम हाउस की कार्यवाही को छोटा कर दें तो I do not subscribe to this. यदि हम डिबेट का जो स्तर है, उसको नीचे ले आएं तो यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा। माफ करना सर, कल जब ओम प्रकाश चौटाला जी बोल रहे थे यदि आप उनको बोलने देते तो वे ज्यादा समय नहीं बोल सकते थे क्योंकि वे तैयारी करके नहीं आए थे। स्पीकर सर, इन चीजों का बहुत असर हरियाणा के लोगों पर पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम सरकार को नहीं बोल सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम मंत्री बनकर यहां पर खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं। सर, 50 दिन की सीटिंग बहुत बड़ी होती है। 50 दिन means 200 घंटे। अगर इन 200 घंटों में हम हरियाणा के लोगों का चित्रण कर सकें तो करना चाहिए। सभी विधायक मिलकर कर सकें, एज ए ग्रुप कर सकें, सभी पालिटिक्ल पार्टीज कर सकें तो हम हरियाणा

[Sh. Birender Singh]

के लोगों में एक संदेश दे सकेंगे। एग्जीक्यूटिव पर हमारी डिपैंडैंस नहीं है। हमारी डिपैंडैंस तो उस पर है जिसके अध्यक्ष स्पीकर साहब आप स्वयं हैं। जिनके नीचे 90 एम०एल०एज० बैठकर हरियाणा की विभिन्न समस्याओं पर विचार रखते हैं और सुझाव देते 11.00 बजे हैं उन सुझावों को अगर आप ठीक मानते हैं और यदि सरकार उनको ग्रहण करती है तो हरियाणा के लोगों को उसका फायदा होता है। मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप इनको हाउस में बुला लें और इनसे पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : बुला तो लेंगे लेकिन उनको लाएगा कौन? ओम प्रकाश चौटाला बी०ए०सी० के भी मैम्बर हैं but he has not attended even a single meeting. दलाल साहब, अगर आप उनकी गारंटी ले लो तो I will call a meeting.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, आप मीटिंग बुला लें उसमें अगर वह आएं तो ठीक है और अगर न आएं तब आप देख लेना।

श्री बिरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, आप मीटिंग बुलाओ। अगर वे उसमें न आएं तो न आएं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वे उसमें न आएं तो आप मीटिंग ही न बुलाएं। आप मीटिंग बुलवाओ और उनसे कहो कि भई, आप आ जाएं, आप आकर मामला शोर्ट आउट करें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मीटिंग बुला लेते हैं उस मीटिंग में आप भी आएं और बी०जे०पी० की तरफ से मलिक साहब आ जाएं। इसी तरह से इस मीटिंग में एक बी०एस०पी० के विधायक, आजाद विधायक और मांगे राम गुप्ता जी भी आएं।

श्री बिरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, बी०जे०पी० वालों से पूछ तो लो कि अगर इन्होंने उनसे समझौता करना है तो फिर इनकी भी जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हम आज ही साढे चार बजे मीटिंग बुला लेते हैं या फिर कल नौ बजे मीटिंग बुला लेते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरी भी आपसे यही रिक्वैस्ट है कि आप कल नौ बजे मीटिंग रख लें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, आप इस मीटिंग का नोटिस इशु करवा दीजिए।

श्री बिरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, अगर आप मेरे को बुलाना चाहते हैं तो फिर यह मीटिंग आज ही बुला लें क्योंकि कल मैं तो यहां नहीं रहूंगा।

Mr. Speaker : Question is—

> That this House condemns the misbehaviour and irresponsible attitude of the members of the Indian National Lok Dal and the unruly scenes created by them yesterday the 10th March, 2008.

The motion was adopted unanimously.

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affiars Minister will move the motion under Rule 121, regarding nominations of various Committees.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so far as they relate to the constitution of the —

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes ;

for the year 2008-2009 be suspended.

Sir, I beg to move—

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2008-2009, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the provisions of Rules 231, 233. 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so far as they relate to the constitution of the—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes ;

for the year 2008-2009 be suspended.

And

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2008-2009, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the —

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

[Mr. Speaker]

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes ;

for the year 2008-2009 be suspended.

And

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2008-2009, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on the Governor's Address will resume. Smt. Geeta Bhukal was on her legs. Smt. Bhukkal may continue her speech.

श्रीमती गीता भुक्कल (एस०सी०, कलायत) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। सबसे पहले इस गरिमामय सदन में जो आपकी गरिमामय चेयर है मैं उसका भी अभिनंदन करती हूं। आपने इस विधान सभा भवन का रेनोवेशन करके जो इसका कायाकल्प किया है। इस बात के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी धन्यवाद किया। हम इस बात के लिए आपका स्वागत करते हैं। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के दौरान सदन में बार-बार मेजें थपथपाई गई, सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाई और जो कार्य हुए हैं उनके होने का पूरा प्रमाण दिया। हरियाणा प्रदेश में जो प्रगति और विकास के कार्य चल रहे हैं उन पर चर्चा क्यों न हो। हरियाणा में बड़ी तेजी से बिजली के उत्पादन के कार्य चल रहे हैं। न केवल हरियाणा में बल्कि दूसरे राज्यों में भी यहां हो रहे विकास कार्यों की और जो स्कीमें यहां चलाई जा रही हैं उनकी चर्चा हो रही है। केन्द्र सरकार का जो बजट आया है और सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये के ऋण माफ करने की घोषणा की है मैं उसका स्वागत करती हूं। हमारा जो हिन्दुस्तान है वह सारा गांवों में बसता है। गांव के किसान के दुखदर्द की किसी ने यदि संभाल की है तो वह हमारी यू०पी०ए० की चेयरपर्सन माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की है। हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने संभाल की है। हमारी पार्टी के सांसद और विधायकगणों ने हमारी यू०पी०ए० की चेयरपर्सन से किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की थी और उसी का यह नतीजा हुआ कि केन्द्र सरकार ने बजट में किसानों का 60 हजार करोड़

रुपये का कर्ज माफ किया है। हमारी केन्द्र सरकार ने इसके लिए पहले से कोई वायदा नहीं किया था लेकिन यह कर्ज माफ करके अपना पूरी तरह से किसान हितैषी होने का प्रमाण दिया है। हमारी सरकार की हमेशा से ही सोशल सैक्टर के उत्थान और इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट की प्रोयोरिटी रही है। हमारी सरकार ने विशेष तौर से कृषि क्षेत्र में बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि खोखले वायदे करते रहे, किसानों पर गोलियां चलवाई लेकिन हमारी सरकार ने तीन साल के शासन काल में सच्ची किसान हितैषी सरकार होने का पक्का प्रमाण दिया है और जो किसानों के दुःख के आंसू थे वे खुशी के मोती बनकर उभरे हैं। किसान आज बहुत ज्यादा खुशहाल हैं। सार्वजनिक कार्यों के लिए हमारी सरकार जो भूमि अधिग्रहण करती है उसके लिए फ्लोर रेट जो सरकार ने फिक्स किया है वह सबसे अधिक है। रिहैबिलिटेशन पौलिसीज जो अभी हाल ही में हमारी स्टेट में नोटीफाई हुई हैं उनके मुताबिक किसान भी हमारे लेजिटिमेट पार्टनर बनते हैं। इसके लिए मैं हमारी सरकार का तहेदिल से धन्यवाद करती हूं। इस अवधि में जहां कहीं भी प्राकृतिक आपदायें आईं तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उन एरियाज का दौरा किया और तुरंत राहत कार्य करवाए व सबसे ज्यादा मुआवजा दिया। गन्नौर में हमारी सरकार मार्किटिंग बोर्ड के द्वारा सबसे बड़ी टर्मिनल मार्किट बनाने जा रही है जो कि 500 एकड़ एरिया में बनेगी। यह सबसे बड़ी होलसेल मंडी होगी और इसमें ऐग्रो मॉल्स बनेंगे। यह प्रपोजल भी हमारी सरकार के पास पेंडिंग है। इससे भी सरकार ने किसान और गरीब हितैषी होने का प्रमाण दिया है। शुरू में ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही एक कलम से किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बकाया बिजली के बिल माफ किये। इसके अलावा जो कर्जा हमारे गरीबों ने और किसानों ने लिया हुआ था उसका ब्याज माफ किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के दौरान जो किसान कर्जा नहीं चुका सकते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। हमारी सरकार ने सत्ता संभालते ही इस काले कानून को खत्म किया है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक फैसला माननीय यू०पी०ए० की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिया है वह है 60000 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया है यह एक ऐतिहासिक कदम है। जिससे सही मायने में जो हम किसानों को धरती पुत्र कहते हैं आज वे हमने खुशहाल बनाये हैं। आपने देखा होगा कि इस फैसले से खुश होकर हमारे किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने पहुंचे थे। आज हमारे किसानों को अपनी जमीन का इतना ज्यादा मुआवजा मिला है कि वे खुशहाल हो गये हैं। हमारी सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसानों को मोबाइल सेवा उपलब्ध करवायी है क्योंकि हमारे ज्यादातर किसानों के पास आजकल मोबाइल हैं। उस मोबाइल सेवा का नम्बर 9915862026 है और वे इस मोबाइल नम्बर के माध्यम से सरकार को एस०एम०एस० कर सकते हैं इसके अलावा सरकार ने एक टोल फ्री नम्बर 1551 भी किसानों के लिए उपलब्ध करवाया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों के समय चाहे वह केन्द्र की सरकार रही हो या हरियाणा राज्य की सरकार, उन सरकारों ने किसानों के साथ हमेशा भद्दा मजाक किया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने किसानों के दर्द के आंसू पौंछे हैं। अब मैं अपने हल्के कलायत के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगी। कलायत क्षेत्र पिछले 20-25 सालों से काफी पिछड़ा क्षेत्र रहा है इस दौरान

[श्रीमती गीता भुक्कल]

कलायत हल्के में कभी भी टेल तक पानी नहीं पहुंचा और हमारे पड़ोस का हल्का श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का था लेकिन उन्होंने हमारे हल्के में कभी भी कोई विकास कार्य नहीं करवाया। लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय सिंचाई मंत्री जी के प्रयास से आज कलायत हल्के के हर क्षेत्र में टेल तक पानी पहुंच रहा है। इस समय एस०वाई०एल० कैनाल का निर्माण कार्य अभी पैंडिंग है और हांसी-बुटाना लिंक नहर का कार्य जोर-शोर से चल रहा है। दादुपुर नलवी परियोजना का कार्य प्रगति पर है। पिछले तीन सालों में हमारे सीसर माईनर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और उसमें पानी चल रहा है, बालू सैंडिल और कपिलमुनि माईनर का कार्य प्रगति पर है। अब सब जगह रिपेयर और रिनॉडलिंग का कार्य पूरे जोरों से चल रहा है। अब मैं वाटर सप्लाई और सैनीटेशन के बारे में बात कहना चाहूंगी। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वह हर शहर में और हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। वह स्वच्छ जल और पीने का पानी देने के लिए पूरे प्रयासरत है। पिछले दिनों श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्मदिवस पर 19 नवम्बर को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जीन्द की रैली में इन्दिरा गांधी पेयजल योजना की शुरूआत की थी। इस सदन में इस बात की चर्चा है कि गांवों में जब भी पानी पहुंचाया जाता है तो अनुसूचित जाति के लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाता था। लेकिन हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है कि हरियाणा के गांवों में रहने वाले 8 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को मुफ्त पानी, टैंक और टूटी के लिए प्लेटफार्म दिया जायेगा। इस समय साढ़े तीन लाख परिवारों को मुफ्त पानी के कनैक्शन दे दिये गये हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस समय चारों तरफ वाटर वर्क्स बनाये जा रहे हैं, बुस्टिंग स्टेशन लगाये जा रहे हैं, जहां पानी नहीं पहुंच पाता था वहां पानी पहुंचाने के प्रयास किये जा रहे हैं। आज घर-घर में पानी दे दिया है। पहले हमारी माता-बहनें सिर पर मटका रख कर पानी भरती नजर आती थी। लेकिन आज वे घरों में ही कपड़े धोती नजर आती हैं और घरों में ही भैंसें और गायों को नहलाती नजर आती हैं आज सरकार ने बहुत ज्यादा सुविधाएं दे दी हैं। लेकिन केवल मात्र अगर कुछ डिपार्टमैंट इसमें पंचायती राज, पी०डब्ल्यू०डी० और पब्लिक हैल्थ ये सब विभाग आपस में कोआर्डीनेट करें तो यह काम आसान हो सकता है क्योंकि इस समय विकास कार्य प्रगति पर हैं। हर जगह शीशे की तरह गलियां बन रही हैं। अगर उस समय पाईपलाईन बिछाई जायें और कंसर्न्ड विभाग को इसकी इन्फर्मेशन दे दी जाये तो जो बाद में सरकार के लोसिज होते हैं वे नहीं हो सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार इस समय बिजली के मामले में बहुत चिन्तित है। इस पर बहुत गम्भीरता से कार्य किये जा रहे हैं। वैसे तो सत्ता के लिए लड़ाई हमेशा होती रही है लेकिन ये बिजली की कमी जो है यह पिछली सरकार का करा धरा है। पिछली सरकार के दौरान बिजली की कमी की वजह से लोग धरने देते थे और जलूस निकालने की कोशिश करते थे, ये लोग दुनिया को बहकाते थे लेकिन इनकी सरकार के दौरान कोई भी बिजली का संयंत्र इन्होंने नहीं लगाया। हमारे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने इस समय क्षेत्र में बहुत काम करवाए हैं। 300 मेगावाट के पावर प्लांट से एक नवम्बर 2007 से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। दूसरा 300 मेगावाट के पावर प्लांट से मार्च 2008 के आखिर तक बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ का शिलान्यास डॉ० मनमोहन सिंह ने किया

है और उसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। 1500 मैगावाट का एक कोल बेस्ड पावर प्लांट का झज्जर में शिलान्यास यू०पी०ए० अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पिछले दिनों किया है और उसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। उसके साथ-साथ 1200 मैगावाट का एक पावर प्लांट झज्जर में लगाने का प्रपोजल पैंडिंग है। हमारी सरकार ने जितनी भी पुरानी तारें थी और टूटी हुई तारें थी उनको बदलने की मुहिम चलाई हुई है। गांवों में पहले टूटी हुई तारों की वजह से बहुत से हादसे होते थे। गांवों में जगह-जगह पर जो ट्रांसफार्मर्ज जल गए थे उनको बदलने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। गांव में रहने वाले गरीब लोग और बी०पी०एल० फैमलीज के लिए राजीव गांधी विद्युत परियोजना के तहत मुफ्त कनैक्शन देने का काम जोरों-शोरों से चल रहा है। हर गांव में, हर शहर में नए सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और जो सब-स्टेशंज इस समय हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है और इसका भी निर्माण कार्य जोरों पर है। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनमें पीले बल्ब लगते थे अब हमारी सरकार ने आदेश दिए हैं कि सरकारी दफ्तरों में सी०एफ०एल० लगाए जाएंगें क्योंकि इससे बिजली की खपत कम होती है। गरीबों को ये सी०एफ०एल० के सफेद बल्ब मुफ्त देने का काम जोरों से चल रहा है। अक्षय उर्जा के स्रोतों को बढ़ाने के काम में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। हमारी सरकार ने किसानों का, गरीबों का, बेरोजगारों का, कर्मचारियों का, व्यापारियों का और अनुसूचित जाति और हरेक वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। इस समय इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर रोडस की बात करें तो चारों तरफ हरियाणा में निर्माण कार्य प्रगति पर है। सबसे ज्यादा यह हमारी गवर्नमैंट की प्रायरिटी भी रही है। किसी देश की डिवैल्पमैंट की तस्वीर उसकी सड़कों से नापी जाती है। कोई भी यात्री जब निकलता है तो यदि सड़कें अच्छी होंगी तो अच्छी सरकार का प्रमाण मिलता है। मैं इस समय कहूंगी कि हमारी सरकार ने राजीव गांधी पुल एवं सड़कें आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए गवर्नमैंट आफ इंडिया के वैरियस मंत्रालयों के कोर्डीनेशन से इस समय चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहा है। हमारी सरकार ने सड़कों को चौड़ा करने का काम किया है, कहीं सड़कें 4 लेनिंग की जा रही हैं और कहीं 6 लेनिंग का काम चल रहा है और कहीं नई सड़कों का काम चल रहा है। जगह-जगह नए-नए ब्रिजिज का काम चल रहा है। कलायत जो कि मैं समझती हूं कि पिछले मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का पड़ौसी हल्का रहा है उस समय सड़कों की हालत बहुत बुरी थी, कहीं कहीं गड्डों में सड़कें नजर आती थी। मैं मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करूंगी कि बैकवर्ड एरियाज में उन्होंने नई और अच्छी सड़कें बनाने का काम किया है। इस समय सड़कों के नए-नए जाल बिछाए जा रहे हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं और उनको बधाई देती हूं। सड़कों की कंडीशन अच्छी होगी तो व्यापारी कमर्शियल एक्टीविटीज अच्छी होंगी तो लोगों को रोजगार के साधन मिलते हैं, लेबर के साधन मिलते हैं। इस समय हरियाणा में जितने भी बस स्टैण्डस हैं उनका निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। बस स्टैण्डस के आधुनिकीकरण के कार्य चल रहे हैं। बस स्टैण्डों के साथ-साथ बसों में मुफ्त यात्रा करने का कार्य भी चल रहा है, जो 100 परसैंट हैंडीकैप्ड हैं या नेशनल अवार्डी हैं उनको यह सुविधा दी जा रही है। मैट्रो लिंक का काम दिल्ली-गुड़गांव और दिल्ली बहादुरगढ़ के लिए हमारी सरकार ने किया है ताकि राष्ट्रीय राजधानी से यहां आवागमन

[श्रीमती गीता भुक्कल]

सही तरीके से हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से इण्डस्ट्रीज और लेबर एम्पलाईमैंट की बात करना चाहूंगी। इस समय हरियाणा का वातावरण बहुत ही स्वच्छ, साफ और अच्छा है। बाहर के इण्डस्ट्रियलिस्ट भी आज के दिन हरियाणा प्रदेश में इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं। इसका मेन कारण यही है कि हरियाणा प्रदेश में इण्डस्ट्रीज के लिए अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर है। इस समय हरियाणा में 92 प्रपोजल एस०सी०जैड० के पैंडिंग हैं और IMTs का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। इण्डस्ट्रियल मॉडल टाऊनशिप के अंदर इण्डस्ट्रीज, रैजीडैंशियल कालोनीज, हैल्थ और एजुकेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त लेबर की समस्याओं की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनके बच्चों की एजुकेशन और मनोरंजन की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने पूरी तरह से ट्रांसपियरेंसी लाने के लिए ई-गवर्नैंस का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने न केवल साहूकारों और इण्डस्ट्रियलिस्ट का ध्यान रखा है बल्कि गरीब लोगों का ध्यान रखने के लिए लेबर पॉलिसी बनाई है जिसमें गरीबों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अतिरिक्त गरीब वैलफेयर स्कीम्ज भी बनाई हैं जिनमें गरीबों की सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें तो पता चलता है कि पिछले दिनों जो एक्सीडैंट्स होते थे उनमें भारी मात्रा में कमी आई है। हमारी सरकार ने पिछले तीन साल में बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिये हैं उसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक टूरिज्म की बात है। हरियाणा एक ऐतिहासिक नगरी है। कुरुक्षेत्र को कृष्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। टूरिज्म की तरफ हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। हाल ही में अधिसूचित राज्य पर्यटन नीति 2008 से यह बात साबित होती है। पब्लिक पार्टीशिपेशन के साथ मिलकर टूरिस्ट्स प्लेसिज को डिवैल्प किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बाहर से आने वाले और हरियाणा में रहने वाले टूरिस्ट्स को सुविधा देने के लिए होटल मैनेजमैंट के कोर्सिज की शुरूआत की जा रही है और निजी क्षेत्र के सहयोग से तिलायर झील, रोहतक और बड़खल झील, फरीदाबाद में होटल मैनेजमैंट के कोर्सिज की शुरूआत की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं हमारी सरकार ने उनकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया है। कलायत में कपिल मुनि का मंदिर है वह बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। जो कि हिंदुस्तान में अपने तौर का एक मात्र मंदिर है। उस मंदिर को साज-संवारने का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त चाहे के०डी०पी० के तहत आने वाले जितने भी मंदिर हैं उनको भी साज-संवारने का निर्माण कार्य इस समय चल रहा है। इसके अतिरिक्त चाहे सूरजकुण्ड है, पिंजौर है वहां पर भी पूरी तरह से कार्य चल रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अर्बन डिवैल्पमैंट की बात करना चाहूंगी कि शहरों की तरफ भी हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। शहरों की हालत सुधारने के लिए हमारी सरकार विशेष सहायता दे रही है और म्यूनिसिपल कमेटीज की हालत सुधारने के लिए बहुत अच्छे फैसले लिये जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत फरीदाबाद शहर को करोड़ों रुपये दिये जा चुके हैं। इसके साथ-साथ अब पंचकूला को भी चण्डीगढ़ और मोहाली के साथ-साथ चलते हुए त्रिनगरीय महाबस्ती या ट्राई सिटी के एक भाग के रूप में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी

सरकार न केवल शहरों में रहने वाले अमीर और अच्छे लोगों की तरफ ध्यान दे रही है बल्कि शहरों में रहने वाले गरीबों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है। शहरों में रहने वाले गरीबों के प्रति भी हमारी सरकार पूरी तरह से चिंतित है और समेकित आवासन तथा मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 शहरों में 238.84 करोड़ रुपये की लागत की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार से अनुमोदित हो चुकी है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं। इसके अतिरिक्त एल०ए०डी०टी० स्कीम के तहत भी शहरों को पैसा दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे हमारे केन्द्र की सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार है इनको शहरों में रहने वाले गरीब भाईयों की बहुत चिंता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब भाईयों के लिए आशियाना योजना कार्यान्वित की है। जिसके तहत चार मंजली मकान हुडा द्वारा बनाये जाएंगे और गरीब लोगों को दिए जाएंगे। इस समय 2072 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पंचकूला में युद्धस्तर पर चल रहा है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले भाईयों के लिए आवास बोर्ड, हरियाणा ने आगामी तीन वर्षों के दौरान 50000 मकानों का निर्माण करने के लिए भूमि की व्यवस्था के लिए कदम उठाएं हैं। उसके लिए हाऊसिंग बोर्ड के तहत मकान बनाने का कार्य इस समय प्रगति पर है और इसमें यह बहुत खुशी की बात है कि विशेष तौर से महिलाओं का हमारी सरकार ने हमेशा ही ध्यान रखा है। इसमें 33 प्रतिशत कोटा महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने न केवल शहरों की तरफ ध्यान दिया है बल्कि गांवों में भी रहने वाले जो हमारे किसान और गरीब भाई हैं और हमारे जो गांव हैं क्योंकि अधिकतर हमारा हिन्दुस्तान और विशेष तौर पर हरियाणा गांवों में ही बसता है और हमारी सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर गांवों में भी शहरों जैसी सुविधायें उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। हरियाणा रूरल डैवेल्पमैंट अथॉरिटी का गठन किया गया है जिस तरह से शहरों के विकास के लिए हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी है उसी तरह से हरियाणा में गांवों के सम्पूर्ण विकास के लिए हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट अथॉरिटी बनाई गई है ताकि गांवों में भी शहरों जैसी सुविधायें दी जा सकें और पंचायती राज को मजबूत किया जा सके और जो हमारी सामाजिक उत्थान की नीतियां हैं वे वहां पर पूरी तरह से लागू हो सकें। हमारे गांवों में रहने वाला हरेक व्यक्ति अपने आपको सरकार का हिस्सा समझ सके, उसे यह लगे कि सरकार में अच्छी प्रकार से हिस्सेदारी है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विशेष तौर से ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया है। स्वर्ण जयन्ती स्वयं रोजगार योजना के तहत स्वयं सहायता समूह गांव-गांव में बन गये हैं जिन्होंने इक्ट्ठे होकर चाहे उनकी क्रेडिट की फैसिलिटी हो, मार्केटिंग की हो, टैक्नीक्स की हो सभी पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। इस पर इस समय हमारे सैल्फ हैल्प ग्रुप्स बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। नेशनल रूरल इम्पलायमैंट गारंटी स्कीम के तहत जो पहले कुछ जिलों में भी हरियाणा में सिरसा और महेन्द्रगढ़ में थी लेकिन हमारे महामंत्री श्री राहुल गांधी जी के प्रयासों से इस नेशनल रूरल इम्पलायमैंट गारंटी स्कीम को पूरे हिन्दुस्तान के सभी जिलों में पूरी तरह से लागू किया जायेगा। अब अम्बाला और मेवात में भी इस पर काम शुरू किया जा चुका है जिसमें कि 365 दिन में से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे बेरोजगार भाई और बहनें जिनको रोजी रोटी की चिंता है उनको साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार हम

[श्रीमती गीता भुक्कल]

सुनिश्चित कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के बहुत से ऐतिहासिक फैसले हैं जो हमारी केन्द्र और हरियाणा सरकार ने गरीबों के सम्पूर्ण उत्थान हेतु लिये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 दिसम्बर, 2007 को दलित समान रैली में मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति ग्रामीण उत्थान योजना और मलिन बस्ती विकास योजना की घोषणा की थी उसके तहत किसी भी गांव में जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या होगी वहां पर हमारी सरकार की तरफ से 50 लाख रुपये दिये जायें ताकि उनके रहने की कंडीशन्ज को सुधारा जा सके। पूरी तरह से पीने के पानी का उसमें प्रावधान किया जायेगा। हमारी सरकार ने पिछले दिनों जब झाड़ली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी आई थी तब यह घोषणा की थी क्योंकि गरीबों के लिए उनके दिल में बहुत दर्द है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से यही नारा रहा है कि कांग्रेस का हाथ गरीब आदमी के साथ। हमारी सरकार 36 बिरादरी की सरकार है लेकिन विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी में गरीबों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100-100 गज के प्लाट देने की जो ऐतिहासिक घोषणा की है उससे हरियाणा में रहने वाले हरेक गरीब आदमी में बहुत ही खुशी की लहर है कि उसको रहने का ठिकाना दिया जायेगा। इससे पहले हमारी राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी अपने समय में प्लाट दिए थे। हमारा जो गरीब समाज है वह हमेशा कांग्रेस पार्टी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी रहेगा। न केवल ये 100-100 गज के प्लाट दिये जायेंगे बल्कि इनको पूरी तरह से डिवैल्प भी किया जायेगा। उसमें पीने के पानी की सुविधा, लाईट की सुविधा, गलियां और इस तरह से इनको पूरी तरह से तैयार करके गरीबों को यथाशीघ्र देने की प्रक्रिया इस समय चल रही है। गांवों में रहने वाले जो हमारे गरीब भाई हैं उनका भी चूल्हा टैक्स माफ करने की घोषणा हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने की जिसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि जब हमारे राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण दे रहे थे तो हमारे सभी साथियों ने उनका जोरदार स्वागत अपनी मेजे थपथपाकर किया था क्योंकि राज्यपाल महोदय ने हमारी सरकार की तारीफ की और मुख्यमंत्री महोदय की पीठ थपथपाई क्योंकि हमने बहुत से अभूतपूर्व ऐतिहासिक फैसले लिए हैं कि गांवों की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। न केवल शहरों की म्यूनिसिपल कमेटीज में बल्कि गांवों में भी हर जगह पर सफाई कर्मचारी लगायें जायें। 11 हजार सफाई कर्मचारियों को लगाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की जो कि एक ऐतिहासिक फैसला है। इसके अनुसार जिस गांव में 2 हजार व्यक्ति होंगे वहां पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जायेगा और जहां पर 4 हजार व्यक्ति होंगे वहां पर 2 सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जाऐंगे उससे ज्यादा में 3 सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाऐंगे और इसी तरह से गांवों की सफाई और स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारी सरकार ने गन्दगी से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनके फैलने के कारणों को होर्डिंग और स्लोगन लगा कर लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार ने गांवों में सफाई की समुचित व्यवस्था की है। उपाध्यक्ष महोदय, जिन प्रान्तों में दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं वहां भी हमारे कामों की प्रशंसा होती है और हमारे कामों का अनुसरण किया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने भी हरियाणा में हुए कार्यों

की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जहां दूसरी पार्टी की सरकार है वहां पर भी हमारे यहां जो लाडली स्कीम है उसी के तहत घोषणा की गई है और रक्षाबन्धन पर हमारे यहां महिलाओं के लिए बसों में जो मुफ्त यात्रा की सुविधा है उसी प्रकार उन्होंने भी मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है। इसी प्रकार से करवा चौथ पर भी अवकाश की घोषणा की है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल ये ही राज्य नहीं बल्कि देश के सभी राज्य हरियाणा का अनुसरण कर रहे हैं। गांवों में महिला होने के नाते इस समस्या को हम बहुत ही गम्भीरता से लेते हैं। महिलाओं के लिए शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी सरकार ने भारत सरकार की मदद से पहले जो मात्र 600 रुपये दिये जाते थे उसको बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। गांवों में शौचालयों के निर्माण के लिए पूरी तरह से कार्य चल रहा है ताकि उनको गन्दगी से मुक्ति मिल जाये। महिलाओं का मान सम्मान पूरी तरह से बरकरार रखा जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारी सरकार ने वर्ष 2007 को बालिका वर्ष घोषित किया था और बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सी घोषणाएं न केवल कागजों पर की बल्कि उनको अमलीजामा भी पहनाया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि वर्ष 2008 को शिक्षा वर्ष घोषित किया गया है क्योंकि आजादी के तकरीबन 60 वर्ष के बाद भी आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा हरियाणा कुछ हद तक पिछड़ा रहा लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को शिक्षा वर्ष घोषित करके इस चिन्ता को दूर करने का प्रयास किया है। आज ड्रॉप-आऊट की जो समस्या है एलीमैंट्री एजुकेशन की जो समस्या है वह बरकरार है। पिछली सरकार ने कभी भी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया। विशेषकर लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने पहली से आठवीं तक के सभी बच्चों को कॉपियां किताबें और वर्दियां देने का काम किया है। जो बच्चियां दूर के गांवों से आती हैं उनको मुफ्त में साईकिलें देने का कार्य किया है। मिड-डे-मील के रूप में स्कूलों में खाना देने का काम हमारी सरकार कर रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत जो भी बच्चे दसवीं में 60 प्रतिशत अंक लेकर पास होते हैं उनको हमारी सरकार छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि देती है। मुख्यमंत्री शैड्यूल कास्ट उत्थान योजना जो कि मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में घोषित की है, एक ऐतिहासिक घोषणा है। अगर हम देखें कि हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं। आज उच्च शिक्षा तो केवल वे ही बच्चे ले पाते हैं जो दूसरी और तीसरी की सीढ़ियां पार करते हुए ऊपर तक जाते हैं। ड्रॉप-आऊट की समस्या बहुत ही गम्भीर समस्या थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंथली छात्रवृत्ति की जो घोषणा की है यह एक ऐतिहासिक कदम है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ रही अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए 150 रुपये से 400 रुपये मंथली छात्रवृत्ति दी जाएगी और लड़कों को 100 रुपये से 300 रुपये तक मंथली छात्रवृत्ति दी जाएगी। अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए इन सभी योजनाओं पर प्रतिवर्ष 280 करोड़ रुपये का खर्च हमारी सरकार वहन करेगी। पिछली सरकार की लिस्ट उठाकर देखें तो पता लगेगा कि पिछली सरकार ने स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया गया था। इस समय शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और हमारे बहुत से स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। मॉडल स्कूल बनाये जा रहे हैं।

[श्रीमती गीता भुक्कल]

कम्प्यूटर दिये जा रहे हैं और कम्प्यूटर की शिक्षा पूरी तरह से दी जा रही है तथा एजूसैट प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। पूरे प्रयास किये जा रहे हैं कि कोई भी बच्चा स्कूल जाए बगैर न रहे। ऐसा करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि हमारी सरकार की तरफ से दी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि न केवल स्कूल शिक्षा की ओर बल्कि टैक्नीकल शिक्षा की ओर भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। टैक्नीकल के मामले में जगह-जगह पर पॉलीटैक्नीक खुल गये हैं। आई०टी०आई०ज० खुल गई हैं ताकि हम एक ट्रेंड मैनपॉवर दे सकें। हमारे बच्चे ट्रेनिंग लेकर इंडस्ट्री में काम कर सकें। इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हमारी सरकार ने की है। विमैन ट्रेनिंग के लिए विशेषतौर पर हमारी सरकार की प्रॉयोरिटी रही है और महिलाओं की शिक्षा के तहत महिलाओं के लिए अलग से 25% सीटें रिजर्व की गई हैं। 31 आई०टी०आईज़० खोलने के लिए काम चल रहा है जिनमें केवल महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बात करूं तो हमारी सरकार ने न केवल सड़क, कृषि, सिंचाई पर ध्यान दिया है बल्कि शिक्षा की तरफ भी पूरा ध्यान दिया है। शिक्षा के साथ ही साथ हमारी सरकार ने खेलों की तरफ भी पूरा ध्यान दिया है। जैसे कि सभी को यह मालूम है कि हमारे गांवों में सभी जगहों पर रूरल स्टेडियम बनाए गए हैं और गांवों में खेलों की सुविधा दी गई है। जिन साथियों ने खेलों में मैडल जीते हैं हमारी सरकार ने उन साथियों के गांवों को आदर्श गांव बनाने की घोषणा करके सभी खिलाड़ियों को पूरा मान-सम्मान दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की भर्तियों में खिलाड़ियों के लिए पद आरक्षित करने का प्रावधान किया है। अगर मैं खिलाड़ियों की डॉयट की बात करूं तो खिलाड़ियों को जो डायट दी जाती है उसमें भी हमारा हरियाणा प्रदेश हिन्दुस्तान में नम्बर वन पर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही सोशल वैल्फेयर स्कीम की यहां पर चर्चा करना चाहूंगी। एजुकेशन के साथ ही साथ सोशल वैल्फेयर भी जरूरी है क्योंकि हमारे संविधान में वैल्फेयर स्टेट की बात कही है। वैल्फेयर स्टेट के लिए हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिये हैं और कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। न केवल सोशल वैल्फेयर बल्कि हैल्थ के बारे में भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किये हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और विजनरी के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे इस सरकार की स्कीमों से लाभ न मिला हो। चाहे वह गांव में रहने वाला छोटे-से छोटा व्यक्ति हो और चाहे शहर में रहने वाला बड़े से बड़ा व्यक्ति हो उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड रियैलिटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और अपनी सरकार को उसी के आधार पर चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे राज्यों की सरकारें भी हमारी सरकार का अनुसरण कर रही हैं हमारे गांवों में विलेज लैवल की कमेटियां बनाई गई हैं और गांवों में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाएं और हमारी बच्चियां गांवों में मिल बैठ कर सरकार की नीतियों पर चर्चा करती हैं। इस समय तकरीबन 6500 वी०एल०सी०सी० अच्छी प्रकार से कार्य कर रही हैं। यह डैलिगेशन ऑफ पॉवर की बात है। गरीब महिला के हाथ में भी जब पावर आती है तो उसका हौंसला बढ़ता है और वह स्वयं काम करती है। इस समय स्वयं

सहायता समूह गांवों में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं इनमें भी हमारी महिलाएं और पढ़ी लिखी बच्चियां कार्य कर रही हैं। वहां पर अवेयरनैस प्रोग्राम्ज चलाए जा रहे हैं। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वह उन तक तथा जन-जन तक पहुंचाई जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने मैल न्यूट्रीशन को खत्म करने के लिए न्यूट्रीशन डॉयट की दर बच्चे के लिए दो रुपए से बढ़ाकर तीन रुपए की है और महिलाओं के लिए अढ़ाई से बढ़ाकर पांच रुपए की है। हमारे समाज में चाहे विधवाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, हैंडीकैप की बात हो, चाहे बौनों की बात हो, कोई भी समाज का ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसको हमारी सरकार ने पैंशन न दी हो। शैडयूल्ड कास्ट सब-प्लॉन हरियाणा में लागू किया गया है, यह भी बहुत अच्छा कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, शैडयूल्ड कास्ट लोगों के लिए जो पैसा आता है वह अलग से लगा हुआ दिखाई देना चाहिए। हमारी सरकार ने जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके विकास के लिए न केवल सामाजिक बल्कि उनके आर्थिक उत्थान के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुफ्त में खाना, मुफ्त में वर्दी, पहनने के लिए कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें और चलने के लिए गाड़ियां सब कुछ हमारी सरकार ने दिया है। लोगों को कम्प्यूटर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कम्प्यूटर ट्रेनिंग के बाद मुफ्त में कम्प्यूटर देने की भी घोषणा हमारी सरकार ने की हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी शगुन योजना के तहत जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए 15000 रुपये की राशि उनके विवाह के समय हमारी सरकार देती है। जैसे कि मैंने जिक्र किया रक्षा बन्धन के मौके पर हमारी बहुत सी बहनें अपने भाईयों को राखी बांधने से वंचित रह जाती थीं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक ऐसी घोषणा की जो आज तक हिन्दुस्तान में कहीं पर भी नहीं हुई। राखी के दिन अपने 15 वर्ष के बच्चे के साथ जो बहनें हैं वे अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बस में मुफ्त आ जा सकती हैं। इसके अलावा अगर बिजली का मीटर महिला के नाम पर है तो 10 पैसे पर-यूनिट उसको सस्ती बिजली मिलेगी। अगर महिला के नाम से रजिस्ट्री होती है तो स्टाम्प ड्यूटी में भी उसको छूट मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जो टीचर्ज की भर्ती होने जा रही है उसमें भी 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। गांवों की महिलाओं के लिए चौपालों का भी प्रावधान किया है। हमारे गांवों में बहुत से आंगनवाड़ी सैंटर खोले जा रहे हैं और उनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं सैक्स रेशो की बात करूं तो यह जो लिंग अनुपात में फर्क आ गया था उसको कम करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने जगह-जगह पर सैमिनार्ज का आयोजन किया है और इन सैमिनार्ज की वजह से लोगों में बहुत जागरुकता आई है। इसी तरह से हमारी सरकार ने लाडली स्कीम के तहत लड़की के नाम पर या उसके मां-बाप के नाम पर बैंकों में 5000 रुपये जमा करवाने का काम किया है। नौकरियों में जो महिलाओं का बैकलॉग था उसको भी पूरा करने का काम यह सरकार कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मैडम जी, आप वाईंड-अप करें।

श्रीमती गीता भुक्कल : सर, मैं पांच मिनट और लूंगी। हमारी सरकार ने तीन साल में बहुत से अच्छे कार्य किए हैं और बहुत सी अच्छी योजनाएं शुरू की हैं उनके बारे में

[श्रीमती गीता भुक्कल]

बोलने के लिए थोड़ा समय और चाहिए। सरकार द्वारा किए सभी कामों के बारे में सदन की छोटी सी कार्यवाही में बोलना मुश्किल है लेकिन मैं कुछ बातें यहां पर जरूर करना चाहूंगी। हमारी सरकार ने अम्बेडकर भवनों के लिए जगह-जगह प्लॉट देने का काम किया है। मैं स्वास्थ्य के बारे में बातें कहना चाहूंगी। नैशनल रूरल हैल्थ प्रोग्राम के तहत हमारी सरकार गांवों के लोगों की सेहत का ध्यान रखने का काम कर रही है। जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सहायता राशि दी जा रही है। स्कूलों में जो बच्चे अनिमिक हैं उनको आर०एन० टैब्लेट्स बंटवाई गई हैं। जो बच्चे पेट में कीड़े होने की वजह से दिक्कत में रहते थे उनको एम्पोजोल दवाई पिलाई गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हरियाणा में चलाई गई है जिसमें बी०पी०एल० फैमलीज को कवर किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं और इस सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और इस सरकार को बधाई देना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री धर्मबीर गाबा (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, 7 मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है इस बारे में मैं यह समझता हूं कि यह सरकार के आने वाले साल के कार्यक्रमों का, पॉलिसियों का और डिवैल्पमैंट का एक अक्ष है, आईना है। सरकार की आने वाले साल की सारी पॉलिसियां गवर्नर एड्रैस में होती हैं। अगर हम यह कहें कि यह एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें कई किस्म के फूल हैं और इन फूलों में सभी फूल अच्छे हैं क्योंकि सभी फूलों की अपनी-अपनी खुशबू होती है इसी तरह से इस एड्रैस में हर पॉलिसी अच्छी है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं दिल्ली में हुई धन्यवाद रैली का जिक्र करना चाहूंगा। वहां पर बहुत कुछ कहा गया और हमने भी बहुत कुछ कहा। वहां पर लोग बहुत ज्यादा तादाद में आए थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो 60 हजार करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए हैं, लेकिन पॉलिसी में यह कहीं नहीं बताया गया कि आईंदा किसान कर्ज में नहीं दबेगा। किसान के कर्ज में न दबने का कोई भी उपाय नहीं बताया गया है। क्या ऐसी पोलिसीज हैं कि किसान दोबारा इस तरह के कर्ज के अंदर नहीं फंसेगा, क्या उसके प्रोडक्शन की इतनी कीमत मिलेगी जिससे किसान को कर्ज लेने की जरूरत ही न पड़े? सर, जब बिजाई या कटाई नहीं होती तो क्या उसको दोबारा से रोजगार दिया जाएगा जिससे वह दोबारा कर्ज में न फंसे? सर, यह हरियाणा गवर्नमैंट का काम है कि वह इन सारी बातों को भी देखें क्योंकि हरियाणा सबसे ज्यादा कृषि प्रधान स्टेट है। हरियाणा सरकार को सोचना ही होगा कि हमें इस बारे में क्या-क्या उपाए करने चाहिएं ताकि किसान दोबारा से कर्ज में न फंसे। सर, मैं फाईनैंस मिनिस्टर साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जो यह 6650 करोड़ रुपए की वार्षिक प्लॉन प्लानिंग कमीशन से मंजूर हुआ है यह मैं समझता हूं कि बेस्ट फाईनैंशियल मैनेजमैंट की वजह के हुआ है। आज हमें प्लॉनिंग कमीशन से कहीं ज्यादा पैसा मिला है अगर इस पैसे को अच्छे ढंग से खर्च किया जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यदि यही पॉलिसीज चलती रहीं तो हो सकता है कि हमें और भी ज्यादा पैसा

अगले साल में प्लॉनिंग कमीशन से मिल जाए। डिप्टी स्पीकर सर, अभिभाषण में बहुत सारी बातें कही गयी हैं। इसमें सबसे पहले ऐग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं भी पिछले बीस सालों में चौथी बार मैम्बर बनकर आया हूं। एक प्रोग्राम था कि राई के अंदर फल-फूल की एक बहुत बड़ी मार्किट खोली जाएगी मुझे खुशी है कि अब शायद यह गन्नौर में खोलने जा रहे हैं। जो यह फल फूल की मार्किट खोलना चाहते हैं वह हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छी होगी। अभी तो तकरीबन फल फूल हिमाचल से या कश्मीर से आकर दिल्ली जाता है और फिर सूखने के लिए सोनीपत, पानीपत और गन्नौर आता है। अगर यह मार्किट खोली जाती है तो मैं समझता हूं कि यह हरियाणा की हिन्दुस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी क्योंकि एक तो पोल्यूशन से बचकर पोल्यूशन फ्री हो जाते हैं और दूसरे ट्रैफिक हैजर्ड नहीं रहेगी और साथ ही लोगों को सस्ता माल भी मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इसको उतनी ही जल्दी बना देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, पिछले दस सालों से हमने देखा है क्योंकि एक बार मैं स्वयं भी वहां पर जाकर देखकर आया था। वहां पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक भी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। हम इस सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वह इस काम को जल्दी ही टेकअप करेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे एक बात की और खुशी है और मैंने पिछले साल भी सी०एम० साहब से कहा था कि मुझे और कोई खुशी हो या न हो लेकिन इस बात की जरूर खुशी है कि हमारे सी०एम० साहब पहले ऐसे सी०एम० हैं जिन्होंने पानी का इक्विल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। डिप्टी स्पीकर सर, आप भी और मैं भी उसी इलाके से बिलोंग करते हैं जिस इलाके में पानी बिल्कुल नहीं मिलता लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि जो अभिभाषण में इस बारे में जिक्र किया गया है और मंत्री जी का भी बयान है कि हमें इस बारे में बहुत बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिलने वाली है। यह बात सही भी है कि गुड़गांव के लोगों को राहत मिली भी है। डिप्टी स्पीकर सर, आप भी उस इलाके के रहने वाले हैं इसलिए आपको भी पता है। पहले गुड़गांव से दिल्ली आने जाने में डेढ़ घंटा लग जाता था लेकिन आज सुपर एक्सप्रेस-हाई-वे बन जाने के बाद सिर्फ 20-22 मिनट ही लगते हैं। यह सरकार की हमारे लोगों को बहुत बड़ी देन है। मैं कैप्टन साहब के नोटिस में एक बात जरूर लाना चाहता हूं। अभिभाषण में भी इस बात का जिक्र है कि पानीपत में जो फ्लाई ओवर बन रहा है यह जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। अखबारों में भी मंत्री जी का बयान आया था कि फरवरी में इसको चालू कर दिया जाएगा। अगर फरवरी में नहीं तो मार्च तक इसको जरूर चालू कर देंगे। लेकिन समालखा और गन्नौर के फ्लाई ओवर का अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है क्या ये भी पूरा होंगे या नहीं। मंत्री जी ने कभी भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया है। मेहरबानी करके इन्हें भी आप पूरा कर दीजिए ताकि उस रास्ते पर यदि हम चलें तो रास्ते में कहीं पर भी दिक्कत न हो। मैं मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि जो आपने कुण्डली, मानेसर, पलवल की यह स्कीम निकाली है। वह हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए इतनी बड़ी देन होगी कि आज तक कोई सरकार ऐसी देन नहीं दे पाई होगी। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की होगी कि वह इंडस्ट्रियल कॉम्पलैक्स हो जाएगा। एक और मेहरबानी कर दें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा कि नेशनल हाइ-वे पर ढाबे और पैट्रोल पंप नहीं होने चाहिएं। यह हाइ-वे से आधा

[श्री धर्मवीर गाबा]

किलोमीटर अंदर होने चाहिएं ताकि लोगों को रुकावट न हो। ए०सी० चौधरी साहब यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण के अंदर जिक्र आया है कि सरकार म्यूनिसिपल डिवैल्पमैंट के लिए बहुत कुछ कर रही है इसके लिए हमें एन०सी०आर० से भी बहुत पैसा मिल रहा है। जिक्र यह भी है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गुड़गांव में सैटअप करने जा रहे हैं। जब मैं इस विभाग का मंत्री था तो मैंने भी इस बारे में प्रपोजल दी थी। चौधरी साहब मैं आपसे भी यही रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि आज यह गुड़गांव की ही नहीं, बल्कि अम्बाला सिटी और अम्बाला कैन्ट की भी जरूरत है, जगाधरी और यमुनानगर की भी जरूरत है और हिसार, रोहतक व करनाल की भी जरूरत है। जो म्यूनिसिपल काउंसिल गुड़गांव है उसका आज 18 किलोमीटर का दायरा है और जो प्रपोजल आपने भेजी है उससे उसका एरिया 370 किलोमीटर का हो जाएगा। शहरीकरण में जो गांव आ चुके हैं या आने वाले हैं उनको यदि हम उस हिसाब से पहले ही डिवैल्प कर देंगे तो यह बहुत अच्छी बात होगी। 1911 में म्यूनिसिपल एक्ट बना था उसके बाद वर्ष 1971 में हरियाणा का एक्ट बना। 1963 में हमसे सबसे बड़ी गलती यह हुई कि म्युनिसिपल कार्पोरेशन व म्युनिसिपल काउंसिल और कमेटीज तो बन गई लेकिन उसमें यह शर्त रख दी कि 5 किलोमीटर के बाद प्लानिंग डिपार्टमैंट उसको सैंक्शन करेगा। हदें बढ़ गई लेकिन कंट्रोल्ड एरिया वही रहे। आज कमेटीज को कोई पॉवर नहीं है। सिर्फ यही पॉवर है कि वेट एंड रिजल्ट। जो कालोनीज 1952 के अन्दर रीसैटलमैंट के वक्त बनी थी, उस वक्त उनकी जरूरत नहीं थी लेकिन आज उनकी जरूरत है। उनके बारे में कौन निर्णय करेगा यह आज तक कोई पता नहीं है। आप इसको काउंसिल तक महदूद रखें या कॉर्पोरेशन तक महदूद रखें। दलाल साहब यहां बैठे हैं ये भी इस बारे में कुछ सुझाव दें। मैं तो चौधरी साहब से भी इस बारे में अर्ज करूंगा कि प्लॉनिंग डिपार्टमैंट वालों ने तमाशा कर रखा है वह यह है कि 500 गज तक के प्लाट का नक्शा तो कमेटी पास करेगी और उससे ऊपर का चंडीगढ़ में पास होगा। चंडीगढ़ नक्शा आएगा तो वह दो साल में पास होगा। हमारे यहां गुड़गांव में एक मॉल बन रहा है। वह 1600 गज एरिया में बन रहा है उसकी जब खुदाई की गई तो उसके आस-पास की 4-4, 5-5 मंजिली जो बिल्डिंग्स थीं, वे हिल गईं। पीड़ित लोग मुझसे मिलने आए और कहने लगे कि हमारे मकान गिरते जा रहे हैं इसलिए इस मॉल को बनने से रोको। जब कमेटी वालों को मैंने कहा तो वे कहने लगे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका नक्शा चंडीगढ़ से पास हुआ है इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दलाल साहब गुड़गांव में ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की मीटिंग में आये थे। मैंने उनसे बात की थी और कहा था कि जब तक आप पावर्ज को डीसैंट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। म्युनिसिपल कार्पोरेशन में आपने डी०सी० के स्तर के अधिकारी या दूसरे अधिकारी बैठा रखे हैं वे भी उतने ही कैलीबर के हैं जितने कि चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं तो वे यह काम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये काम वहीं होने दें ताकि लोगों को इस गलत रास्ते से बचाया जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सरकार जो कुछ करे वह देख कर करे। इस पॉवर को वापिस करे ताकि म्युनिसिपल कांउसिल और म्युनिसिपल कार्पोरेशन का जो कण्ट्रोल है वह उसकी हद जहां खत्म होती है उसके पांच किलोमीटर बाद तक उसका कंट्रोल होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि चण्डीगढ़ में बैठकर प्लानिंग कंट्रोल करें। क्योंकि

कमेटी या कार्पोरेशन की हद तो बढ़ जाती है लेकिन उसका कंट्रोल एरिया नहीं बढ़ता। जबकि इसके एक्ट में यह साफ प्रोविजन है कि हद बढ़ाने के साथ-साथ कंट्रोल एरिया भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद हम खुश हो जाते हैं कि अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए इतना पैसा मिल रहा है। एजुकेशन के लिए इतना पैसा मिल रहा है। मुझे खुशी है कि ऐजुकेशन के लिए इतना पैसा मिल रहा है लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि हमारे यहां पर ज्यादातर टैक्नीकल ऐजुकेशन पर जोर दिया गया है। इस बारे में मेरा सुजैशन यह है कि टैक्नीकल ऐजुकेशन की वहां पर जरूरत है जहां पर इण्डस्ट्रियल सिटी हैं जिनको हम इण्टरनेशनल सिटी बनाने जा रहे हैं। जैसे इण्डस्ट्रियल टाऊन फरीदाबाद है, गुड़गांव है, बहादुरगढ़ है और कुण्डली है। मैं समझता हूं कि टैक्नीकल ऐजुकेशन की इन सैंटर्ज में जरूरत है ताकि हम इण्डस्ट्रियलिस्ट्स से गाईडैंस लेकर सलाह करके कन्सल्ट कर सकें कि उनको कितने लड़कों की जरूरत है ताकि उतने लड़कों को सही ट्रेनिंग दी जा सके। इस सैक्टर में यह प्रिफैंस की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसको अगर हम ठीक ढंग से खर्च करें तो वह ठीक जगह पहुंच सकता है। यह तो एक हमारा मिशन है। हकीकत में तो हमारा यह मिशन तब कामयाब होगा जब हम डिवैल्पमैंट करें तो इसके लिए सोच समझकर खर्च करें।

श्री उपाध्यक्ष : गाबा साहब, वाईड-अप करें। आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं।

श्री धर्मबीर गाबा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं। वर्ष 1992-93 में मैंने कुछ कालोनियां रेगुलराइज की थी जो फरीदाबाद, रेवाड़ी और गुड़गांव की कालोनियां थी और उस समय 32-32 कालोनियां रेगुलराईज की गई थी। लेकिन प्लानिंग कमीशन उनको मानने को तैयार नहीं है। अब वे लोग कहते हैं कि हम कहां जायें यह तो एक तमाशा बन कर रह गया है। ये जो दिक्कतें हो रही हैं मेहरबानी करके आप ठीक ढंग से इन कालोनियों को रेगुलराइज करें। मैं एक बात कहता हूं जो सबसे उचित है। आज आप अर्बन डिवैल्पमैंट बनाने जा रहे हैं। क्या हो रहा है आप रेगुलराइज नहीं करते और प्लानिंग को भेज देते हैं। नक्शा पास नहीं होता कमेटी वाले लोगों से कहते हैं कि इंतजार करो। इसी दौरान और झुग्गी झोपड़ियां बढ़ जाती हैं। आज मैं समझता हूं कि सरकार 20 हजार के करीब फलैट्स बनाने जा रही है। उससे अन-अथोराईज्ड कालोनियां हैं वे रेगुलराईज हो सकेंगी। यह एक बहुत बड़ा क्वैश्चन है। हरियाणा में अर्बन डिवैल्पमैंट की तर्ज पर हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट एथोरिटी बनाने जा रहे हैं। मेरा सुजैशन यह है कि आज गांव के अन्दर कोई भी मकान 500 गज से कम नहीं है। क्योंकि उसको भैंस बांधने के लिए जगह चाहिए, उसको तूड़े के लिए जगह चाहिए, घास के लिए जगह चाहिए। क्या अर्बन डिवैल्पमैंट वाले उनको इतनी जगह दे पायेंगे। क्या उनकी जरूरत के मुताबिक ये घर बनाऐंगे या शहर की तरह दड़बे बन जाऐंगे। यदि आप गांव की डिवैल्पमैंट चाहते हैं तो खास तौर से गांव की जरूरत को आपको ध्यान में रखना होगा। यह सही है कि रूरल अर्बन डिवैल्पमैंट के द्वारा लोगों के घर तरकीब से बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। आप सीवरेज की, ड्रेनेज की, पानी की, बिजली की, नालियों की और सड़कों की फैसीलिटीज दे पाएंगें। मैं इस बात को मानता हूं कि गांवों की सड़कें टूट जाती

12.00 बजे

[श्री धर्मबीर गाबा]

हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज नहीं हो पाता और आप ये सुविधाएं दे पाएंगे और मैं समझता हूं कि इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मैं एक बात पर मुख्यमंत्री महोदय की दाद देता हूं मैंने उनको कहा कि आपकी एक्साइज पोलिसी मुझे बहुत अच्छी लगी है, आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आफ वाटर की पोलिसी भी मुझे बहुत अच्छी लगी है इसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। तीसरी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वह है एजुकेशन सिटी। आज हम बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं तो कोई अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मकान बेचता है कोई जेवर बेचता है और सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बन जाएं। अगर इसके लिए यहां प्रोविजन है या आप प्रोविजन कर देंगे तो हरियाणा पर ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान पर इस गवर्नमैंट का बहुत बड़ा अहसान होगा। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनने जा रही है मुझे यह एजुकेशन सिटी का आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा है मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं इसलिए मैंने मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वैस्ट की कि हमें इसकी ब्रांच खोलने के लिए इजाजत दी जाए और अब हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यह काम हो जाए। एजुकेशन सिटी का यह प्रोग्राम सरकार का बहुत नेक कदम है इसका कभी मुकाबला नहीं हो सकता। इस बारे में आज नहीं बल्कि आने वाले समय में जनता बताएगी कि हरियाणा सरकार ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। आज मैं मुख्यमंत्री की एक बात के लिए और दाद देता हूं कि इन्होंने कभी कुछ नहीं छिपाया, मैंने 16 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय को कहा कि आप लोगों को कह रहे हैं कि बिजली का हम सारा बंदोबस्त कर रहे हैं, आज तक किसी गवर्नमैंट ने ऐसे काम नहीं किए। 10 अप्रैल को तो नई सरकार आ जाएगी और फरवरी में इलैक्शन हो जाएंगे तो हम कैसे कह पाएंगे तो कहने लगे कि मैं झूठ नहीं बोलता। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की शराफत है कि जो असलियत है उसको कहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते। आज एफ०एम० जी बैठें हैं उन्होंने बिजली के लिए बहुत पैसा दिया है। मुझे खुशी होती है मैं इनसे एक बार बात कर रहा था तो ये कहने लगे बिजली के लिए जितना पैसा मांगो हम देने के लिए तैयार हैं ताकि गुड़गांव में बिजली आनी चाहिए, सारे हरियाणा में बिजली आनी चाहिए। यदि इंडस्ट्रीज को 4 घंटे बिजली मिलती है तो इंडस्ट्रीज कैसे पनपेगी, कैसे लेबर को तनख्वाह दे पाएंगे और कैसे और कुछ कर पाएंगे। वित्त मंत्री महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जो प्रूवडैंट फिजीकल मैनेजमैंट है उसका आपको 25 परसैंट ज्यादा पैसा मिला है, मैं समझता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगले साल इससे भी ज्यादा पैसा मिले ताकि लोगों की भलाई के लिए आप कुछ काम कर सकें। मैं इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राज्यपाल महोदय ने जो 7 मार्च 2008 को अभिभाषण दिया है उसका अनुमोदन करती हूं। मैं हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा जी को बधाई देती हूं कि जिन्होंने किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ करने का काम किया। पिछले साल जो 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल किसानों के माफ किए गए उसके लिए भी मैं उनको बधाई देती हूं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए और उनकी भलाई की जाए क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो

पूरा देश खुशहाल होगा। वे धूप में, ठण्ड में और बरसात में हमारे लिए गेहूं, चावल और सब्जियां उगाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों को देश में सबसे ज्यादा भाव गेहूं, जीरी और गन्ने का दिया है जिसके कारण आज सही मायने में किसानों के चेहरे पर खुशी दिख रही है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं। पिछले कई सालों से हरियाणा में गेहूं का उत्पादन गिर रहा था, गेहूं के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। आज के दिन प्रदेश में जितनी भी उपलब्ध बिजली है उसमें से आधी बिजली कृषि क्षेत्र की सिंचाई के लिए दी जा रही है। किसानों की समस्याएं हल करने के लिए हमारी सरकार द्वारा नई मोबाईल फोन सेवा शुरू की जा रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय प्रदेश में जितना भी नहरी पानी उपलब्ध है उसका बराबर बंटवारा हमारी सरकार कर रही है। प्रदेश में सभी खालों को पक्का करने के लिए तेजी से काम चल रहा है और पुराने खालों की मुरम्मत का काम भी तेजी से चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों में कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं और कितने ही मुख्यमंत्री बने और हटे लेकिन किसी ने भी बिजली के उत्पादन की तरफ ध्यान नहीं दिया लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने बिजली के उत्पादन की तरफ विशेष ध्यान दिया है और प्रदेश में नये-नये थर्मल पावर प्लांट लगाये जा रहे हैं। यमुनानगर में, झाड़ली में और हिसार आदि जगहों पर थर्मल पावर प्लांट लगाये जा रहे हैं। हमारी सरकार का इन प्लांटस से 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। हमारी सरकार ने पिछले तीन साल के दौरान जितनी भी खराब बिजली की तारें थी उनको बदला है और नये खम्बे लगाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ट्रांस्फार्मर्ज को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इन सब बातों के साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान बिजली के कटों की तरफ भी दिलाना चाहूंगी कि जब कभी बिना किसी शिडयूल्ड के पांच-दस मिनट बिजली आने के बाद कट लग जाता है तो किसानों और लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे और परोपर शिडयूल्ड अपनाये जायें। पब्लिक को पता होना चाहिए कि कब बिजली आयेगी ओर कब कट लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सरकार की तरफ से गांवों और शहरों में सैंकड़ों ट्यूबवैल लगाये जा रहे हैं। उनमें से काफी ट्यूबवैल लगने के बाद अभी तक चालू नहीं हुए हैं इस ओर सरकार ध्यान दे। इसके अतिरिक्त मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि हमारे जो ट्यूबवैल आपरेटर लगे हुए हैं उनकी ड्यूटी के समय बिजली न होने के कारण वे ट्यूबवैल नहीं चला पाते। क्योंकि बिजली जब आती है उस समय वे ड्यूटी पर नहीं होते। जिसके कारण आम जनता को बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि जो पब्लिक हैल्थ के ट्यूबवैल हैं उनको होट लाईन के साथ जोड़ा जाए ताकि ड्यूटी के समय ट्यूबवैल आपरेटर ट्यूबवैल चला सकें और आम जनता को समय पर पानी मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि इंदिरा गांधी पेय जल योजना के तहत गांवों में रहने वाले गरीब हरिजन भाइयों को मुफ्त पानी की टंकी, टूंटी और कनैक्शन दिया गया है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से अर्ज करना चाहूंगी कि गांवों की तर्ज पर शहरों में रहने वाले गरीब हरिजन भाइयों को भी मुफ्त पानी की टंकी, टूंटी और कनैक्शन दिया जाए। क्योंकि शहरों में भी गरीब हरिजन भाई रहते हैं और ज्यादातर अनएथोराइज्ड कालोनियों में रहते हैं इस बारे में जब प्रशासन से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि इन जगहों पर पानी और सीवरेज

[श्रीमती सुमिता सिंह]

की सुविधा नहीं दी जा सकती क्योंकि ये कालोनियां अनएथोराइज्ड हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि शहरों में ऐसी जगहों पर भी बेसिक सुविधायें गरीब भाइयों को अवश्य दी जायें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि अगर एक पक्षी के पास घोंसला होता है तो एक गरीब आदमी के पास भी अपना आशियाना अवश्य होना चाहिए। यही कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है उन गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लाट देने की घोषणा की है। इस घोषणा पर काम भी शुरू हो गया है और फार्म आदि भरे जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन जितने विकास कार्य हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं इतना विकास न तो पहले कभी हुआ और न ही सोचा था। आज के दिन हरियाणा में किसी भी तरफ चले जाएं, कहीं पर सड़कें बनने लग रही हैं, कहीं पर ओवर ब्रिज बन रहे हैं तो कहीं पर अंडर ब्रिज बन रहे हैं। इस तरह से हर तरफ अब हरियाणा में विकास कार्य हो रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा शिक्षा की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने वर्ष 2008 को शिक्षा वर्ष घोषित किया है। इस समय नये-नये स्कूल और कालेज प्रदेश में बनाये जा रहे हैं और महिलाओं के लिए महिला यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। नये-नये कालेज, नये-नये स्कूल बनाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए स्पैशल यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं और अनुसूचित जाति के जो बच्चे स्कूल छोड़ देते थे ड्राप आऊट हो जाते थे उनके लिए सरकार ने मंथली स्टाईफंड शुरू किया है और स्कॉलरशिप शुरू की है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। इससे यह फायदा होगा कि बच्चे स्कूल छोड़कर नहीं जायेंगे क्योंकि जब ये दसवीं कर लेंगे तब इनको जो यह पैसा इनका इकट्ठा होगा उसका आधा पैसा इनको मिलेगा और 12वीं के बाद इनको पूरा पैसा मिलेगा जिससे ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते है। अनुसूचित जाति की लड़कियों को साईकिल दी जा रही हैं। कालेज की छात्राओं को भी साईकिल दी जा रही हैं और जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे कम्प्यूटर के छात्र हैं उनको मुफ्त में सरकार ने कम्प्यूटर देना भी शुरू किया है। इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है वह था कि शहरों के रैजीडैंशियल घरों के ऊपर हाऊस टैक्स हटाना। पिछली सरकार ने यह टैक्स इतना ज्यादा कर दिया था कि एक आम आदमी के साथ-साथ एक अमीर आदमी भी हाऊस टैक्स देने में दिक्कत महसूस करता था। ऐसा लगता था कि हम अपने घर में रहने का किराया दे रहे हैं। इसके लिए वाकई माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं जबकि किसी ने इस बात की आवाज भी नहीं उठाई कि हाऊस टैक्स को समाप्त किया जाये। पानी और सीवरेज के बिल्स के ऊपर जो सरचार्ज था वह भी हमारी सरकार ने माफ किया और गांवों में चूल्हा टैक्स माफ किया यह भी एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम हमारी सरकार का है। हमारी सरकार का ध्यान सफाई की ओर भी पूरी तरह से है। गांवों में 11 हजार सफाई कर्मचारी लगाये गये हैं मैं इस बात के लिए भी सरकार को बधाई देती हूं और इसके साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान शहरों की सफाई व्यवस्था की ओर भी दिलाना चाहूंगी। शहरों में सफाई कर्मचारियों की बहुत ज्यादा कमी है। इसके लिए शहरों में भी वार्डवाइज नये कर्मचारी रखने चाहिएं और उनको परमानैंट रखना चाहिए न कि ठेके पर रखना चाहिए। ठेकेदारी की प्रथा को भी समाप्त करना चाहिए। मैं इस बात की बधाई देती हूं कि

हमारे हरियाणा में न्यूनतम वेज 3500 रुपये हैं जो कि सबसे ज्यादा हैं। किन्तु जो भी हम सफाई कर्मचारी ठेके पर रखते हैं उनको ये 3500 रुपये नहीं मिलते हैं क्योंकि ठेकेदार उनको सिर्फ 2000 या 2200 रुपये महीना ही देते हैं। घटते लिंगानुपात को देखते हुए हमारी सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनायें लागू की हैं जैसे कि लाडली योजना, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना और अभी जो हमारी सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर और हैल्पर का वेतन बढ़ाया है इसके लिए भी मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देती हूं। हुडा के मकानों में हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए जो 33 प्रतिशत आरक्षण किया है यह भी एक सराहनीय कदम है। बिजली के कनैक्शन महिलाओं के नाम पर होने पर 10 पैसे प्रति यूनिट छूट और जो टीचर्ज की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए किया है यह भी सराहनीय कदम है और एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, वह फैसला था गांवों में महिलाओं की चौपाल बनाने का। मैं सरकार का ध्यान थोड़ा सा इस ओर दिलाना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आपने टीचर्ज की भर्ती में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण किया है उसी प्रकार से हमारी जो विधवा बहनें हैं उनकी क्वालीफिकेशन को देखते हुए उनके लिए भी नौकरियों में आरक्षण जरूर किया जाये क्योंकि एक महिला जब विधवा हो जाती है तो उसको विधवा पैंशन तो मिलती है जो कि 350 रुपये है किन्तु वह इस 350 रुपये में अपने परिवार का अपने बच्चों का खाना-पीना और पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकती। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि हमारी ऐसी महिलाओं के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण किया जाये। उनके लिए भी कुछ परसैंट सरकारी नौकरियों में आरक्षण किया जाये। हमारी सरकार का ध्यान स्वास्थ्य की ओर भी पूरी तरह से है। गांवों में गरीब लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है और जिन के पास बी०पी०एल० कार्ड्ज हैं उनमें गरीब महिलाओं को जो गर्भवती हैं उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 700 रुपये दिये जाने चाहिएं। हमारे वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि करनाल में एक मैडीकल कालेज अनाऊंस हुआ है और उसके बारे में मेरा आज प्रश्न भी लगा था जिसके जवाब में मंत्री महोदया ने कहा कि फण्ड्स नहीं हैं और जब फण्ड्स आयेंगे तो यह मैडीकल कालेज शुरू हो जायेगा। तो मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि कुछ बजट हमारे इस मैडीकल कालेज के लिए भी आप जरूर रखें। हमारी सरकार उद्योग की तरफ भी बहुत ध्यान दे रही है। हरियाणा में जो विशेष आर्थिक जोन्ज़ की स्थापना के लिए प्रस्ताव आये हैं उससे 2 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक निवेश होगा और कितने ही बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि जो पिछली सरकार के समय गुंडागर्दी का माहौल था, लोग आराम से सो भी नहीं सकते थे। आज के दिन हरियाणा में सुख-शान्ति है और हमारी सरकार ने जो प्रशंसनीय कार्य किये हैं उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ-साथ कुछ मेरे हल्के की भी समस्याएं हैं मैं उनको भी हाऊस के सामने रखना चाहता हूं। हरियाणा के विकास के लिए तथा हरियाणा को नम्बर एक राज्य बनाने के लिए हरियाणा सरकार जो

[श्री अमीर चन्द मक्कड़]

प्रयास कर रही है उसकी तस्वीर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में स्पष्ट दिखाई देती है। हरियाणा में विकास के जितने भी कार्य चल रहे हैं वे नजर आ रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो प्रदेश को एक नम्बर का राज्य बनाने का सपना संजोया था वह पूरा होगा। इसी तरह से अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए भी प्रति हैक्टेयर 42 क्विंटल गेहूं की पैदावार का भी एक रिकॉर्ड हरियाणा ने कायम किया है। 147 लाख टन अनाज की पैदावार बनाकर हरियाणा सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। इसी तरह से पीने के पानी की बात है। हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की हुई है कि 40 से 70 लीटर तक पीने का पानी प्रति व्यक्ति उपलब्ध करवाया जायेगा। इस बारे में मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे हल्के में हांसी शहर में पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है और जब तक दूसरा वाटर वर्क्स हांसी में नहीं बन जाता तब तक हांसी शहर के लोगों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। मेरी हरियाणा सरकार से यह प्रार्थना है कि जहां विकास के इतने बड़े-बड़े कार्य हो रहे हैं तो पीने के पानी की समस्या को सबसे पहले निपटाया जाना चाहिए। यदि इन्सान को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलता है तो उसकी सेहत भी ठीक नहीं रह सकती। आज हांसी में पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है और कई बार लोग शिकायत भी करते हैं मगर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि दूसरे वाटर वर्क्स का जल्दी से ऐस्टीमेट बनवाकर उसके निर्माण का काम शुरू किया जाये ताकि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो पीने के पानी के नाले हैं उनको भी कवर किया जाना चाहिए। आजकल हमारी जो बहनें हैं वे उन नालों पर कपड़े धोने लग गई हैं। सारी गन्दगी पानी में मिल जाती है और इससे बीमारियां फैलने का भय बना रहता है। दूसरे प्रकार की गन्दगी की सफाई हो सकती है मगर इस प्रकार की गन्दगी की सफाई नहीं हो सकती। इसलिए उनको कवर करने का प्रावधान जरूर करवाया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ मेरी सरकार ने हरियाणा के अन्दर पीने के पानी के साथ ही किसानों की उन्नति के लिए बड़े ही सराहनीय काम किये हैं। हरियाणा देश का सबसे पहला राज्य है जिसने किसानों के अरबों रुपये के बिजली के बिलों के बोझ को माफ करके किसानों को राहत दी है। किसानों के कर्जों को मुआफ करके किसानों को कर्जों से मुक्त करवाया है और उनको समाज में आगे बढ़ने का मौका दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ करोड़ों अरबों का जो ब्याज किसानों के ऊपर था उसको मुआफ किया है और अब सैंटर की सरकार ने इतना बड़ा किसानों को फायदा पहुंचाया है। केन्द्र की सरकार ने 60 करोड़ रुपये के कर्जे मुआफ करने का सराहनीय कार्य किया है। हमारे ओपोजीशन के भाई इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और लोगों का मन उधर से हटाने के लिए गलत बयान देकर लोगों को भरमाने की बात कर रहे हैं जो कि अत्यन्त निन्दनीय बात है। 5-7 साल पहले ये लोग कहा करते थे कि कर्जे मुआफ करो, कर्जे मुआफ करो और आज जब सरकार ने कर्जे मुआफ कर दिये तो बजाए उसकी तारीफ करते ये लोगों को भरमाने की तरफ लगे हुए हैं, यह उनका अच्छा काम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने लोगों की भलाई के बहुत अच्छे काम किये हैं। इसी तरह से सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐलान कर रखा है। कर्जा मुआफी से महिलाओं को भी शक्ति मिलती है क्योंकि कर्जा मुआफी के अन्दर महिलाएं भी बराबर की शरीक हैं और

इससे महिलाओं को भी बड़ी राहत मिली है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सड़कों का उद्धार किया है और तीन हजार करोड़ रुपये के काम शुरू कर रखें हैं। मैं समझता हूं कि मेरे हल्के हांसी में कुछ सड़कों की रिपेयर की जरूरत है। कुछ नई सड़कें बनाने के लिए मैंने लिख कर भी दिया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हांसी गये थे तो उस वक्त भी मैंने कुछ सड़कों के बारे में उनसे निवेदन किया था। घाणा से जमावड़ी तक सड़क, लाल पुरा से धुलाना तक की सड़क वाया ढाणी मुज्जफर होकर जाती है यह सड़क बननी बहुत जरूरी है। एक सड़क खरखड़ा से होकर अनाज मण्डी तक जाती है वह थोड़ी बननी रह गई थी उसको बनवाया जाए क्योंकि किसानों को वहां से आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वह सड़क भी पक्की करवाई जाए। जितनी भी सड़कें टूटी हुई हैं उनकी रिपेयर भी युद्धस्तर पर करवाई जाए ताकि किसानों को आने-जाने की सुविधा मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ एक बाईपास जो जी०टी० रोड से चल कर शहर से होता हुआ जी०टी० रोड में दुबारा मिलता है उसको भी जल्दी चालू करवाया जाए। उद्योगों के बारे में हरियाणा सरकार बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने युद्धस्तर पर कार्य शुरू किया है। पिछली सरकार के वक्त में तो बहुत से उद्योग यहां से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और पिछली सरकार के वक्त में कुछ उद्योगपति यहां से बाहर चले गये थे। इस सरकार के आने के बाद वे उद्योगपति वापिस हरियाणा में आ रहे हैं। विदेशों से भी उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए आ रहे है क्योंकि हरियाणा की सरकार उद्योगों को बहुत सहूलियतें दे रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में बहुत से उद्योग लग रहे हैं। हांसी में एक बहुत बड़ी स्पीनिंग मिल थी जिसमें हजारों मजदूर काम करते थे लेकिन पिछली सरकार ने वह मिल बेच कर हजारों मजदूरों को बेकार कर दिया। पचास एकड़ ज़मीन वहां पर खाली पड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि हांसी में इस जमीन पर कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए ताकि हांसी के लोगों को कारोबार मिल सके। अगर कोई बड़ा उद्योग वहां पर चलाएंगे तो उससे मजदूरों को भी काम मिलेगा। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वहां पर कोई बड़ा उद्योग जरूर लगाया जाए। इसके साथ ही हमारी सरकार पर्यटन में भी काफी विस्तार कर रही है और अच्छे-अच्छे काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहूंगा कि हांसी में छोटे-छोटे बहुत से पार्क हैं लेकिन कोई भी बड़ा पार्क नहीं है इसके लिए हमने मांग भी कर रखी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर एक बड़ा पार्क बनाया जाए ताकि वहां पर लोग खुली हवा में सांस ले सकें और घूम फिर सकें। इसी तरह से शहरों में निकासी के लिए बड़े स्तर पर काम किए जा रहे हैं, विकास के काम किए जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि हांसी में विकास के काम नहीं किए जा रहे हैं। विकास के काम तो वहां पर भी किए जा रहे हैं लेकिन बाकी जगहों के मुकाबले में कम हो रहे हैं। वहां पर कई सड़कें कच्ची हैं उनको सरकार द्वारा पक्का करवाया जाए, इसके अलावा गांवों में नालियों और गलियों को भी पक्का किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, हांसी शहीदों और देश भक्तों का शहर हैं। हांसी में 1857 में जंगे आजादी के वक्त जब दोबारा से अंग्रेज काबिज हो गए थे जो उस वक्त लोगों को सड़कों पर लिटा कर गिरड़ी फेर दी थी जिसके कारण उनके खून से वह सड़क लाल हो गई थी। आज भी वह सड़क लाल है। हमारे मंत्री जी वहां पर गए थे और उन्होंने

[श्री अमीर चन्द मक्कड़]

उस सड़क को देखा भी था। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि मंत्री जी हांसी के बारे में भी ध्यान रखें और वहां पर विकास के कार्य करवाएं। उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों ने लोगों की भावनाओं को कुचलने के लिए हिन्दुओं को दफनाया था और मुसलमानों को जलाया था। उन्होंने धर्म के विरुद्ध काम किए थे। मेरी रिक्वैस्ट है कि शहीदों के नाम पर वहां पर जो पार्क बनाया गया था उसको डिवैल्प करने के लिए और पैसा दिया जाए ताकि लोग हमारे शहीदों को याद करते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यह सरकार शिक्षा के विस्तार के लिए पूरा जोर लगा रही है और एस० सीज०, एस० टीज और बी०सीज० के गरीब बच्चों को प्रोत्साहन देकर शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए। हमारे यहां पर कालेज तो हैं लेकिन वहां पर एक तकनीकी कालेज लड़कियों के लिए जरूर खोला जाए। इसके अलावा हमारे यहां पर एक कालेज के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था लेकिन मैं फिर से यह कहना चाहूंगा कि वहां पर महिलाओं के लिए एक कालेज भी जरूर होना चाहिए। हमारी बच्चियां भिवानी और रोहतक में पढ़ने के लिए जाती हैं। अगर हमारे वहां पर ही गर्ल्ज कालेज खुल जाएगा तो उनको बहुत ही सुविधा हो जाएगी। हमारी बच्चियां भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। इसी के साथ उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर भुजारे हैं जो कि 100 सालों से कास्त करते आ रहे हैं लेकिन उनको आज तक उन जमीनों का मालिकाना हक नहीं दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनको उन जमीनों का मालिक बनाया जाए ताकि वे अपना गुजारा ठीक ढंग से कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

संसदीय सचिव (राव दान सिंह, महेन्द्रगढ़) : परम आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और साथ ही स्पीकर साहब का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हरियाणा विधान सभा के इस सदन को एक नयी पहचान देकर नवीनीकरण का कार्य पूरा किया है। आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, इस वर्ष के बजट में भारतवर्ष के वित्त मंत्री ने आदरणीय मनमोहन सिंह और यू०पी०ए० की चेयरपर्सन परम आदरणीय सोनिया जी के निर्देश और आदेशानुसार एक ऐसा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बजट इस देश को दिया जिसका आज तक कोई सानी नहीं है। विपक्ष के लोग आज तक यह समझ ही नहीं पाए हैं कि हकीकत में ऐसा हुआ कैसे। इसलिए हर विपक्ष का आदमी उसकी अपने-अपने तौर पर व्याख्या करता है। डिप्टी स्पीकर सर, आज एक नया माहौल, एक नयी दिशा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री जी की जोड़ी ने हरियाणा में और मनमोहन सिंह और आदरणीय सोनिया गांधी जी ने केन्द्र के अंदर देने का प्रयास किया है। डिप्टी स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की आने वाली गतिविधियों के बारे में एक प्रतिबिम्ब होता है और प्रतिपक्ष एक आईना होता है। विपक्ष सत्ता पक्ष की ओर से किए हुए हर कार्य की व्याख्या आलोचनात्मक विश्लेषण के तौर पर सही और गलत गुणदोष के आधार पर करता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहां परिपाटी और परम्परा इस तरह की है कि जो व्यक्ति विपक्ष में बैठता है वह आलोचना की ही बात करता है। सरकार चाहे अच्छे काम करे लेकिन वह उसकी सराहना नहीं कर

सकता। जबकि हकीकत यह है कि हलवाई से अगर बैर हो तो मिठाई खराब नहीं बतानी चाहिए। यह बात प्रतिपक्ष के लोगों को समझ में आनी चाहिए। माननीय सदस्य ओम प्रकाश चौटाला जी इस समय सदन में नहीं हैं। वे इस सदन के बहुत वरिष्ठ मैम्बर हैं और वे पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने अभिभाषण पर एक टिप्पणी की और कहा कि आखिर किसान कर्ज लेता ही क्यों है? डिप्टी स्पीकर सर, मैं इस बारे में उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि उनसे ज्यादा किसान की व्यथा को कौन जानता है। वह स्वयं किसान के बेटे हैं, किसानों के नेता हैं और किसानों को सत्ता की सीढ़ी बनाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं लेकिन अगर वे भी इस सदन के माध्यम से यह पूछें कि किसान कर्ज लेता ही क्यों है तो क्या यह ठीक है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उनके जमाने में किसान कर्जा नहीं लेता था। हरियाणा में यह बात प्रचलित रही है कि चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं लिख दूंगा कि कर्जा माफ और नीचे देवीलाल। डिप्टी स्पीकर साहब, जब ये सारी चीजें थीं तो इसका मतलब यह है कि किसान का कर्जा आज का नहीं है बल्कि यह बहुत पुराना चला आ रहा है। जो आदरणीय मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री जी ने 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे किसानों के माफ करने का फैसला किया है तो इनको तो इसकी सराहना करनी चाहिए थी। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने हरियाणा के किसानों के 1600 करोड़ रुपयों के बिजली के बिलों को माफ करने का फैसला किया तो इनको तो उसकी भी सराहना करनी चाहिए थी हालांकि कांग्रेस ने इसका वायदा नहीं किया था। अगर हमारी सरकार ने 830 करोड़ रुपयों का कोओपरेटिव बैंकों का किसानों का कर्ज माफ किया है तो इनको तो उसकी भी सराहना करनी चाहिए न कि उसकी नुक्ताचीनी करनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, इस प्रदेश में दो ही अन्नदाता हैं एक भगवान और दूसरा किसान। आप जानते हैं कि आज कृषि लाभ का धंधा नहीं है। आज किसान को चारों तरफ घाटा उठाना पड़ता है। अगर कृषि लाभ का धंधा होती तो फिर टाटा, बिड़ला, अम्बानी और मित्तल जैसे कृषि का कार्य करते। इसलिए घाटे की वजह से ही आज किसान अपनी व्यथा पर रोता है। केन्द्र सरकार ने अगर आज किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर उसकी आत्महत्याओं के कगार पर पहुंचने की स्थिति को देखते हुए अगर कोई ऐतिहासिक फैसला लिया है तो हमें उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों की बात आती है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा किसान हितैषी कोई दूसरी सरकार नहीं हो सकती। आज किसानों का कर्ज माफ करके हमने उन पर कोई परोपकार नहीं किया है। किसान का बेटा जानता है कि उसका बाप फटी धोती पहनकर किस तरह रहता है और रोटी चटनी के साथ मांगी हुई छाछ पीकर उसका बेटा अपनी मां की तार-तार ओढ़नी को देखकर और उसकी बहन की बढ़ती हुई उम्र देखकर उसकी शादी की चिंता में और अपने भाई और भतीजे की शादी ब्याह और हारी बीमारी और शिक्षा के प्रबंध के लिए चारों तरफ जब कोई व्यवस्था नहीं देखता है तो उसे कर्ज के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आता है। यही कारण है कि वह कर्ज लेता है। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास कर्ज न लेने की कोई कैमिस्ट्री थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताई। अगर अब भी उनके पास कोई ऐसी कैमिस्ट्री है तो वे इस सदन में बताएं तो यह सदन उसे सहर्ष स्वीकार करेगा। हम भी यही चाहते हैं कि किसान कर्जदार न हो। मैं तो इस बारे में यही कहूंगा कि हम अपने फर्ज को निभाएं। अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों की भी बात करें तब जाकर हम कह सकते हैं कि

[राव दान सिंह]

वाकई में हम कुछ बदलना चाहते हैं। किसी शायर ने कहा है कि "पीड़ पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए, इस धरा से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी तो कोशिश है कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए।" आदरणीय उपाध्यक्ष जी, हम यहां पर स्वस्थ परम्पराओं को स्थापित करना चाहते हैं। जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सत्ता आई है। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने प्रदेश में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री व बीरेन्द्र सिंह जी को विल मंत्री बनाया है तब से इन दोनों ने विकास का संकल्प किया है। पिछले तीन वर्ष की स्थिति की तरफ झांककर देखें तो पता लगेगा कि किसान की अवस्था कितनी दयनीय थी, कानून व्यवस्था की स्थिति भी चरमराई हुई थी। प्रायः हत्या, डकैती और लूटपाट का आलम था। इन परिस्थितियों में पलायन को रोकना था व नयी व्यवस्था को जगाने की बात थी और जगाया भी है और उसका परिणाम हमें साफ तौर पर नजर आता है कि उद्योगों की लम्बी लाइन लगी है। एक लाख करोड़ के आसपास उद्योगों के प्रपोजल्स आए हुए हैं और 33-34 हजार करोड़ रुपये के उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं जिससे हजारों नहीं लाखों बेरोजगार युवकों को आस बंधी है। मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि मैं हरियाणा को एक नंबर का प्रदेश बनाऊंगा लेकिन ऐसे मामलों में किसी एक व्यक्ति के संकल्प लेने से बात नहीं बनती। इसमें सभी के सहयोग की जरूरत होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सदन से प्रतिपक्ष के लोग हैं या सत्ता पक्ष के लोग हैं सभी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा का नवनिर्माण होगा। नारनौल की ढाणी से तरक्की और विकास की राह चलकर चंडीगढ़ पहुंचेगी तभी हम उसे विकास कह सकते हैं। मात्र बड़े शहरों के विकास से बात बनने वाली नहीं है। मेरे साथी सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए बहुत से बिंदुओं को छुआ है मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका मैं निश्चित तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। जहां तक सिंचाई का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह क्षेत्र अधिकतर सूखे की चपेट में रहता है और जहां पानी 500 फुट से लेकर 1400 फुट गहराई तक भी नहीं मिल पाता। मेरे क्षेत्र का किसान इतना परिश्रमी है कि सूखी जमीन का सीना चीरकर अनाज पैदा करने की क्षमता तो रखता है लेकिन अपनी बदहाली पर आंसू बहाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही पहला निर्णय पानी के समान बंटवारे का लिया। यह एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। जिससे मेरे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यह कार्य किसी तरह से पूरा हो तब जाकर हम मान पाएंगे कि वाकई में जिस पानी के समान बंटवारे की बात हम कह रहे थे वह हकीकत के रूप में हमारे सामने होने जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० का मामला कोर्ट में लंबित है इसलिए मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जल आपूर्ति के जितने संसाधन हैं उनको पूरी तरह से जुटाया जाए ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जा सके। बिजली की बात आती है तो इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि बिजली की भारी कमी है। जब प्रदेश में चर्चा होती है और राज्य के बारे में कहा जाता है तो यह कहा जाता है कि सब चीजें बहुत अच्छी हैं सिर्फ बिजली की वजह से आपकी बदनामी है और यह बात

सत्य भी है । लेकिन सरकार ने पूरे प्रयासों के साथ बहुत बड़ी व्यवस्था करके इस तरफ काम करने का काम किया है । आज 8.57 पैसे प्रति यूनिट बिजली लेकर किसानों को 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने का काम किया जा रहा है । एक तरफ तो विकास का इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प किया जा रहा है और दूसरी तरफ बिजली पैदा करने के कारखाने लगाये जा रहे हैं । जबकि दूसरी पार्टी सत्ता में आने के बाद लोगों को बहकाने का काम करते रहे कि 24 घण्टे बिजली देंगे । जैसे कि कोई आसमान से तारे या तारों की चमकती बिजली को तोड़कर किसानों को बिजली देनी हो । आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज का किसान बहकावे में नहीं आने वाला है । एक समय था जब यह कहा जाता था कि Indian democracy is not a democracy it's a mobocracy where heads are counted but not the brains. लेकिन आज उनके ब्रेन भी काउंट किये जाते हैं । आज आम जनता और जमींदार वह बात कह सकते हैं जो आपके कालेज में पढ़े हुए इंजीनियर्स और साईंटिस्टस नहीं बता सकते । इसलिए आज उनको गुमराह नहीं किया जा सकता । आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने बहुत सोच समझकर अच्छी शुरूआत की है । हम बिजली के कारखाने लगा रहे हैं और उनके माध्यम से हरियाणा के अन्दर बिजली की सप्लाई करेंगे ताकि हरियाणा कृषि के साथ उद्योगों में भी साईमैलटेनियशली विकास कर सके । चहुंमुखी विकास तभी हो सकता है जब बिजली और उद्योग साथ-साथ चलें । आज जो बिजली की परियोजनाएं चल रही हैं जैसे यमुनानगर, खेदड़ और झाड़ली में वे डेढ़ दो साल में पूरी हो जायेंगी जब हरियाणा अपने किसानों को 18-20 घण्टे प्रति दिन बिजली दे पायेगा और निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान कर देंगे ।

अब मैं सड़क और परिवहन के बारे में कहना चाहता हूं परिवहन मेरा स्वयं का विभाग भी है । अगर किसी प्रदेश की तरक्की मापनी हो तो उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर को उसकी सड़कों और परिवहन की व्यवस्था से मापा जा सकता है । हरियाणा प्रदेश के अन्दर सड़कों की दो-दो, चार-चार, छः-छः और गुड़गांव में 8-8 और 12-12 लेन वाली सड़कें बनाकर, हकीकत में बदल दिया है । आने वाले समय में आप देखेंगे कि गुड़गांव चेहरे के तौर पर नजर आयेगा । अगर कोई दुबई से आकर गुड़गांव में उतरेगा तो यह लगेगा कि प्रदेश ने वाकई तरक्की की है लेकिन बात गुड़गांव तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए । आम गांव से, आम रास्ते से और आम व्यक्ति से जुड़कर के किसी बात को करेंगे तभी हम हकीकत के साथ न्याय कर पायेंगे । सरकार ने यह एक सराहनीय काम किया है । आज सरकार ने हरियाणा में एयर कंडीशनर वोल्वो बसें चलाई हैं, गुड़गांव में लोअर फलोरिंग की 15 सिटी बसें चलाई हैं । सी०एन०जी० की 150 बसें चलाई हैं । यह एक बहुत बड़ा काम पूरा हुआ है और प्रदेश में रोडवेज ने बड़ी तरक्की की है लेकिन अभी हमारे पास कर्मचारियों की थोड़ी कमी है जिसके कारण रोडवेज में थोड़ी दिक्कत है लेकिन दो महीने बाद भर्ती हो जायेगी तो यह समस्या भी हल हो जायेगी और रोडवेज की सुविधा प्रदान कर देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पर्यटन की बात है, पर्यटन हरियाणा के अन्दर स्वाभाविक तौर पर कम है but we have created a lot out of this. आज हरियाणा में पर्यटन के साथ मैडी टूरिज्म भी बहुत बड़ी चीज है जो हरियाणा को मिल सकती है । गुड़गांव में और फरीदाबाद सैंट्रल्ड सिटीज के आसपास सिटी होस्पिटल बनायें । जो लोग विदेशों में उपचार करवाने जाते हैं उनका काफी पैसा खर्च हो जाता है वह इलाज हिन्दुस्तान में ही सस्ती दर पर उपलब्ध हो

[राव दान सिंह]

सके और जो विदेशी मुद्रा के तौर पर हमारे प्रदेश को सहयोग दे सकें और मुनाफा कमा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा शहरी विकास और ग्रामीण विकास के बारे में बात करना चाहता हूं। आज शहरी विकास के साथ-साथ ग्रामीण विकास की भी बहुत जरूरत है। जैसे हरेडा की स्थापना की बात की जा रही है। यह वाकई में ही एक बहुत अच्छी योजना है। किसी गांव के आदमी को शहर की तरह जीने का मौका मिलेगा उनको शहर जैसा माहौल देखने को मिलेगा। इसके बाद शिक्षा की बात आती है। जैसा कि कहा गया है कि 'अज्ञानता अभिशाप है' और जब तक आदमी अज्ञानी रहता है तो उसे दुनिया की बात समझ नहीं आ सकती। आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करने का काम किया है। खासकर हमारी बहनों को क्योंकि जब कोई बहन पढ़ती है तो उसके साथ दो परिवार पढ़ते हैं लेकिन जब एक बच्चा पढ़ता है तो एक व्यक्ति ही पढ़ता है। इसी तर्ज पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जींद की रैली में एक महिला कालेज खोलने की घोषणा की थी उसके बाद हमारे प्रदेश में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उसके बाद कई कालेज जैसे रेवाड़ी में एक महिला कालेज की स्थापना की गई। जहां तक टैक्नीकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज की बात है महिलाओं को उनमें विशेष आरक्षण दिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। ऐजूसिटी बनाया जा रहा है जो कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड की तर्ज पर बनाया जायेगा यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। इसलिए निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश तरक्की की तरफ जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खेलों की बात हैं हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए इसका बजट डबल किया है। जिन खिलाड़ियों को 50 रुपये प्रति दिन डाइट के लिए मिलते थे उसको बढ़ाकर 100 रुपये किया गया है। जो खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा के अंदर अच्छा खेल प्रदर्शन करके मैडल जीतकर आते थे उनको 10-10 लाख रुपये तक के इनाम देने की बात की गई है ताकि उनको प्रोत्साहित किया जा सके। यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। जब तक नागरिक का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक आपके सारे कार्यक्रम व्यर्थ हैं। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक और बात चिन्तनीय है और इसको अगर मैं ज्वलंत समस्या कहूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी और वह समस्या है घटता हुआ लिंगानुपात। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि जहां सरकार ने भ्रूण हत्या रोकने के लिए अल्ट्रासाउंड रोकने का कानून बनाया है और सजा का प्रावधान किया है तो वह नाकाफी है क्योंकि मात्र सजा के तौर पर हम किसी बात को पूर्णतया लागू नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को इसको मन से समझना पड़ेगा क्योंकि हर व्यक्ति जो बड़ा है वह मां की कोख से पैदा हुआ है। एक महिला के कई रूप होते हैं, कहीं मां के रूप में जीजाबाई बनकर अपने बेटे को प्रोत्साहित करती है, कहीं बहन के रूप में लक्ष्मीबाई बनकर अपने अधिकारों के लिए लड़ती है और कहीं पत्नी बनकर सीता के रूप में पतिव्रता बनकर काम करती है। आज भ्रूण हत्या की जाएगी तो कल कोई बड़ा व्यक्ति कहां से पैदा हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि there is a woman behind every great man इस बात को समझना

पड़ेगा और लिंगानुपात जो गिरता जा रहा है इसको बढ़ाना पड़ेगा। सरकार ने इस क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए प्रावधान किया है कि जिस गांव में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कम होगा उसके लिए एक लाख रुपये और जो गांव पूरे हरियाणा प्रदेश में नम्बर 1 पर होगा उसके लिए 5 लाख रुपये का इनाम देंगे जोकि बहुत बड़ी बात है। इसको और भी आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने जो कानून व्यवस्था की बात की तो हरियाणा में अब पूरी तरह से अमन और चैन है, पूरे हरियाणा में शांति है। पहले कानून और व्यवस्था टूटने और चरमराने की जो बात थी वह खत्म हो चुकी है। हरियाणा में आने वाला हर उद्योपति आज अपने आपको सुरक्षित महसूस करता है और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आज हरियाणा में किसी बदमाश के लिए कोई जगह नहीं है या तो वे पुलिस के साथ लड़ते हुए ढ़ेर हो चुके हैं या फिर इस प्रदेश को छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा एक टीम के रूप में काम करते हुए दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया। उपाध्यक्ष महोदय, कई साथियों ने कहा है कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करने का है चाहे वह केन्द्र की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, पता नहीं ये क्यों भूल जाते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम सरकार करती है हमने उसकी सराहना की है। माननीय वित्त मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं इनको कहना चाहूंगा कि 3 साल के अंदर हमारा 3 गुना प्लान बजट बढ़ा है। इसके साथ-साथ मेरे साथी विधायकों को बोलने के लिए सरकार की तरफ से शायद कागज थमा दिया जाता है क्योंकि यह तो महालेखाकार की रिपोर्ट है, हमारी सरकार की तो है नहीं। यह केन्द्र की रिपोर्ट है अगर इसको पूरा पढ़े तो एक भी चांयट ऐसा नहीं है जिसमें सरकार की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। किसी ने जलापूर्ति के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं, इसमें लिखा है कि दिसम्बर 2004 में जलापूर्ति के अभावग्रस्त 1971 गांवों में से 868 गांव मार्च 2007 तक अभावग्रस्त रहे। अभावग्रस्त गांवों को जल आपूर्ति करने की प्राथमिकता नहीं दी गई क्योंकि 2005-07 में उन 510 गांवों को आवेष्टित किया गया जिनको जल आपूर्ति की कमी नहीं थी। यानि वे 510 गांव लिए गए जहां पहले पानी पूरा जा रहा था उसके बावजूद पैसा वहां खर्च हो रहा है जहां पानी की कमी नहीं तो वह पैसा कहां जाएगा या तो अधिकारियों की जेब में जाएगा या ठेकेदारों की जेब में जाएगा, वह प्रदेश का पैसा तो बेकार गया। दूसरा, मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना नारनौल नगर, मकराना गांवों के समूह तथा नंगल दारगु गांवों के समूह की जल आपूर्ति स्कीमों को चलाने के परिणामस्वरूप 5.47 करोड़ रुपये की निधियों का व्यर्थ व्यय/अवरोधन हुआ यानि की बेकार में 5.50 करोड़ रुपये का खर्चा सरकार ने किया। तीसरा, मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग के साथ अपरिष्कृत जल के निर्गम के मामले को उठाने में विलम्ब के कारण कलायत शहर के वासी 4.99 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद सुरक्षित पेय जल से वंचित रहे। इसी तरह से 15.59 करोड़ रुपए की लागत पर 4 से 37 महीने पीछे सम्पूर्ण की गई जलापूर्ति स्कीमें बिजली के कनैक्शन न मिलने के कारण अकर्मण्य रही यानि कि सिंचाई और बिजली महकमें का तालमेल न होने

[श्री नरेश मलिक]

के कारण सरकार का 16 करोड़ रुपये बेकार हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की कितनी बातें मैं गिनाऊं। महालेखाकार की रिपोर्ट में ऐसी-ऐसी कई बातों का जिक्र किया हुआ है और न जानें कितना पैसा बेकार गया है। इस रिपोर्ट में कोई गुण नहीं बताया गया है। मेरी बहन बैठी थी उसने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है जिससे विपक्ष के साथी बौखला गये हैं। विपक्ष के भाई कुछ बोल नहीं सकते। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि केन्द्र सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस बारे में लोक सभा में सभी पार्टियों ने एकमत होकर एक डिमांड भी रखी थी जिसे सारा देश देख रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि आढ़तियों से और साहूकारों से जो पैसा ब्याज पर किसानों ने ले रखा है उस पर भी प्रदेश सरकार विचार करेगी। इस बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें जो इफ-बट लगा रखी है वह नहीं लगानी चाहिए। उसमें 2.50 एकड़ जमीन वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, चाहे प्रदेश सरकार और ऋण ले ले हमारे यहां एक प्रथा है कि यदि एक बाप के चार बेटे हैं और मान लो बाप के नाम 8 एकड़ जमीन है, उनका बाप मरता नहीं तब तक वे लड़के अपने नाम जमीन नहीं चढ़वाते। अगर वह जमीन चार बेटों के नाम हो जाये तो 2-2 एकड़ चारों के हिस्से आती है। ज्यादातर किसानों के साथ ऐसा ही हो रखा है। इसलिए इसमें 2.50 एकड़ वाली कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उन लोगों की क्या गलती है जिन्होंने महीने-दो-महीने पहले अपना लोन जमा करवा दिया। उनकी यही गलती है कि उन्होंने समय पर पैसा जमा करवा दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन्होंने समय पर पैसा जमा करवाया है उनको भी कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने जो पैसा जमा करवाया था वह पैसा भी बैंकों में क्रेडिट हो सकता था क्योंकि 60 हजार करोड़ रुपये भी बैंकों पर ही डाल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक बहन ने यहां बोलते हुए कहा था कि अब रात के समय माताएं और बहनें आराम से सो सकती हैं क्योंकि प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बेहतर है जबकि चौटाला जी के राज में माताएं और बहनें आराम से नहीं सो पाती थी। इस बारे में मैं तीन उदाहरण अपने हल्के के देना चाहूंगा। मेरा पहला उदाहरण यह है कि 6 महीने पहले मेरे गांव में एक मां बेटे की सोते हुए हत्या कर दी गई थी और हत्या करवाने वाला उसका चाचा का लड़का और उस लड़के की बहू थी। मैंने बार-बार एस०एस०पी साहब को कहा कि एस०एस०पी० महोदय इसमें इसकी पत्नी का भी हाथ है। पूरा गांव कह रहा था कि उस औरत का भी कत्ल में हाथ है। पूरा गांव कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद लड़के को गिरफ्तार किया गया। लड़के को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन्स्पैक्टर कहता है कि यह लड़का कातिल है इसको ले जावो। उपाध्यक्ष महोदय, यदि 302 के हत्यारे को पुलिस छोड़ेगी तो क्या होगा। उसके बाद पंचायत हुई और प्रशासन पर दबाव बनाया, उसके बाद उस औरत को 120बी धारा के तहत गिरफ्तार किया गया। धारा 302 और 120 बी में गिरफ्तार करने के बाद एक दिन भी उनको पुलिस रिमाण्ड पर नहीं लिया गया, सीधे ही जेल भेज दिया गया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में अनुरोध किया है। यह जो मैं बता रहा हूं यह कोई 20 दिन पहले की बात है। इस्माईला गांव के अन्दर एक लड़का रात को सो रहा था, सोते-सोते उसे

काटकर गली में गिराकर जला दिया। आज तक भी उसके हत्यारों को पकड़ा नहीं गया। यह तो मैं 2-3 उदाहरण ऐसे बता रहा हूं। बीच में इस बारे में कुछ अच्छे स्टैप लिये थे कई मर्डर बड़े लोगों द्वारा किए गए थे और उनका एनकाऊंटर भी हुआ लेकिन फिलहाल जो ढुलमुल पुलिस की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था चल रही है यह ठीक नहीं है। पुलिस प्रदेश के अन्दर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को काबू करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। बहुत भारी परेशानी की स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले प्रदेश में पीले कार्डों के ऊपर बहुत कुछ आया था और अभी भी उसका सर्वे चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इसके पात्र होने के बावजूद इसमें शामिल होने से रह गये हैं। सरकार इसका सर्वे करवा रही है यह बहुत अच्छी बात है। मेरा इस बारे में यही निवेदन है कि इसके लिए जो व्यक्ति रह जायें उनको एक मौका जरूर देना चाहिए ताकि वे अपने आवेदन कर सकें और उसकी इंक्वायरी हो और बाकायदा उससे कोई बचे नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में हरियाणा के पिछड़े वर्ग के शोषित भाइयों के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। लेकिन पिछले साल की जो आपकी लेखाकार की रिपोर्ट है इसके मुताबिक इसमें लॉ के लिए बहुत ज्यादा पैसा आता है और उसमें प्रावधान है कि उसमें 90 दिन के अन्दर वह पैसा एप्लीकैंट्स को दे देना चाहिए। आपकी एप्लीकेशन्ज आई थी जिसमें से केवल 23 आदमियों को ही लोन दिया गया और वह भी 12 से 14 महीने के अन्दर यानि जिससे कोई पैसा मिल गया तो उसका लोन मंजूर कर दिया और बाकी धक्के खाते रहे। मेरा अनुरोध है कि इसके ऊपर भी एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही हांसी-बुटाना नहर की बात भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आई। यह केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि इसमें फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में हो।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि हांसी-बुटाना नहर के बारे में सी०डब्ल्यू०सी० ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और यह रिपोर्ट हमारे हक में गई है। इनने अपनी रिपोर्ट में जो फैक्ट्स दिये थे सी०डब्ल्यू०सी० ने उन्हीं के आधार पर हमारे हक में अपना फैसला दिया है। इस केस की सुनवाई आगामी 29 अप्रैल, 2008 को है। यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के सूचनार्थ बता रहा हूं।

श्री नरेश मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, सी०डब्ल्यू०सी० ने जो हरियाणा के हक में अपनी रिपोर्ट दी है इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसमें हरियाणा का पक्ष यही है कि हम अपना पानी लेंगे और अपना पानी हम कहीं से भी लें इसमें किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें पीछे से राजनीति कर रहे हैं। सरकार को उनको क्लीयर करना चाहिए कि कौन ऐसे आदमी हैं जो इस केस को दक्षिणी हरियाणा को पानी से वंचित रखना चाहते हैं। आज जो बार-बार बयान देते हैं ओम प्रकाश चौटाला के जो आदमी हैं उन्होंने यह सब करवा रखा है। वे आदमी आज

13.00 बजे

अपने आपको किसान हितैषी कहते हैं। मंत्री जी ने कहा है कि सतलुज यमुना लिंक नहर की अगली तारीख 12 अप्रैल लगी है हम तो परमात्मा से

[श्री नरेश मलिक]

प्रार्थना करते हैं कि उसका फैसला हमारे हित में ही हो और हमें हमारा हक मिले। पंजाब सरकार ने जिस तरह का असंवैधानिक कदम उठाते हुए उस फैसले को रद्द किया था उसको तो केन्द्र सरकार रोक सकती थी। **********

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ये आपत्तिजनक शब्द कहे हैं यह सदन की कार्यवाही में रिकॉर्ड नहीं होने चाहिएं।

श्री उपाध्यक्ष : ये शब्द सदन की कार्यवाही में रिकॉर्ड न किए जाएं। मलिक साहब आप वाईंड-अप करें।

श्री नरेश मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की बात है कोई शक नहीं है कि सरकार ने अच्छे प्रयास किये हैं और लगभग 5 हजार मैगावाट के नये प्लांट लगा रही है। यह वाकई सरकार का एक सराहनीय कदम है लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हाऊस को इस बारे में नहीं बताया गया कि जो हमने दूसरी संस्थाओं में हरियाणा का पैसा लगाया है उनके साथ समझौता किस आधार पर किया गया है। वे किस प्रकार से हरियाणा को पॉवर सप्लाई करेंगे? आज के दिन बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है। गांवों में दो-तीन घंटे ही बिजली मिलती है। आज जगह-जगह पर बिजली के कारण लोग जाम लगा रहे हैं। इसी प्रकार से मैं एक बात और कहना चाहूंगा जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश के अन्दर जमीन के फलोर रेट हरियाणा में सबसे ज्यादा हैं। मुझे मालूम नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कैसे कह दिया क्योंकि दिल्ली के अन्दर कांग्रेस की ही सरकार है वहां पर पहले 25 लाख रुपये प्रति एकड़ का रेट था लेकिन आज के दिन 75 लाख रुपये प्रति एकड़ हो गया है।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के रेट अभी आये हैं पहले दिल्ली का रेट 23 लाख रुपये प्रति एकड़ था। दिल्ली सरकार ने यह फैसला अभी एक महीना पहले ही किया है। हम अगर गुड़गांव और एन०सी०आर० की बात करें तो वह दिल्ली से भी ज्यादा है। दिल्ली के पास तो वैसे भी जमीन है ही नहीं चाहे वे एक करोड़ का रेट कर दें। जमीन तो हरियाणा के पास है।

श्री नरेश मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तो सरकार से यही निवेदन है कि एन०सी०आर० के अन्दर आपको अलग से रेट तय करने चाहिएं। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने तीन कैटेगरी बनाई हैं उसी प्रकार से एन०सी०आर० के लिए एक करोड़ या डेढ़ करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना चाहिए। उनके रेट बहुत ऊंचे पहुंच गए हैं और दिल्ली में ये रेट 75 लाख रुपये हैं। हरियाणा प्रदेश फाईनैंशियली भी स्ट्रोंग है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि एन०सी०आर० का रेट कम से कम 75 लाख रुपये तो होना ही चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में जरूर बात कहना चाहूंगा। रोहतक के अन्दर पी०जी०आई० मैडीकल कॉलेज है जहां

*चेयर के अनुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

पर पीले कार्ड वाले लोग तथा गरीब से गरीब आदमी इलाज के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर इन लोगों को दवाई के नाम पर एक गोली तक नहीं मिलती है, कोई टेबलैट नहीं मिलती है। अगर वहां के वार्डों की स्थिति देखें तो वहां पर आदमी कराहते रहते हैं लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। मेरे पिता जी का एक्सीडैंट हो गया था और उनको इलाज के लिए वहां पर ले जाया गया था। मैंने वहां पर खुद देखा है कि पी०जी०आई० मैडीकल कॉलेज, रोहतक की हालत आज के दिन बहुत ही खस्ता है। आज इस अस्पताल में दूसरे प्रदेशों के लोग भी इलाज के लिए आते हैं लेकिन इस अस्पताल की हालत बहुत ही खस्ता है इसलिए वहां पर कोई भी पेशैंट जा कर सैटिस्फाईड नहीं होता है क्योंकि वहां पर कोई भी दवा नहीं मिलती है, न कोई सुविधा और टेबलैट मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 100-100 गज के प्लॉट गरीब लोगों को देने की घोषणा की है। जिन गांवों की पंचायत के पास जमीन है वहां तो प्लॉट दे देंगे लेकिन जिन गांवों में पंचायतों के पास जमीन नहीं है वहां के गांवों के लोगों को प्लॉट कहां से देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि पिछली बार माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा था कि गांवों और शहरों में अगर गरीब लोगों को प्लॉट देने हैं तो उसके लिए सरकार को जमीन के लिए एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में भी थोड़ा सा स्पष्ट करें कि उन्होंने इसके लिए कितने पैसे का प्रावधान बजट में किया है। वैसे तो यह बजट आने के बाद ही पता लगेगा कि कितना पैसा इस काम के लिए बजट में रखा गया है। गरीबों को अगर प्लॉट दिये जाते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि पिछले 40 सालों में पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया। **(इस समय माननीय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा को बने करीब 40 वर्ष हुए हैं और पिछले 40 सालों के दौरान 30 साल तक तो कांग्रेस पार्टी की सरकारें ही रही हैं। यह अलग बात है कि इस दौरान मुख्यमंत्री चाहे चौधरी भजन लाल जी या दूसरे लोग रहे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी भी उन सरकारों में मंत्री रह चुके हैं इसलिए इसके लिए इनकी खुद की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी की बनती है। पीछे की बात सम्भालने की बजाए अब आगे के लिए सम्भाल लें तो यह अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से केवल एक ही निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अगर एन०सी०आर० के लिए कोई जमीन ऐक्वायर होती है तो उसका रेट 75 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए इसके लिए आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सुखबीर सिंह (रोहट) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया था वह बहुत ही सराहनीय था। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले तीन साल में जो काम किये हैं ऐसे काम पूरे हिन्दुस्तान में किसी अन्य मुख्यमंत्री और सरकार ने नहीं किये हैं। हरियाणा राज्य में बिजली पानी के कार्य भी हुए हैं, खेलों को भी बढ़ावा दिया गया है और दूसरे विकास कार्य भी किये गये हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज और हर क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने यह दिखाया है कि सरकार लोगों के लिए होती है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी हुड्डा और वित्त मन्त्री महोदय और सारी सरकार ने यह दिखाया है कि यह सरकार केवल अपने पेट के लिए कार्य

[श्री सुखबीर सिंह]

नहीं करती है बल्कि यह सरकार जनता ने बनाई है और इस सरकार ने जनता के लिए ही कार्य किया है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं अभी भी हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। जैसे कि मलिक भाई साहब ने मेरे से पहले बोलते हुए कहा है कि एन०सी०आर० के लिए 75 लाख रुपए प्रति एकड़ करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, दो साहूकार इकट्ठे हों और एक को हक दे दिया जाए और दूसरे का हक काटा जाए यह ठीक नहीं लगता है। अध्यक्ष महोदय, अब दिल्ली में ऐसा कर दिया गया है और हमारे यहां पर ऐसा नहीं किया गया है जबकि हमारी जमीन उनसे ज्यादा उपजाऊ है। अध्यक्ष महोदय, सरपंचों, पंचों और लम्बरदारों को पेसे दे दिए, गरीब बच्चों को वजीफे के पैसे दे दिए तो हमारे जो वृद्ध हैं उनकी पैंशन भी 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी जाए। यह जो इस पैंशन के साथ देवी लाल का नाम जोड़ा गया है इसको हटा देना चाहिए। आज वृद्ध आपकी तरफ देख रहा है और आशा लगाए बैठा है कि आप उनकी पैंशन भी बढ़ाएंगे। अध्यक्ष महोदय, वृद्ध एक, दो या ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक ही पैंशन ले लेगा, इससे सरकार को क्या फर्क पड़ेगा। पिछली सरकार तो वृद्धों के लिए कुछ नहीं करके गई है लेकिन आप से उनको बहुत उम्मीदें हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार ने काफी इम्पलाईज को नए स्केल दे दिए हैं, इसी विषय में मुझे ड्राईंग टीचर्ज भी मिले थे तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनके स्केलों के बारे में भी विचार करें और उनका स्केल बढ़ा दें। इसी तरह से लाल डोरे को बढ़ाने की भी बहुत डिमाण्ड है और मेरा आपसे निवेदन है कि लाल डोरे को भी बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, बहुत समय पहले लाल डोरे को बढ़ाया गया था। जहां पर इण्डस्ट्रियल विकास होता है वहां पर तो लाल डोरा बढ़ना चाहिए। इसी तरह से बी०पी०एल० कार्ड के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसको तो सोने का हाथी बना दिया है। मेरा इस बारे में कहना है कि जो भी इसके लिए अप्लाई करता है उसका कार्ड बना दो। इस कार्ड पर उसको थोड़े से सस्ते चावल ही मिलेंगे और क्या मिलेगा। इसी तरह से मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। इस सरकार द्वारा 1600 करोड़ रुपये माफ कर दिए गए और केन्द्र सरकार द्वारा 60 हजार करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ कर दिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो लाल डोरे के बाहर मकान बने हुए हैं और उन मकानों के ऊपर से जो बिजली की तारें जा रही हैं उनको भी हटाया जाना चाहिए। पिछली सरकार के समय में उन्होंने अपने बोरे भर लिए और साहूकार हो गये। मेरा कहना है कि जो किसानों से ट्यूबवैल के कनैक्शन के लिए सात हजार रुपये प्रति पोल लिए जाते हैं उनको भी माफ किया जाए क्योंकि इससे किसान के ऊपर बड़ा भारी बोझ पड़ता है। जब किसानों के सरकार ने 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिल के माफ कर दिए हैं तो इनको भी माफ करना चाहिए। आप किसान को इसके कारण क्यों मारने लग रहे हो। इसी तरह से इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है यह भी माफ होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बाकी तो सरकार नम्बर वन चल रही है क्योंकि इसने हरियाणा में बदमाश खत्म कर दिए और भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। कोई सोचता भी नहीं था कि हरियाणा में इस तरह से काम किए जाएंगे, हरियाणा में शांति बहाली होगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, लोगों की जेबें भरी जाएंगी और मुख्यमंत्री और मंत्री दिन-रात मेहनत करके लोगों के बारे में सोचेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि आगे भी सरकार ऐसी ही बनेगी। हम सरकार के पूरी तरह से साथ हैं। ओम प्रकाश चौटाला का भी आपने बढ़िया

काम कर दिया है। आप बुद्धिजीवी हैं, पी०एच०डी० ऐग्रीकल्चर हैं, विद्वान आदमी हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं इसलिए आपने उसको सही रास्ता दिखाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें उसकी ज्यादा शक्ल न दिखाया करो और इसको बाहर ही रखा करो। अगर वह आप जैसे बुद्धिजीवी से बात करें तो यह स्टेटस की बात नहीं है। एक राजा दूसरे राजा से ही बात करता हुआ अच्छा लगता है। अगर आप यहां पर स्पीकर नहीं होते तो ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री अर्जन सिंह (छछरौली) : स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए टाईम दिया। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि आज यह सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। हम सरकार की यूं ही तारीफ नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सच्चाई बता रहे हैं। आज कोई किसी की वैसे ही नहीं तारीफ करता है, आज हर कोई अपना नफा नुकसान समझता है। अध्यक्ष महोदय, अपोजीशन का काम केवल टीका टिप्पणी करना ही नहीं है बल्कि अगर कोई सही बात हो तो उसको उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो गैलरीज में इधर-उधर लोग बैठे हुए हैं इन सभी को भी पता है कि सच्चाई क्या है और सरकार किस तरह से चल रही है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज सरकार काम कर रही है मैं तो वहीं बता रहा हूं। लोग भी आज इस सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इस सरकार की नीयत अच्छी बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सरकार की नीयत और नीति दोनों बढ़िया हैं। इसके लिए हम आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं। यह अच्छी बात है कि सैंट्रल गवर्नमैंट ने किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने की बात कही है। मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि किसानों के कर्ज माफ करना तो अच्छी बात है, यह बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है लेकिन जो दूसरे गरीब लोग हैं जो किसान नहीं हैं और जिन पर कर्जा है उनके भी कर्ज माफ होने चाहिएं क्योंकि उन्होंने मजबूरी में ही कर्जा लिया है। उन्होंने ऐश करने की खातिर लोन नहीं लिया था। किसी ने मकान बनाने के लिए या किसी ने अपनी बीमारी के लिए लोन लिया था। मेरा कहना है कि चाहे वे किसी भी कॉस्ट से सम्बन्धित लोग हों लेकिन वे गरीब तो हैं इसलिए उनका भी कर्जा माफ होना चाहिए क्योंकि उन लोगों के पास उसको वापस करने के लिए आय का कोई सोर्स नहीं है। जब आपने किसानों का कर्जा माफ कर दिया तो जिनके पास आय का अपना कोई साधन नहीं है उन बेचारों का भी कर्जा माफ किया जाए क्योंकि वे कैसे अपना कर्जा उतारेंगे? सरकार को जरूर इनके बारे में सोचना चाहिए यही मेरी आपसे अपील है। सरकार ने पहले किसानों के बिजली के बिल माफ करके एक बहुत ही अच्छा काम किया था क्योंकि किसान यह बिल देने की स्थिति में नहीं थे। पिछली सरकार ने किसानों को गुमराह कर दिया था इसलिए किसानों ने वे बिल नहीं दिए थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अनुरोध है कि हमारे एरिया में पिछली सरकार के समय में अवैध खनन के कारण सात-आठ गांव ऐसे हैं जिनकी फसल बह गयी थी। उनके बिजली के बिलों को माफ करने के बारे में डी०सी० साहब ने भी, सरकार ने भी और कैप्टन साहब ने भी आश्वासन दिया था। सर, उन्होंने मजबूरी में ही यह बिल रोके थे क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो गयी थीं। पहली फसल तो उनकी फ्लड में खराब हो गयी थी, दूसरी फसल की उनकी बिजाई नहीं हुई थी और अगली फसल पर बहुत ज्यादा खर्च आ रहा था

[श्री अर्जन सिंह]

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनके बिजली के बिलों के बारे में भी सरकार सोचे। उसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगा कि उसमें भी थोड़ा सा गौर करें। थोड़े ज्यादा बिल इकट्ठे हो गए हैं इसलिए वे नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा जो बिजली की तारें लोगों के घरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं यह भी एक बहुत बड़ा अन्याय है जिन लोगों के घरों के ऊपर से तारें जा रही हैं उन तारों की वजह से वे अपने घरों में कपड़े नहीं सुखा पाते हैं और हमेशा हादसा होने का डर रहता है और करंट का डर रहता है। इसके अलावा एक मेरी रिक्वैस्ट यह भी है कि जो गैस्ट टीचर लगाने का काम सरकार ने किया है यह भी बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले तो इसमें यह जो नीति अपनाई कि जिस गांव में लगना था उसी गांव का टीचर लिया, वहां से नहीं मिला तो ब्लॉक से लिया, ब्लॉक से भी नहीं मिला तो जिले से लिया इस बात का भी बहुत अच्छा मैसेज जनता में गया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो टीचर अच्छा काम कर रहे हैं उनको ऐडजस्ट कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बारे में भी गौर होना चाहिए, यह मेरा निवेदन है जिन लोगों के घरों से गैस्ट टीचर लगे हैं उनके घरों में खुशहाली आई है और वे सरकार की तारीफ करने में लगे हुए हैं। वैसे सरकार की तारीफ कोई नहीं करता है यह तो आपका गुण है कि आप लोग अपनी तारीफ करवा रहे हो। किसान ही खुशहाली का माध्यम है। अगर किसान के घर में खुशहाली है तो मजदूर की भी तरक्की हो जाएगी। अगर किसान की जेब में पैसा है तो वह बाजार जाएगा और बाजार से सामान खरीदकर लाएगा इस प्रकार बाजार में भी रौनक आएगी। पिछली सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका था। लोग यह सोचने लगे थे कि क्या होगा, कैसे होगा? मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने हर घर में पीपल के पेड़ लगाये हैं जिनसे कि दिन-रात ऑक्सीजन मिल रही है। यह नहीं है कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं विपक्ष के साथियों की भी तारीफ कर सकता हूं। जो भी लोग अच्छा काम करते हैं मैं उनकी तारीफ करता हूं। चौटाला जी ने साढ़े पांच साल तक सरकार चलाई, साढ़े पांच साल उनको जनता की सेवा करने का मौका मिला लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और वे आज सच्चाई भी नहीं सुन सकते हैं। आप लोग काम कर रहे हैं तो अच्छा है नहीं करेंगे तो जनता आपको भी रिजल्ट दे देगी। पिछली सरकार पॉपुलर, जीरी, गन्ने और गेहूं के दाम सब अपने घर ले गई और इस सरकार ने रेट बढ़ाकर जनता को दिए हैं, किसान को दिए हैं। जनता को आप पर भरोसा है इसलिए ही आपको चुनकर भेज रखा है। मैं तो यह अपील करूंगा कि जिस नीयत से आप काम कर रहे हैं वह उसी नीयत से करते रहें। सारी दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं होती लेकिन जिस नीयत से आप लोग काम कर रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम लोगों को भी जनता ने चुनकर भेज रखा है। (विघ्न) वैसे मैं ब०स०पा० से हूं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी पार्टी इंसानियत है। मैं कभी भी पार्टी को नहीं मानता। मैं तो जो इंसान सच्चा है, अच्छा है उसकी कद्र करता हूं। अगर कोई गलत काम करता है और वह किसी भी पार्टी में हो तो हम गलत का विरोध करेंगे। जो वार्निंग दी जा रही हैं उनकी हमें कोई परवाह नहीं है। मरना तो सभी को जरूर है यहां पर तो कोई नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष : कौन मार रहे हैं।

श्री अर्जन सिंह : मैं तो विपक्ष के भाइयों से कहता हूं कि अगर वे सच्चाई नहीं कह

पाते तो सुन तो सकते हैं। हम तो अन्याय का विरोध करेंगे और न्याय के पक्ष में बोलेंगे। अन्याय को सहना भी गलत है, उन्होंने तो टीका-टिप्पणी करना ही आता है। वे तो पहले से ही सोचकर आते हैं कि हमें भागना ही है। अगर वे हमारे पक्ष की बात नहीं कर सकते तो टीका-टिप्पणी करने का मतलब यह है कि वे प्रदेश की खुशहाली देखकर खुश नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप वाईंड-अप करें।

श्री अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब चौटाला जी की सरकार थी तो वे किसानों के हितैषी बनने की बात करते थे लेकिन उनकी सच्चाई का लोगों को पता है। पिछली सरकार के समय में लोगों का उन पर से विश्वास खत्म हो गया था क्योंकि सुबह ही सारे परिवार के लोग लोगों के ट्रैक्टर, मोटर साईकल में तेल मापना शुरू कर देते थे लेकिन सभी का रिजर्व लगा होता था क्योंकि जब लोगों के पास पैसे होंगे तभी तेल डलवायेंगे। उनके समय में पापुलर का भाव 150-200 रुपए प्रति क्विंटल होता था और एक ट्राली 12 हजार रुपए में जाती थी। लोग मजबूर हो गये थे कि जायें तो कहा जायें क्योंकि किराया, आढ़ती और ट्रैक्टर का निकाल कर सिर्फ खूंटे ही किसान के पास बचते थे लेकिन इस सरकार के समय में एक ट्राली 70-80 हजार रुपए में जा रही है और सभी लोग खुशहाल हो गये हैं। पिछली सरकार के समय में 50 हजार रुपये प्रति ट्राली का किसानों को नुकसान हो रहा था। लेकिन आज चारों तरफ खुशहाली छाई है लोगों के घरों में चिनाई लगी हुई है, लोग मोटर साईकिल और कार खरीद रहे हैं और विवाहों में भी कार दे रहे हैं। पिछली सरकार के समय में एक कीले का रेट 2.50 लाख रुपये होता था लेकिन आज एक कीले का जमींदार भी खुशहाल है क्योंकि उसके एक कीले की कीमत 20-35 लाख रुपये बिना खेत में जाये बिना खेत में काम किए वह मालिक बना बैठा है। मैं क्या-क्या गिनाऊं। हमारे बाहर जाने से पहले लोगों को सच्चाई का पता लग जाता है क्योंकि हमारे पत्रकार भाइयों को सब पता है इनके माध्यम से जनता को सच्चाई का पता चल जाता है इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 12th March, 2008.

*13.30 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Thursday, the 12th March, 2008).

44390—HVS—H.G.P., Chd.